हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 मार्च, 1987

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 3 मार्च , 1987

पृश्ठ संख्या

ताराकित प्र न एवम उत्तर	(5)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र ान एवं उत्तर	(5)24
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	
उचाना कलां निर्वाचन क्षेत्र के कतिप गांवों में ओलावृश्टि से नश्ट हुई फसलों सम्बन्धी	(5)25
वक्तव्य –	
राजस्व राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(5)26
वर्श 1987–88 के बजट पर सामान्य चर्चा	(5)30

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 3 मार्च , 1987

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्र ान एवम उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब क्वैश्चन होंगे। कल मैंने जो स्टार्ड क्वैश्चन नं. 1253* आज के लिए डैफर किया था, वह सबसे पहले टेक अप किया जाएगा और उसके बाद आज की क्वैश्चन लिस्ट टेक अप की जायेगी।

Progress on S.V.L. Canal in Punjab territory

***1253. Sh. Bhalle Ram @ Sh. Nihal Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any decision has been taken by the Government to take a team of Sarpanches/Panches of the State for an on-the-spot study of the works in progress on the SYL Canal in the Punjab territory; if so, the time by which the said decision is likely to be implemented?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Yes Sir, in April-May, 1987.

श्री भले रामः स्पीकर साहब, हरियाणा में 6 हजार के लगभग पंचायतें होंगी। मैं मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि क्या

ये सारी पंचायतों के मैम्बर्ज को ले जाएंगे या सिर्फ सरपंचिज को ही ले जाएंगे? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रास्ते में उनके ठहरने, खाने–पीने और सिक्योरिटी आदि का क्या इन्तजाम होगा?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, इसमें केवल सरपंचिज को ले जाने की बात नहीं है। हमारी तो सारे पंचिज को ले जाने की योजना है। उनकी ट्रांसपोर्ट, खाना खाने और ठहरने आदि का सारा इन्तजाम सरकारी तौर पर किया जाएगा।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि सरपंचिज और पंचिज के साथ–साथ हाउस के सारे मैम्बर्ज को भी ये ले जाएंगे और यह तकरीबन कब तक पौसीबल होगा?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैम्बर्ज का दर्जा पंचिज और सरपंचिज से काफी ऊंचा है। वे तो किसी वक्त भी जा सकते हैं और उसके लिए सरकार से ये जो सहूलियत चाहें, वह हमेशा हाजिर हैं। (विघ्न) सब एम.एल.एज. जा सकते हैं, चाहे सरदार लछमन सिंह जी जाना चाहें या कोई और जाना चाहें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक समय की बात हैं, मैंने अभी अर्ज किया कि सरपंचिज और पंचिज को अप्रैल–मई, 1987 में ले जाने का प्रोग्राम हे। सर्दी की वजह से अभी तक प्रोग्राम नहीं बन पाया। जैसे ही मौसम ठीक होगा पंचिज और सरपंचिज को हम ले जाएंगे।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, बार–बार सरकार की और से यहां यह जवाब आता रहा है कि अब एस.वाई.एल. कैनाल दिसम्बर, 1987 तक बन कर तैयार हो जाएगी लेकिन पिछले दिनों पार्लियामैंट में जवाब आया था कि यह अप्रैल, 1988 तक तैयार होगी। क्या मंत्री जी इसके बारे में रोशनी डालेंगे?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: सर, इस कैनाल का जो कम्पलीशन शिडयूल है, वह दिसम्बर 1987 ही है। इस बात को बार–बार पंजाब भी कह चुका है और हरियाणा भी कह चुका है। लेकिन यह बात ठीक है कि पिछले दिनों पार्लियामैंट में यूनियन इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने यह बात कही कि–

"The construction work on the S.Y.L. Canal is likely to be completed by March, 1988."

और नैशनल प्रैस में यह रिकार्ड हुई। कुदरती बात है कि माननीय सदस्य और पूरे हरियाणा के लोग इससे निन्तित हुए होंगे परन्तु इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना रखी है। उसकी मीटिग इरीगेशन सैक्रेटरी ने 12.12.1986 को बुलाई थी जिसमें पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के चीफ सैक्रेट्ररीज, इरीगेशन सैक्रेट्ररीज, इंजीनियर्ज–इन–चीफ और चीफ इंजीनियर्ज वगैरा ने भाग लिया था। उसमें जब पोजीशन रिव्यू हुई तो पंजाब के चीफ इंजीनियर ने, एस.वाई.एल. कैनाल की कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज हैं, कहा था कि सिरसा ऐक्वीडक्ट एक ऐसी आईटम है जो मार्च, 1988 में कम्पलीट

होगी ओर बाकी सारे काम दिसम्बर, 1987 तक कम्पलीट हो जाएंगे। इस बात पर हमारे चीफ सैक्रेटरी, कमिश्नर एंड सैक्रेटरी और चीफ इंजीनियर आदि ने एतराज किया और यह बात कही कि यह काम किसी तरह भी दिसम्बर, 1987 से आगे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तीन शिफ्टों में करके यह दिसम्बर, 1987 तक पूरा हो सकता है। उस मीटिंग में पंजाब के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि यह काम तीन शिफ्टों में नही हो सकता लेकिन उसके बाद 18 फरवरी, 1987 को, लगभग दो महीने बाद, जारे पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बरनाला जी की चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाम आई उसमें यह बात लिखी हुई है कि सिरसा ऐक्वीडक्ट का काम तीन शिफ्टों में शुरू कर दिया है। इसमें उन्होंने यह नहीं लिखा कि किसी भी आईटम का काम मार्च, 1988 तक चलेगा बल्कि सारी आईटम्ज की डेट औफ कम्पलीशन दिसम्बर, 1987 की कही है। मेरा ख्याल है कि यूनियन इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने पार्लियामैंट में जो स्टेटमैंट दी है उसकी इंफर्मेशन पंजाब ने सप्लाई की होगी क्योंकि पंजाब इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज है। हमारे से ऐसा कोई इन्फर्मेशन नहीं मांगी गई। उन्होंने शायद 12.12.1986 की मीटिंग के बेसिज पर यह इन्फर्मेशन दे दी लेकिन बरनाला साहब की तरफ से जो लेटैस्ट चिट्ठी आई है उसमें लिखा है कि सिरसा ऐक्वीडक्ट का काम तीन शिफ्टों में शुरू कर दिया गया है। तो, सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 1987 तक ही यह कैनाल कम्पलीट होगी और पंजाब गवर्नमैंट ने अब जो इन्फर्मेशन सप्लाई की है

उसके अनुसार इसके मार्च, 1988 तक कम्पलीट होने का कोई सवाल नहीं है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा ने अब तक जो पैसा एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए दिया है क्या उसे भारत सरकार ने उल्टा देना शुरू कर दिया है या नहीं? अगर देना शुरू नहीं किया है तो उसका क्या कारण है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हरियाणा ने जो रूपया अब तक खर्च किया है और जो आगे खर्च करना है वह सारा, जेसा प्रधान मंत्री जी ने पलवल में अनांउस किया था, भारत सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है। हम महीने का जो खर्च है वह न हमने दिया है और न ही पंजाब ने दिया है यह मान कर कि इसे अब भारत सरकार करेगी। पीछे का जो रूपया है उसके लिए हमारी उनसे बातचीत हो रही है और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार भारत सरकार उसे रीइमबर्स करेगी।

श्री अध्यक्ष: अब आज की क्वैश्चन्ज लिस्ट अेक अप की जाएगी।

Abolition of Road Tax on Two-Wheelers.

***1232. Seth Ram Dass Dhamija**: Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish

Road Tax on the Two wheelers in the State; if so, the time by which a decision in the matter is likely to be taken?

Transport Minister (Sh. Amar Singh): No, Sir.

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, यह तो बड़ा आसान सा जवाब है। वैसे भी कहा जाता है कि 'एक 'न' और सौ सुख''। खैर, स्पीकर साहब, पंजाब गवर्नमैंट ने 23 जनवरी 1986 को एक आर्डिनैंस जारी किया है जिसके मुताबकि जिन वहिकल्ज का अनलेडन वहेट 90 किलो से कम है और लाईसैंस की मियाद 3 साल है उनसे लम्प–सम रोड़ टैक्स 120 रूपया लिया जाएगा और जिनके लाईसैंस की मियाद 3 से 6 साल तक की है उनसे 90 रूप्या लिया जाएगा। 6 से 9 साल तक की मियाद वाले लाईसैंस होल्डर्ज से 60 रूपये और 9 साल से अधिक मियाद वाले लाईसैंस होल्डर्ज से 30 रूपये लिए जाएंगे। जब दूसरे मामलों में हरियाणा नम्बर एक पर होने जा रहा है तो इस मामले में नम्बर 2 या 3 पर क्यों रहे? अगर इस तरह की बात पंजाब में हो सकती है तो यहां भी हो सकती है। अब तो स्कूटर साईकिल के बराबर हो गया है। तो स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि ये कम से कम यह तो कह दं कि इस बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप धमीजा साहब का दिल न तोड़ा करें। (हंसी)

श्री अमीर चन्द: स्पीकर साहब, इसमें धमीजा साहब का दिल तोड़ने की बात नहीं हैं। मैं तो हाउस को आंकड़े बताना

चाहता हूं कि हरियाणा, पंजाब और यू.टी. चण्डीगढ़ में किस हिसाब से सालाना रोड़ टैक्स पे किया जाता है। आंकड़े इस प्रकार हैं:–

			Haryana	Punjab	U.T. Chandigarh
			Rs.	Rs.	Rs.
1	(a)	Bi-cycle not exceeding 200 Ibs. in weight unladen.	31.25	31.25	31.00
	(b)	Bi-cycle exceeding 200 Ibs. in unladen weight.	62.50	62.50	62.00
	(c)	Bi-cycle as in (a) or (b) when used for drawing a trailor or side car in addition to the tax payable therefor.	15.65	15.65	16.00
	(d)	Tricyces.	62.50	62.50	62.00
2		Vehicles not exceeding 5 OWT in weight unladen adopted and used solely by or for a person suffering	6.25	7.00	7.00

		from any infirmity.			

स्पीकर सर, जहां तक पंजाब सरकार द्वारा आर्डिनैंस जारी करने का सवाल है, उसके बारे मे मुझे जानकारी नहीं है लेकिन टू व्हीलर्ज के रोड टैक्स की लेटैस्ट इन्फर्मेशन जो मेरे पास थी, वह मैंने बता दी है।

सेठ राम दास धमीजा: मेरे पास आर्डिनैन्स की कापी है। अगर मिनिस्टर महोदय चाहते हैं तो वह भी दे देता हूं। दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि पांच साल का टैक्स एक ही बार ले लिया जाये ताकि लोगों को हर साल तकलीफ न हो।

श्री अमर सिंह: पिछले दिनों रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटी की मीटिंग जयपुर में हुई थी उसमें भी रोड टैक्स के बारे में जिक्र हुआ था और उस मींटिग में इस सम्बन्ध में जो फैसला हुआ था वह इस प्रकार है –

"It was recommended that Rajasthan pattern for charging road tax at the initial stage of registration of vehicles for a period of 10 years may be considered by the participating States."

The Rajasthan system is under examination of the Government.

चौ. धर्मबीर गाबा: स्पीकर साहब, मैं तो यह चाहता था कि रजिस्ट्रेशन के टाईम पर ही यदि दस साल का टैक्स इक्ट्ठा ले लिया जाये तो ऐसा करने से टैक्स की चोरी नहीं हो सकेगी।

Mr. Speaker: They are considering it. Next question.

Construction of bus stands at Barwala and Uklana Mandi

***1246. Ch. Inder Singh Nain**: Will the Minister for Transport be pleased to refer to reply to Started Question No. 1120, answered on the floor of the House on the 27th February, 1986 and state–

(a) whether the construction of bus-stands at Barwala and Uklana Mandi in district Hissar have started; and

(b) if so, the time by which the construction of the said bus-stands is likely to be completed together with the estimated cost thereof?

Transport Minister (Sh. Amar Singh):

(a) Construction work of bus stand at Uklana Mandi has been started. The bus stand at Barwala has also been sanctioned and work will be started shortly.

(b) The estimated cost of the Uklana Mandi bus stand is Rs. 1060526.20 and that of Barwala bus stand Rs. 1192700. These are likely to be completed in the next financial year.

चौ. इन्द्र सिंह नैनः स्पीकर साहब, उकलाना मंडी बस स्टैन्ड के बारे में जो जवाब दिया गया है उससे मैं फुल्ली सन्तुश्ट हूं। मंत्री महोदय ने दो फरवरी को पत्थर रखा था, वहां पर काम शुरू हो गया है लेकिन बरवाला के बारे में मैं सन्तुश्ट नहीं हूं। बरवाला बस स्टैन्ड की नींव 27.10.1984 को रखी गई थी। आज उस नींव को रखे हुए 856 दिन हो गये हैं। जब उस बस स्टैन्ड की मंजूरी हो गई थी तभी तक पत्थर रखा गया होगा। दूसरे शब्द उन्होंने प्रयोग किये हैं कि उसका निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा। मैं मिनिस्टर महोदय से कैटेगरीकली अश्योरैन्स चाहूंगा कि अगर वे डेट नहीं बता सकते तो कम से कम महीना बना दें कि कौन से महीने से काम शुरू करेंगें?

श्री अमीर सिंहः स्पीकर साहब 27.10.1984 को ऐक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बस स्टैन्ड का पत्थर रखा था। आनरेबल मैम्बर ने यह पत्थर रखवाया होगा। मैं आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस पर काम शुरू कर दिया है और अगले वित्तीय वर्श में पूर्ण होने की सम्भावना है। इस पर 11 लाख 92 हजार रूपये के करीब खर्च होगा।

ठाकुर बहादुर सिंहः स्पीकर साहब, परिवहन मंत्री जी ने फाउनडेशन स्टोग रखने की बात की है। क्या वे बताएंगे कि बस स्टैन्ड बनाने का कोई माप दण्ड रखा हुआ है कि जो उन कन्डीशंज को पूरी करेगा वहां बस स्टैण्ड बना दिया जायेगा? क्या सिरसा जिले का भी कोई बस स्टैन्ड इन कन्डीशन्ज को पूरा

करता है और अगर पूरा करता है तो क्या वांह भी बस स्टैन्ड बनाने की योजना है?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जब हरियाणा बना उस समय अम्बाला और गुड़गांव के ही बस–स्टैन्ड बने हुए थे और कोई बस–स्टैन्ड उन समय नहीं बना हुआ था। इस वक्त अम्बाला जिले में तीन, करनाल में तीन, कुरूक्षेत्र में आठ, सोनीपत में दो, जीन्द में दो, हिसार में सात, भिवानी में चार, फरीदाबाद में एक, महेन्द्रगढ़ में तीन और रोहतक में दे बस–स्टैन्डज बन चुके हैं। कुल 35 बस स्टैन्डज तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा डबवाली, बावल, सिरसा, बल्लभगढ़ झज्जर, नारायणगढ़, धारूहेड़ा, एन.आई. टी. फरीदाबाद, फिरोजपुर झिरका, नूंह, पीपली, पंचकूला, सोहना, कोसली, अम्बाला कैन्ट और मेहम आदि के 16 बस स्टैन्ड अन्डर कन्सट्रक्शन हैं। Most of these bus stands are likely to be completed during the next financial year. Then to provide more facilities to the travelling public, the department has decided to construct way-side bus stands on G.T. Road. आपने दिल्ली से चण्डीगढ़ आते हुए देखा होगा कई जगह वे–साइड बस स्टैन्डज बनाये हुए हैं। नीलोखेड़ी, तरावड़ी, घरौंडा सम्भालखा और मुरथल में ये सन् 1985–86 में बनाये हैं। इसके अलावा सन् 1984–85 में 140 और सन् 1985–86 में 140 बस–क्यू–शैलटर्ज बनाये हैं करन्ट फाइनैन्शल ईयर में दस बस–क्यू–शैल्टर्ज पर–डिपो बनेगें जो कि मंजूर हो चुके हैं। इन पर 22 लाख 37 हजार रूपये खर्च कर रहे हैं। इनकी कुल तादाद 130 है। जहां

तक सिरसा जिले की बात हैं, उसमें आनरेबल मैम्बर यदि कहीं बतायेंगें तो वहां पर बस–क्यू–शैल्टर या बस स्टैन्ड बनाने के बारे में विचार करैंगे।

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नारायणगढ़ में जो बस स्टैन्ड का पत्थर रखा हुआ है, उसको हुए कितने साल हो गये हैं और यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा?

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नारायणगढ़ में जो बस स्टैन्ड का पत्थर रखा हुआ है, उसको रखे हुए कितने साल हो गये हैं और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा?

श्री अमर सिंह: इस बारे में मुझे पता नहीं। आनरेबल मैम्बर ने अपने आप ही पत्थर रखा होगा। पहले ये मिनिस्टर थे इसलिए इन्होंने साईट देख कर रखा होगा। जहां पर पत्थर रखा हुआ है, उसकी साइट बतायेंगे तो इस बारे में छानबीन करायेंगे।

चौ. लाल सिंह: ट्रांसपोर्ट का महकमा मेरे पास कभी नहीं आया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने पत्थर रखा था। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसका पत्थर रखे हुए कितने साल हो गये हैं और इसे कब बनायेंगे?

श्री अध्यक्ष: आपका सप्लीमैंटरी इस क्वैश्चन से रिलेट नहीं करता।

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बताया है कि अम्बाला और गुड़गांव के बस स्टैन्ड हरियाणा बनने से पहले के बने हुए हैं। अम्बाला कैन्ट का बस स्टैन्ड बहुत पहले का बना हुआ है। वहां नया बस स्टैन्ड बनाने के बारे में हाउस में कहा गया था कि यह 31 मार्च, 1987 तक बन जायेगा लेकिन अभी तो वहां मिट्टी पड़ रही है। मिट्टी पड़ते हुए एक साल हो गया है। क्या मंत्री जी कोई तारीख बतायेंगे कि यह बस स्टैन्ड कब तक बन जायेगा? जब ऐग्जिस्टिंग बस स्टैन्ड बना था उस समय अम्बाला कैंट की 25 हजार की आबादी थी लेकिन अब वहां की आबादी डेढ़ लाख हो गई है लेकिन वह बस स्टैन्ड वैसा का वैसा ही है।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, पहले तो आनरेबल मैम्बर साईट की सिलैक्शन नहीं करवा पाये। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट तो काफी पहले इसको बनाना चाहता था लेकिन साईट का झगड़ा था। अब साईट सिलैक्ट हुई तो उसे फिल–अप करने की कोशिश की जा रही है। साईट फिल–अप करने के बाद काम शुरू करवाया जायेगा।

चौ. अजमत खां: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने उन बस स्टैडज के नाम बताये हैं। जहां पर ये बन रहे हैं लेकिन जहां पर नहीं बन रहे हैं और साईट का भी सिलैक्शन हो चुका है, जैसे हथीन में साईट का सिलैक्शन हो चुका है, क्या वहां पर भी काम चालू करेंगें?

श्री अमर सिंहः जहां पर भी साईट का सिलैक्शन हो गया है, वहां पर विद इन दी फाइनेन्शल ईयर काम शुरू कराया जायेगा। अगले साल में उसे कम्पलीट करवा देंगे।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, जहां पर भी नये बस स्टैड बनते हैं, वहां पर यूरिनल प्रोवाइड किया जाता है लेकिन साथ–साथ यह भी बात है कि एक दफा बनने के बाद उसकी बहुत बुरी कन्डीशन हो जाती है। वहां पर प्रौपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। जैसे प्रौपरली पानी छोड़ना चाहिए वह नहीं छोड़ा जाता हैं। जो नये बस स्टैन्ड सरकार बनाने जा रही है उनके टायलेट में 24 घन्टे पानी चलना चाहिए ताकि उनकी कन्डीशन हाईजिनक रह सके।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, हम बहुत ही माडर्न बस स्टैन्ड बनाने जा रहे हैं। सभी के एक ही नक्शे हैं। थ्री बेज, सीक्स बेज और एट बेज के जितने भी बस स्टैन्ड बनने जा रहे हैं, सभी एक ही नमूने के हैं। ये सभी एक से नजर आयेंगे। जहां पानी की प्रोब्लम है, वह बिजली की वजह से है। बिजली की जब प्रोब्लम हो जाती है तो साथ ही पानी की भी प्रोब्लम हो जाती है, वरना इस बारे में सरकार पूरा ध्यान दे रही है कि सीविक ऐमेनिटिज प्रोवाईड की जायें।

श्री अध्यक्ष: उनका कहने का मतलब यह है कि कभी–कभी आप बस–स्टैन्डज को चैक भी कर लिया करें क्योंकि लैटरीन्ज से काफी बदबू आती है।

श्री अमर सिंह: अच्छा जी।

Construction of new bridge on drain No. 8 at Gohana

***1258. Sh. Bhalle Ram**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bridge on drain No. 8, at reach RD-Zeor, near subzi mandi Gohana; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the above-said bridge on priority basis?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, यह जो सब्जी मंडी है, यह बिल्कुल ड्रेन न. 8 के किसारे पर है और इसके साथ ही एक पुराना पुल बना हुआ है जो पानीपत रोड को कनैक्ट करता है। यह बहुत जरूरी हे। अगर यह उस पुल को दोबारा से नहीं

बनवायेंगे तो लोगों को घूम कर आना पड़ेगा। क्या मंत्री जी उस पुल को रिलैक्सेशन देकर बनाने की कृपा करेंगे क्योंकि अब जो पुल वहां पर बना हुआ है, वह बहुत पहले का बना हुआ है, टूटने के करीब है और काफी ज्यादा सवारियां यहां से गुजरती हैं?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, यह ड्रेन न. 8 जो है, अगर पानीपत से रोहतक जायें तो गोहाना शहर से मशरह की तरफ से गुजरती है। इसके ऊपर पुल बना हुआ है जो सोनीपत से और पानीपत से आने वाली सड़क को मिलाता है। ये उस पूल से 1670 फुट ऊपर एक और पुल चाहते हैं। वह विलेज रोड ब्रिज किसी पुराने वक्त का वहां पर बना हुआ है और उसको कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। गोहाना शहर के और दूसरे इलाके के कुछ लोग उस पुल को इधर से उधर जाने के लिये इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना यह है कि इस छोटे से रोड ब्रिज को भी बना दिया जायें। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे सिर्फ 1670 फुट नीचे तो बड़ा ब्रिज है। जो भी बड़ा व्हीकल है, टाउन का या कहीं और का, वह वहां से गुजर सकता है। पहली बात तो यह है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और दूसरी यह कि इसके दोनों तरफ चूंकि लोगों ने मकान भी बना लिये हैं इसलिए यदि म्यूनिसिपल कमेटी जरूरी समझे तो वहां पुल बना सकती हैं। न तो ड्रेनेज डिपार्टमैंट वहां पर ब्रिज बनाने की जरूरत महसूस करता हैं और न ही बनाने की कोई तजवीज है।

Village connected with link roads in the State

***1266. Ch. Roshan Lal Arya**: Will the Minister for Public Works (B & R) be pleased to state –

(a) the details of such villages in the State as have not been connected with link roads upto 1.2.87.

(b) whether there are any villages in the State which have been connected with double link roads; and

(c) if so, the number of such villages as on 1.2.87?

Public Works Minister (Ch. Phool Chand): The time and labour involved in collecting the required information will not be commensurate with any possible benefits to be obtained from it.

Mr. Speaker: Mr. P.W.D. Minister, this is no reply. कल भी इसी तरह का जवाब हाउस में दिया गया था। मैम्बर ऐसे रिप्लाई से बहुत टची हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें इन्फर्मेशन दी जाये। यह पता लगाना कौन सा डिफीकल्ट है कि कोई गांव रोड से कनैक्टिड है या नहीं।

श्री फूल चन्द: यह अगर किसी स्पैसिफिक विलेज के बारे में पूछें तो बता सकता हूं।

Extension of Bye-Pass in Jind

***1270. Sh. Brij Mohan Singla**: Will the Minister of Public Works (B & R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to further extend the Bye-Pass in Jind City towards Hansi road and Kaithal road; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise?

Public Work Minister (Sh. Phool Chand):

(a) Yes, Sir.

(b) No definite time-limit can be indicated as taking up the work will depend upon availabity of funds.

श्री बृज मोहन सिंगला: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि क्योंकि फंडज की भाौर्टेज है, इसलिये कोई डैफिनिट टाईम नहीं बता सकते कि कब तक इसको बना देंगे। स्पीकर साहब, दूसरी जगहों पर भी सड़कें बन रही हैं। जीन्द में खासतौर पर शूगर मिल लगाने के बाद वहां पर काफी हैवी ट्रैफिक रहता है। वहां पर ऐक्सिडैंटस होने का अन्देशा बना रहता है। जो मौजूदा सड़क है, वह बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। गन्ने के ट्रक सारा दिन चलते रहते हैं। ऐसे कामों को प्रायरिटी पर शुरू करना चाहिये। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि जो भी फंडज अवेलेबल हैं, क्या उनसे इस बाई–पास को प्रायरिटी देकर बनाया जायेगा?

श्री फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने अपने सवाल में दो बाई–पासिल का जिक्र किया है। एक जींद में भिवानी

रोड से जींद हांसी रोड पर और दूसरा जींद गोहाना रोड से जींद कैथल रोड पर बनता है। पहले की लम्बाई 8.00 किलोमीटर है और दूसरे बाई–पास की लम्बाई 6.001 किलोमीटर है। एक की कौस्ट इनीशियली जब हमने असैस की थी तो 29 लाख 97 हजार के करीब की थी। लेकिन इसके बनाने में दिक्कत यह है कि इसके बीच में रिजर्व फौरेस्ट आता है रिजर्व फौरेस्ट बीच में आने की वजह से गवर्नमैंट ऑफ इंडिया पर परमिशन लिये बगैर सड़क नहीं बना सकते। हम उसकी एलउइनमैंट चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह से दूसरे बाई–पास के पोर्शन की कौस्ट इनीशियली 2969689 रूपये थी, इसका अभी रिवाईज्ड ऐस्टिमैटस बनाया है। मैं आनरेबल मैम्बर को यह आश्वासन दिलाता हूं कि यह सारा मामला अंडर कंसिड्रेशन है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी यह बात हाउस में कही थी। किसी भी शहर में जब कहीं पर बाई–पास बनता है तो उसमें लिमिटेशन होती है। आर्डिनेरिली तो शिडयूल्ड रोडज के 100 मीटर सामने तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। बाई–पास के लिये शादय 200 फुट तक का हिसाब–किताब है। लेकिन ज्यों ही बाई–पास बनने के बाद ये रोड्स म्यूनिसिपल लिमिटस में आ जाती हैं तो उस रोड के बिल्कुल किनारों पर ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। क्या मंत्री जी इस बात को ऐनश्योर करेंगे कि जब सड़कें म्यूनिसिपल लिमिटस के अन्दर भी आ जाये तो भी उन पर यह पाबन्दी रहेगी?

श्री फूल चन्द: सर, पी.डब्ल्यू.डी. रोड्ज के मामले में ऐसी कोई कंडीशन वेव नहीं की जाती। अगर यह म्यूनिसिपल रोड है तो वह म्यूनिसिपलिटी का काम है। खासतौर पर बड़े शहरों में ट्रैफिक को कन्ट्रोल करने के लिये हमने सड़कों को चौड़ा करने का प्रोग्राम बनाया है। जैसे पानीपत है, शाहबाद है, पिपली है या जहां–जहां से भी जी.टी. रोड पास करती है, वहां हमने रोडज को सिक्ल–लेन करने का प्रोग्राम बनाया है। कई जगह पर हम बना रहे हैं और कई जगह पर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, आज से 10–12 साल पहले रोहतक का बाई–पास बनाया गया था। आपसे भी वहां पर देखा होगा कि उस बाई–पास के किनारे पर कंस्ट्रकशन बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। मैं यह बात हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल लिमिट से लेकर मय्यड गांव गांव तक तो मैंने खुद कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी देखी है। यह बात इसी हाउस में कही गयी थी कि यह अन–अथोराईज्य कंस्ट्रक्शन है। क्या मंत्री जी इस तरह की कंस्ट्रक्शन को न होने देने की बात ऐनश्योर करेंगे?

श्री फूल चन्द: स्पीकर साहब, जहां तक पी.डब्ल्यू.डी. रोडज के ऊपर ऐन्क्रोचमैंट की बात आयी, वह तो हमने दूर कर दी है। कुछ कंस्ट्रक्शन अगर म्यूनिसिपल लिमिटस में रोडज के साथ–साथ है, तो हम इसकी जांच करवा लेंगे और ऐसी किसी भी कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं देंगे।

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, शहरों में ट्रैफिक का ज्यादा रश है। शहरों में पहुंचने के लिये सिंगल रोडज हैं। इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। आपको भी पता है कि पीपली से कुरूक्षेत्र जाने के लिये सड़क पर कितना ट्रैफिक होता है। वहां पर लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है और ऐक्सीडैंट होने का भी खतरा रहता है। कया पीपली से लेकर कुरूक्षेत्र तक, जहां पर फ्लाई–ओवर बनाया जा रहा है, वहां तक सड़क को फोर लेने बनाने की तजवीज है? मुझे यह बताया गया है कि उसका ऐस्टिमेट गवर्नमैंट के पास आया हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाये।

श्री फूल चन्द: यह अन्डर कंसिड्रेशन है।

श्री बृज मोहन सिंगला: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि फंडज की शौर्टेज की वजह से कुछ दिक्कत है और कुछ जंगलात की वजह से जमीन ऐक्वायर करने की दिक्कत है। इसमें कुछ टाईम लगेगा। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि भिवानी रोड से रोहतक रोड और हांसी रोड से शहर के बीच में जाने के लिये जो मेन रोड है, वह पी.डल्ब्यू.डी. रोड है और इसको जल्दी चौड़ा करवाया जाएगा ताकि ट्रैफिक के लिये वहां पर आसानी हो सके?

श्री फूल चन्द: जैसे मैंने अर्ज किया और आनरेबल मैम्बर को पता भी है कि रूपये की दिक्कत है जब फौरैस्ट वाली

दिक्कत दूर होगी और रूपये की दिक्कत हल होगी हम इम्मीजीयेटली इन्हें बनवा देंगे। इन्होंने यह भी कहा कि शहर में जाने के लिये कुछ दिक्कत है। अगर वह पी.डब्ल्यू.डी. रोड है, तो हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और जो कुछ हो सका, वह करने की कोशिश करेंगे।

श्री नेकी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से एक बात जानना चाहूंगा। उकसाना नरवाना रोड पर माल–गोदाम या वेयर हाउस बना हुआ है। ट्रकों की वजह से सारी सड़क रूकी रहती है। आने–जाने वालों के लिये कोई रास्ता नहीं रहता। जींद शूगर मिल में गन्ना आने की वजह से भी वहां पर काफी रश रहता है। मैं सुझाव दूगा कि जींद–नरवाना रोड को डबल कर दिया जाये। तकरीबन 5 किलोमीटर तक का टुकड़ा हैं। इसी तरह से उकलाना–नरवाना को भी डबल कर दिया जाये ताकि लोगों को आने–जाने में कोई दिक्कत न हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे इस सुझाव को सरकार मान लेगी? अगर मान लेगी तो इस पर कब तक का शुरू कर देगी?

श्री फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनकी यह बात है कि ट्रकों की वजह के सारी सड़क रूकी रहती है, वह तो हमारे कन्ट्रोल में नहीं है। जहां तक इन्होंने सड़कों को चौड़ा करने के बारे में सुझाव दिया है, उसको हम चैक करवा लेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो उस पर विचार कर लेंगे।

10.00 बजे

श्री कंवल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क के साथ ऐनक्रोचमैंट नहीं है। आपको मालूम है कि हरियाणा में पंजाब शिडयूल्ड रोडज एंड कन्ट्रोल औफ अर्बन एरियाज एक्ट लागू है। इस एक्ट के मुताबिक पी.डब्ल्यू. डी. की बाउंडरी 150–200 गज तक होती है और उस एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती लेकिन रोहतक बाई–पास पर अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन की गई है और इस ऐक्ट की अवहेलना की गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस केसिज को क्या ये कंपाउंड करने जा रहे है?

श्री फूल चन्द: स्पीकर साहब, मेरे नोटिस में ऐसा कोई केस नहीं है और न ही कोई कंपाउंड करने की बात है। जब भी कोई केस सरकार के नोटिस में आएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

Declaration of Ambala Tehsil as Industrially Backward Area

***1233. Seth Ram Dass Dhamija**: Will the Minister for Industries be pleased to refer to Starred Question No. 715 answered on the floor of the House on 4.4.1984 and state the date on which the matter for declaration of Ambala Tehsil, as Industrially Backward Area, was referred to the Government of India and the stage at which the matter stands at present?

उद्योग मंत्री (श्री श्रीकिशन दास): अम्बाला जिला को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोशित करने के लिये भारत सरकार को 16.3.1984 को अनुरोध किया गया था। मामला अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, मैंने अम्बाला तहसील का क्वैश्चन दिया था लेकिन मंत्री महोदय ने अम्बाला जिले का जवाब दिया है। अम्बाला तहसील में चार हल्के पड़ते हैं। इसी फरवरी में मंत्री महोदय ने ब्यान दिया था कि अम्बाला तहसील जल्दी ही बैकवर्ड डिक्लेयर होने जा रही है। स्पीकर साहब, करीब तीन साल पहले यानि 16.3.1984 को इन्होंने भारत सरकार को लिखा था कि अम्बाला तहसील को बैकवर्ड डिकलेकर किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। जहां तक अम्बाला में इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, हजारों की तादाद में वहां पर छोटी–2 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। जितना सामान हरियाणा से ऐक्सपोर्ट होता है उसका एक तिहाई हिस्सा अम्बाला से ऐक्पपोर्ट होता है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो अभी–अभी बैकवर्ड घोशित हुआ है वहां पर अम्बाला के मुकाबले में बहुत कम इन्डस्ट्रीज हैं, लेकिन उसको बैकवर्ड घोशित कर दिया गया है जबकि अम्बाला को नहीं किया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिसके बारे में मैंने चार साल पहले क्वैश्चन दिया था और तीन साल पहले केन्द्रीय सरकार को लिखा गया अब तक इन तीन साल में सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

श्री श्रीकिशन दास: स्पीकर साहब, राज्य सरकार ने 15 बार केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखा है और अभी 12.2. 1987 को फिर लिखा है। इसके लिए एक कमेटी बनी है और यह मामला उस कमेटी में आ रहा है कि इसको जल्दी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार दे दिया जाए। स्पीकर साहब दूसरी बात यह है कि जब वहां पर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं तो उसको इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर कराने में कुछ देरी हो भी जाए तो कोई विशेश बात नहीं है।

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, जिला कुरूक्षेत्र की थानेसर तहसील को इंडस्ट्रीयली बैंकवर्ड डिक्लेयर कराने के लिए मैंने प्रार्थना की थी और लिखकर भी दिया था। स्पीकर साहब, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक हर शहर में इन्डस्ट्रीज हैं परन्तु कुरूक्षेत्र में कोई इंडस्ट्रीज नहीं हैं। पिछली दिनों वहां पर पांच सौ एकड जमीन इंडस्ट्रीज के लिए ऐक्वायर की गई थी लेकिन जमीन के हाई रेट होने के कारण किसी ने नहीं ली। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि तहसील थानेसर को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर कराने का कश्ट करेंगे?

श्री श्रीकिशन दास: स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर कराने के लिए जनवरी, 1987 में केस सैन्ट्रल गवर्नमैंट को भेजा गया है।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई हुई है जो यह फैसला करती है कि कौन सा इलाका इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित किया जाए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी से क्या यह इंफरमेशन आई है कि अम्बाला जिले के कौन–कौन से इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया है?

श्री श्रीकिशन दास: स्पीकर साहब, ऐसी कोई खबर अभी नहीं आई है।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसी इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिए सरकार ने कोई जनरल पालिसी बनाई हुई है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिकलेयर करने के लिए डिजर्व करता है?

श्री श्रीकिशन दास: स्पीकर साहब, गवर्नमैंट आफ इंडिया ने तो इसके लिए अपने नार्मज बनाए हुए हैं और एक कमेटी बनाई हुई है जो इस बात का फैसला करती है। हमारे नोटिस में जो केस आता है उसके बारे में हम गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिख देते हैं जैसे कि अभी कुरूक्षेत्र का केस हमने भेजा है।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या सरकार ने किसी क्षेत्र को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिए नार्मज फिक्स

किए हुए हैं कि एक तहसील में इतनी नम्बर आफ इंडस्ट्रीज होनी चाहिएं और कई दूसरी बातें हैं जिनकी बिनाह पर किसी तहसील को बैंकवर्ड डिक्लेयर किया जाता है? अभी अम्बाला के बारे में बताया गया है कि बारह बार केन्द्रीय सरकार को लिखा गया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया है। क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि धमीजा साहब को खुद वहाँ पर भेजा जाए? मैं समझता हूं कि ये खुद वहां जाकर बात कर लेंगे और उसका फैसला करा लेंगे।

श्री श्रीकिशन दास: स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार खुद भी एरियाज को बैकवर्ड घोशित करती है और उस नीति के मुताबिक उसने ये एरियाज बैकवर्ड घोशित किए हैं – गुड़गांव में नुंह, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका और तावडू ब्लाक। फरीदाबाद में – हथीन ब्लॉक। अम्बाला में – कालका एंड नारायणगढ़ तहसील। रोहतक में – सब–तहसील नाहड़, झज्जर एंड रोहतक।

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी कहा था कि जब अम्बाला में बहुत अधिक इंडस्ट्रीज हैं तो उसको बैकवर्ड डिक्लेयर करवाने में कुछ देरी भी हो जाए तो कोई विशेश बात नहीं। स्पीकर साहब, मेरी तहसील में एक आदमी से लेकर पांच आदमी तक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हमारे यहां छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं हैं इसलिए इस तहसील को बैकवर्ड डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज को बिजली मिलती न हो तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी।

सारे वर्कर्ज बेकार हो जाएंगे बिजली है नहीं और उसकी वजह से वर्कर्ज के पास काम नहीं है इसलिए इस तहसील को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। स्पीकर साहब, मुझे दिल्ली भेजने की बात कही गई। मैं कहता हूं कि मुझे अपने खर्च पर ही भेज दो, मैं एक दिन में ही काम करवा लूंगा।

श्री श्रीकिशन दास: स्पीकर साहब, हम बैकवर्ड डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बैकवर्ड एरिया इसलिए डिक्लेयर करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज उस एरिया में लगें जहां इंडस्ट्रीज नहीं हैं।

श्री मोहन लाल पिपल: स्पीकर साहब, जब पाटौदी महेन्द्रगढ़ में थी तो बैकवर्ड एरिया घोशित किया हुआ था और जब से गुड़गांव में आया है तब से बैकवर्ड नहीं रहा। क्या मंत्री महोदय पटौदी को बैकवर्ड एरिया घोशित करने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीकिशन दास: स्पीकर साहब, रिवाड़ी को इस वास्ते निकाला गया था कि जहां तीस करोड़ लागत की इंडस्ट्रीज हो जाएं वह एरिया बैकवर्ड नहीं रहता। मैम्बर साहब ने जो कहा है उसकी हम जांच करा लेंगे।

Construction of Water Works

***1247. Ch. Inder Singh Nain**: Will the Minister of State for Public Health be pleased to state –

(a) whether there is any porposal under consideration of the Government to construct water works at following villages of district Hissar.

(i) Uklana Gaon;

(ii) Banbhori-Sandlana;

(iii) Litani;

(iv) Sarsana and

(v) Kheri Jalab; and

(b) if so, the time by which the construction of the above said water works is likely to be completed togetherwith the estimated cost thereof, separately?

Minister of State for Public Health (Sh. A.C. Chaudhry):

(a) Yes.

(b) All these 5 schemes have already been commissioned. The approved estimated cost of these schemes is as follows.

	Name of scheme	Estimated Cost (Rs. in lakhs)
(i)	W/S to Uklana gr. of 2 No. villages	46.51

(ii)	W/S to Banbhori gr. of 3 No. villages	29.59
(iii)	W/S to Scheme villages Litani	22.90
(iv)	W/S to Sarsana gr. of 5 No. villages	40.10
(v)	W/S to Kheri Jalab gr. of 4 No. villages	45.46

चौ. इन्द्र सिंह: मंत्री महोदय ने यह तो बता दिया कि स्कीम्ज चालू हो गई हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये स्कीमज कम्लीट कब तक हो जाएंगी?

श्री ए.सी.चौधरी: स्पीकर साहब, सरकार की हमेशा यह मंशा रहती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीने का पानी कम से कम समय में मिल जाए। इस सम्बन्ध में जो भी स्कीम हमने बनाई है उसको दो पार्ट में इम्पलीमैंट करते हैं। पहले पार्ट में उसकी अरजैन्सी को फीड करते हैं और दूसरे पार्ट में औगमैन्टेशन के लिए कार्यवाही करते हैं। पांचों स्कीम्ज का पहला पार्ट कम्पलीट हो चुका है और मैं समझता हूं कि आज के वक्त की जरूरत के मुताबिक पूरा पानी मुहैया हो रहा है। इसके साथ ही साथ जहां औगमैंन्टेशन की जरूरत है वहां के लिए फण्डज ऐलोकेट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को पूरा पानी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने वचन दिया है कि 1990 तक पीने का पानी हर गांव में पहुंच जाएगा और कोई

भी प्रोब्लम विलेज नहीं रहेगा। पहले ही यह प्रोब्लज खत्म कर दी जाएगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल हिसार जिला में सम्बन्धित है लेकिन मैं फरीदाबाद के मुताल्लिक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब का जवाब फेवरेबल होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जैसे मेवला महाराजपुर और बल्लबगढ़ में एम.आई.टी.सी. की नहर जो आगे दूसरी बड़ी नहरों को फीड करने के लिए निकाली गई हैं, वहां पर आज पानी पूरी तरह से ऐक्सप्लायट हो रहा है जिसके कारण से वहां पर 50 से 60 फीट तक पानी का लेवल नीचे चला गया है और यहां के तकरीबन सारे गांव प्रौब्लम विलेजिज बन गए हैं। क्या आने वाले दो–तीन महीनों के अन्दर–अन्दर इन गांवों में जो लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं, उनको दूर करने को सरकार कोशिश करेगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और लोगों को हर तरह की सहूलियतें मुहैया हो सकें?

श्री ए.सी. चौधरीः स्पीकर साहब, जहां तक फरीदाबाद जिले का ताल्लुक है, इस वक्त वहां पर कुछ 459 गांव हैं और जिनमें से 251 प्रोब्लम विलेजिज है। इनमें से 228 विलेजिज को पानी मुहैया कर दिया गया है। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि उस इलाके में सूखा पड़ जाने के कारण और डीप वैल्ज होने के कारण पानी का लैवल काफी नीचे चला गया है। इसके लिए

सरकार पूरी तरह से सतर्क व जागरूक है। लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। न सिर्फ प्रोब्लम विलेजिज में बल्कि और दूसरे सभी गांवों में जहां–जहां लोगों को दिक्कतें होंगी और जहां भी लोगों को पानी की आवश्यकता होगी, वहां पर पानी मुहैया किया जाएगा। मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं। कोई दिक्कत होगी तो उसे अवश्य दूर किया जाएगा।

Construction of SYL Canal

***1259. Sh. Bhalle Ram**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to refer to the reply to Starred Question No. 1163, answered on the floor of the House on 25.11.86, and state –

(a) the percentage of earth work and lining work executed on S.Y.L. Canal in the Punjab Territory upto 31.1.1987; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government for the early completion of the said Canal togetherwith the time by which the4 construction of the said Canal is likely to be completed?

Irrigation & Powr Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a)	(i)	Earthwork	:	77.94% upto Jan. 1987 & upto middle of Feb. 79.4%
	(ii)	Lining	:	19.86% upto Jan. 1987 & upto middle of Feb. 21.8%

(b)	Progress of construction of SYL Canal in Punjab territory is being reviewed nad monitored regularly in the meetings held at Govt. of India level to ensure its early completion. These meetings are attended by Haryana and Punjab and bottlenecks, if any, are discussed therein, and remedial, measures are evolved after detailed discussions. As per schedule supplied by Punjab, Government construction of SYL Canal in Punjab territory is targetted to be completed by December, 1987.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि अर्थ–वर्क लगभग 80 परसैन्ट के करीब और लाईनिंग का काम लगभग 20 परसैंट के करीब पूरा हो चुका है बाकी का अर्थ–वर्क कब तक पूरा होने की संभावना है। इसके लिये कोई जमीन भी ऐक्वायर की गयी है या नहीं?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जमीन तो लगभग सारी ऐक्वायर हो चुकी है। केवल पौने–चार एकड़ रिलिजियस लैंड ऐक्वायर करनी बाकी है जिसके लिये नो–औबजैक्शन–सर्टीफिकेट ले लिया गया है सैक्शन 4 और 6 क अन्तर्गत नोटीफिकेशन की कापी प्रैस को भेज दी गयी है और जमीन का पोजैशन 15.3.1987 तक मिल जाने की सम्भावना है। ऐसा पंजाब वालों ने हमें आश्वासन दिया है। मार्च क मिडल तक जमीन ऐक्वायर हो जाएगी। जहां तक अर्थ–वर्क का सवाल है, इस बारे में में हमें उम्मीद है कि यह शिडयूल के मुताबिक पूरा हो

जाएगा और बाकी जो दूसरे वर्क्स हैं, उनका इस वर्श के अन्त यानि दिसम्बर 1987 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

श्री कर्नल सिंह: स्पीकर साहब, एस.वाई.एल. पर जो ब्रिजिज और ऐक्वीडक्टस बनने हैं उनकी अब तक क्या प्रोग्रैस है? क्या मंत्री महोदय रोशनी डालैंगे कि इस पर मेजर–क्रौस–ड्रेनेज वर्क्स की प्रोग्रैस कितीन है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, ऐक्वीडक्टस तथा मेजर क्रोस ड्रेनेज वर्क्स कुल 11 हैं। इनकी काम की जो प्रोग्रैस है, वह काफी स्लों है, इसमें घग्गर सुपर–पैसेज भी शामिल है। इसी तरह से सिरसा ऐक्वीडक्ट पर भी काम चल रहा है और यह काम दिसम्बर, 1987 तक हो जाने की सम्भावना है। इसी तरह से भीडियम क्रौस ड्रेनेज वर्कस की संख्या 41 है जिन पर काम आरम्भ हो चुका है। टोटल ब्रिजिज 73, नैशनल हाईवे ब्रिजिज 4, स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट रोड़ ब्रिजिज 11, विलेजिज रोड ब्रिजिज 55 तथा रेलवे ब्रिजिज 3 है। रेलवे ब्रिज नम्बर 1 जोकि राजपुरा के पास है पूरा हो चुका है। रेलवे ब्रिज नम्बर 2 पर भी 80 प्रतिशत का हो चुका है और नम्बर 3 पर काम की प्रौग्रेस बहुत अच्छी है। बाकी के ब्रिजिज पर प्रोग्रैस वेरी करती है। इस तरह काम की यह डिफरैन्ट स्टेजिज हैं और शिडयूल के अनुसार यह काम दिसम्बर, 1987 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

श्री मोहन लाल पिपल: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों में यह आश्वासन दिया था कि प्रदेश के पंचों और सरपंचों को एस.वाई.एल के निर्माण का कार्य दिखाया जाएगा। क्या इस विधान सभा के सदस्यगण को भी निर्माण कार्य दिखाया जाएगा?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इस बारे में मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। शायद उस समय मैम्बर साहब सदन में नहीं होंगे। मैंने कहा था कि विधान सभा के सदस्यों का पंचों और सरपंचों से काफी ऊंचा दर्जा है। वे जब भी चाहें किसी वक्त भी जाकर एस.वाई.एल. का कार्य देख सकते हैं उनके लिये कोई समस्या नहीं है। इस बारे में सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं उन्हें दी जा सकती होंगी, वह दी जाएंगी।

चौ. लीला कृश्ण: स्पीकर साहब, इन्होंने कई बार कहा है कि सरकार का यह प्रयत्न है कि इस एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का काम केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार ने क्या–क्या उपाय किये हैं ताकि यह कार्य केन्द्र सरकार के हाथों में आ जाए?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इसके लिये हरियाणा सरकार निरन्तर प्रयत्न कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे में केन्द्र सरकार से पत्र–व्यवहार भी किया है और

मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और दूसरे मंत्रीगणों से इस बारे में मिले भी हैं और इस बात को प्रैस भी किया है। हमें यह आशा है कि केन्द्र सरकार इस काम को जल्दी ही अपने हाथ में ले लेगी और यह काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इस काम में हमें काफी सफलता मिली है।

Opening of Veterinary Hospitals in the State

***1267. Ch. Roshan Lal Arya**: Will the Minister of State for Animal Husbandary be pleased to state –

(a) the number of new veterinary hospitals, if any, proposed to be opened in the State during the year 1987-88; and

(b) the constituency-wise number of such hospitals opened in the State during the year 1986-87 (to-date)?

पशुपालन राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) 30. डिसपैंसरियों/स्टाकमैंन केन्द्रों को वर्श 1987–88 में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) वर्श 1986–87 में राज्य सरकार ने 40 पशु डिसपैंसरियां खोली हैं तथा 30 पशु डिसपैंसरियों/स्टाकमैंन केन्द्रों को दर्जा बढ़ाकर पशु हस्पताल–कम–प्रजनन केन्द्रों में परिवर्तित किया है जिनका विवरण अनुबन्ध ''क'' एवं ''ख'' में सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न हे।

अनुबन्ध ''क''

नई पशु डिसपैंसरियां खोलना (1986–87)

क्रम	जिले का नाम	खोली गई पशु डिसपैंसरियों की संख्या	विधान सभा क्षेत्र
1	2	3	4
1	अम्बाला	1	जगाधरी
		1	संढौरा
		1	अम्बाला कैन्ट
2	भिवानी	4	तोशाम
		1	मुढाल खुर्द
3	फरीदाबाद	1	फरीदाबाद
4	गुड़गांव	2	तावडु
		1	गुड़गांव
5	जीन्द	2	नरवाना

		1	कलायत
6	हिसार	1	बरवाला
7	महेन्द्रगढ़	1	रिवाडी
		1	अटेली
		1	महेन्द्रगढ़
8	करनाल	1	नीलोखेड़ा
		1	पानीपत
		1	घरौंडा
		1	समालखा
9	कुरूक्षेत्र	1	रादौर
		1	थानेसर
		1	शाहबाद
		1	पुंडरी
10	रोहतक	2	बादली
		1	हसनगढ़

		1	बेरी
		1	किलोई
		1	रोहतक
11	सिरसा	2	रोड़ी
		1	डबवाली
12	सोनीपत	1	कैलाना
		1	बरोदा
		1	रोहट
		1	सोनीपत
	कुलः	40	

अनुबन्ध ''ख''

पशु डिसपैंसरियां/पशुधन केन्द्रों को नियमित पशु हस्पतालों एवं प्रजनन केन्द्रों में अपग्रेड करना (1986–87)

क्रम	जिले का नाम	खोली गई पशु डिसपैंसरियों की	विधान सभा क्षेत्र

		संख्या	
1	2	3	4
1	अम्बाला	1	छछरौली
		1	यमुनानगर
2	भिवानी	1	मुढाल खुर्द
		1	तोशाम
3	फरीदाबाद	1	मेवला महाराजपुर
		1	बल्बगढ़
4	गुड़गांव	1	फिरोजपुर झिरका
		1	ताबडू
5	हिसार	1	बरवाला
6	जीन्द	1	राजौन्द
		2	सफीदों
7	करनाल	1	समालखा

		2	नौलथा
8	कुरूक्षेत्र	1	पुन्डरी
		1	पेहवा
		1	कैथल
9	रोहतक	1	बहादुरगढ़
		1	हसनगढ़
		1	महम
10	सिरसा	1	डबवाली
		2	रोड़ी
		2	ऐलनाबाद
11	सोनीपत	1	रोहट
		1	सोनीपत
		2	राई
	कुल :	30	

चौ. रोशन लाल आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि डिसपैंसरीज/अस्पतालों को अप–ग्रेड करने का सरकार का क्या क्रायटेरिया है?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जहां पर आवश्यकता होती है वहां हम डिसपैंसरीज/स्टाक मैन सैन्टर्ज बना देते हैं और जहां हस्पतालों की आवश्यकता होती है वहां पर अगर गांव वाले हस्पताल के लिए जमीन व डाक्टर के रहने के लिये क्वाटर वगैरह के लिए जमीन दे दें तो हम वहां पर हस्पताल खुलवा देते हैं।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय स्टेट में टोटल कितने पशु हैं और कितने पशुओं के पीछे आप एक डिसपैन्सरी खोलते हैं तथा प्रति पशु कितना खर्चा आता है? क्या यह सब भारत सरकार के नौर्मज के अनुसार ही किया जा रहा है?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में करीब 80 लाख पशु है जिनकी ब्रेक–अप इस प्रकार है:– बैफेलो 33 लाख, पौनी 28 हजार, डांकी 86 हजार, शीप 7 लाख 83 हजार और गोट 5 लाख 94 हजार। इसके अलावा कम से कम 1 लाख 23 हजार कैमल्ज हैं, पिग्ज 2 लाख 51 हजार ये कुल 80 लाख के करीब हैं। दूसरे इन्होंने पूछा कि प्रति पशु कितना खर्चा

आता है यह 80 पैसे के करीब आता है। पशुओं के बारे में केन्द्र का जो नार्म है वह काफी नीचा है।

श्री बनारसी दास बाल्मिकी: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में कम से कम डेढ़ दो लाख रूपए लगा कर पंचायतों ने डिसपैंसरीज के लिए बिल्डिगें बना रखी हैं। क्या मंत्री महोदय वहां डिसपैंसरीज खोलने पर विचार करेंगे?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, मैंने पहले ही कहा है कि जहां जरूरत है वहां सरकार डिसपैंसरी/हस्पताल खोलने की कोशिश कर रही है। अगर इनके हल्के में डिसपैंसरी खोलने की जरूरत होगी तो वहां भी खोलने की कोशिश करेंगे।

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गउएं मरने लग रही हैं उनकी सेवा क्यों नहीं करते? (हंसी व शोर)

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि गउ मरनी नहीं चाहिए, अगर मरती हैं तो उनकी जिम्मेदारी लाल सिंह की है क्योंकि मेरे से पहले इस महकमे के यही मंत्री थे। (हंसी)

चौ. अजमत खां: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि किसी जिले में 3, किसी में 5, सिकी में एक और किसी में 4 डिस्पैसरीज खोली गई हैं। फरीदाबाद जिले में केवल एक खोली गई है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वहां पर पशु नहीं हैं? कहीं

ऐसी बात तो नहीं है कि जिस जिले के नुमांयदे इनकी बात न मानते हों वहां पर मांग के अनुसार इन्साफ न मिलता हो?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि फरीदाबाद जिले में पशु कम है। वहां की पंचायत ने या तो रैजोल्यूशन नहीं किया होगा या मकान वगैरह बना कर नहीं दिया होगा। कोई न कोई कारण जरूर है। जो बात ये कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, अम्बाला कैंट में भी एक डिसपैंसरी खोल रहे हैं। अगर मंत्री जी हल्का–वाइज जानवरों की संख्या देंखे तो अम्बाला में सबसे ज्यादा हैं। अम्बाला कैंट में 6 गवाह मंडी हैं। इसलिये वहां पर कम से कम दो डिसपैंसरीज जरूर होनी चाहिएं।

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, हल्का वाइज फिगर तो मेरे पास नहीं है लेकिन जिला वाइज जरूर हैं जो मैं इनको बता देता हूं। अम्बाला में 7.67 लाख पशु हैं, भिवानी में 6.44 लाख हैं, फरीदाबाद में 4.52 लाख हैं, गुड़गांव में 6.09 लाख हैं, हिसार में 8.93 लाख हैं, जीन्द में 6.86 लाख हैं, करनाल में 8.32 लाख हैं, कुरूक्षेत्र में 8.05 लाख हैं, महेन्द्रगढ़ में 5.75 लाख है, रोहतक में 6.46 लाख हैं, सिरसा में 5.56 लाख हैं और सोनीपत में 4.70 लाख पशु हैं।

चौ. लीला कृश्णः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नील गाय और राम गाय भी पशुओं मे ंआती हैं। अगर आती हैं तो क्या उनकी सम्भाल की जाएगी?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, ये दोनों तो पशुओं में आती हैं लेकिन जो राजनैतिक नील गाय हैं वे पशुओं में नहीं आती। पिछली बार भी सैशन में झगड़ा हुआ था। जहां तक इनके प्रबन्ध का सवाल है, उनके लिए कैंचिग पार्टीज का प्रबन्ध है। राम गाय उसको कहते हैं जिसे लोग छोड़ देते हैं और ऐसी गउओं को झुंड में इकट्ठा करके पकडने का प्रावधान है। उनको एक जगह इकट्ठी करके गौ सदन में भेज देते हैं जहां तक नील गाय का ताल्लुक हें उसको कैचिंग पार्टी नहीं पकडती। अगर उसे पकड़ लिया जाता है तो वह मर जाती है। गाय के मरने के साथ धार्मिक भावना जुड़ी हुई है इसलिये नील गाय को नहीं पकड़ा जाता।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, ये जो डिसपैसरीज अपग्रेड की जाती है क्या ये इन–डोर और आउट–डोर पेशैंट देखकर की जाती है कि या किसी एरिया का लोड देखकर की जाती हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अभी मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज फिग्गर्ज बताई हैं कि सिकी जिले में कौन–कौन से और कितने जानवर हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि अम्बाला जिले में जो उन्होंने जानवर बताएं हैं उनमें गधों की तादाद कितनी है? (हंसी)

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, किसी डिस्पैंसरी को अपग्रेड करने के लिए इन डोर या आउट डोर पेशैंटस का सवाल नहीं है। जो आ जाता है उसका इलाज किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नजदीक के गांव में डाक्टर को ले जाते हैं इसलिए यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहां तक अम्बाला में गधों की संख्या की बात है मेरे ख्याल में ऐसा कोई रिकार्ड तो नहीं है लेकिन अन्दाजा है कि अम्बाला में सबसे ज्यादा गंधे हैं (हंसी)

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके अनुसार 1986–87 में 40 डिस्पैंसरीज खोली गई हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि जो पंचायतें डिस्पैंसरी के लिए कमरे तथा डाक्टर की रिहायश के लिए मकान बनाएंगी वहां भी इन्हें खोल देंगे। मेरे हल्के में तीन जगह पर पंचायतें यह सहूलियत देने के लिए तैयार हैं। क्या मंत्री जी वहां डिसपैंसरीज खोलने का आश्वासन देंगे?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, इस बार ग्राम पंचायतों की तरफ से काफी दरखास्तें आई हैं लेकिन कई जगहों पर डिस्पैंसरी के लिए कमरा या डाक्टर के लिए क्वार्टर नहीं थे। इसलिये हम वहां नहीं खोल सके। अगले साल हम वहां खोलने की कोशिश करेंगे जहां पर ये सारी सुविधा होंगी।

चौ. शकरूल्ला खां: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि वे डिस्पैंसरीज वहां खोलते हैं जहां की पंचायत

डिस्पैंसरी के लिए कमरा तथा डाक्टर के लिए क्वार्टर बना कर दे। मेवात के इलाके फिरोजपुर झिरका तथा नुंह में एक भी डिस्पैंसरी नहीं है जबकि वहां की पंचायतें ये सुविधा देने के लिए तैयार है। मिसाल के तौर पर मैं गांवों के नाम बता देता हूं। नई, बिछुर, तिगांव, दोहा, महू, साकरस और जमालगढ़।

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो अगले साल जरूर गौर कर लिया जाएगा।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Construction of pucca road from Brah Kalan to Kharak Ramji

***1271. Sh. Brij Mohan**: Will the Minister for Public Works (B & R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct pucca road between village Brah Kalan, in Jind District, and village Kharak Ramji; and

(b) if so, the time by which such a proposal is likely to materialise?

लोक निर्माण मंत्री (श्री फूल चन्द):

(क) जी हां। मिट्ठी का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

(ख) धन राशि उपलब्ध होने पर यह कार्य 1988–89 में पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद फौरन ही बजट पर बोलूंगा। मैं इस समय यहां पर अपोजीशन पार्टी का अकेला मैम्बर हूं। पहले इधर बहुत सारे अपोजीशन के साथी बैठा करते थे। मैं बजट पर बोलने से पहले यह इत्तलाह चाहूंगा कि हमारे यहां पर कौन–कौन सी पार्टीज हैं और उनके कितने–कितने मैम्बर हैं। यह इस विधान सभा का आखिरी सैशन है। मैंने अखबार में पढ़ा है कि इस हाउस में जनता पार्टी की भी एग्जिसटैन्स है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि यहां पर किस–किस पार्टी के कितने–कितने मैम्बर्ज हैं। बजट पर बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि मुझे यह बता दिया लाये कि हाउस में कितनी पार्टियां हैं, उनके कितने–कितने मैम्बर्ज हैं और उनके नेता कौन–कौन हैं।

श्री अध्यक्षः यह बात हाउस में उठाने वाली नहीं है। यह इन्फर्मेशन तो आप हमारे स्टाफ से ले सकते थे।

श्री लछमन सिंहः सर, मुझे इस बारे में इलम नहीं था। I am sorry to have put you to inconvenience.

Mr. Speaker: You can meet the Secretary of the Vidhan Sabha and get necessary information.

श्री लछमन सिंह: बहुत अच्छा जी।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

उचाना कलां निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में ओलावृश्टि से नश्ट हुई फसलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री सूबे सिंह पुनिया की तरफ से उनकी कांस्टिचुऐंसी उचाना कलां के कुछ गांवों के किसानों की फसलों का हेल स्टौर्मज से हुए नुकसान के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन मिला है। मैं इसे ऐडमिट करता हूं। श्री सूबे सिंह पुनिया अपना नोटिस पढ़ दें।

Ch. Sube Sing Punia: Sir I want to raise the urgent matter of public importance to draw the attention of the august House that the crops of peasants in a dozen of villages in my Constituency, Uchana Kalan, is badly and totally damaged by hail storms on 16th February night. The people of the villages named: Danoda Kalan, Danoda Khurd, Sainthly, Durjanpur, Darond Khera. Nachhar Khera, Kakrod, Surbara, Mangalpur, Daroli Khera, Uchana Khurd, Makhand and Budain met the A.D.C. of Jind with the loaded trollies of hail storms. I myself also visited the area with the Sub-Divisional level officers in the affected villages. The crop of wheat, gram, oil seeds Sarson (सरसों) Sugar care and fodder is badly damaged. On account of this, the farmers are suffering a great

loss. 5000 acres of land of the above mentioned villages affected by the hail storms of my area. The crops of "Ashari" (आशाढ़ी) is very much expensive, dur to the inputs of seeds, pesticides and fertilizers. The loss is intolerable for the poor peasants. The loss is estimated near about Rs. 4.00 crores. Therefore, Haryana Government is requested to compensate the farmers at the earliest to meet out their losses and provide fodder for the cattle of the area at minimum rates. This is a matter, of urgent public importance.

श्री अध्यक्षः क्या मंत्री महोदय इसका जवाब अभी देना चाहेंगे।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह): जी हां।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री द्वारा उपराक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

राजस्व राज्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह): स्पीकर साहब, दिनांक 16 फरवरी, 1987 को जिला जीन्द के 13 गांवों उचानाखुर्द, सुरबाड़ा, नच्दर खेड़ा, काकरोद, मखंड, मंगलपुर, बुडैन, दरौली खेड़, दनोदाखुद्र, दनोदा कलां, सेंथली, दरियावाला तथा खेड़ी जजवान में वर्शा के साथ ओलावृश्टि हुई जिससे खड़ी फसलों विशेशकर गेहूं, सरसों और चना को बहुत हानि हुई। फिर 24 फरवरी, 1987 को जीन्द जिला के 36 गांवों में ओलावृश्टि

हुई। इन कुल 49 गांवों में से 16 जींद उप मण्डल और 20 नरवाना तथा 13 सफीदों उप मण्डल के हैं, जहां ओलावृश्टि हुई है जिससे नुकसान हुआ है। ओलावृश्टि से 24000 एकड़ क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकार न 10.00 लाख रूपए की राशि उपायुक्त जींद को प्रभावित किसनों में चारा तकावी तथा सबसिडी बांटने के लिए दी है।

2. जींद जिला के इलावा राज्य के दूसरे भागों में विशेशतया फरीदाबाद, गुडगांव, भिवानी तथा रोहतक जिलों में ओलावृश्टि से 15, 16 23 तथा 24 फरवरी को भारी नुकसान हुआ। हिसार, महेन्द्रगढ़, सोनीपत, सिरसा तथा करनाल जिलों के कुछ गांव भी प्रभावित हुए हैं। पूरे राज्य में ओलावृश्टि से प्रभावित गांवों में विशेश गिरदावरी के आदेश दे दिये गये हैं और यह विशेश गिरदावरी हो रही है। जबकि प्रभावित क्षेत्र और अलग–अलग खेतों की हानि की मात्रा का पूरा पता विशेश गिरदावरी के परिणाम पर ही आधारित होगा परन्तु प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य के लगभग 875 गावों के 5.90 लाख एकड़ का कुछ क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

3. जिन लोगों की इस अचानक प्राकृतिक आपदा से फसलें नश्ट हो गई है, सरकार उनके दुःखों और कठिनाइयों से बहुत चिन्तित है। मंत्रिमण्डल की एक उप समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष सिंचाई तथा विद्युत मंत्री है, वित्त, कृशि तथा राजस्व राज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। यह समिति राज्य में

ओलावृश्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने के प्रश्न के बारे में विचार कर रही है। उपायुक्तों को हिदायत दी गई है कि जिलों में औलावृश्टि से प्रभावित क्षेत्रों में शत प्रतिशत चैंकिंग करवाई जाये ताकि खराबा बिल्कुल ठीक दर्ज किया जाये और कोई भी पात्र व्यक्ति सहायता से वंचित न रह जाये और इस कार्य के लिए उनको हिदायत की गई है कि जिला के सभा उपलब्ध अधिकारी इस काम में लगा दिये जायें। राजस्व विभाग के अमले को कड़ी हिदायत कर दी गई है कि अगर खराबा को लिखने में कोई भी गलती पकड़ी गई तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. भारत सरकार को इस अभूतपूर्व आपदा से हुए नुकसान के बारे में सूचित कर दिया गया है और प्रभावित किसानों के लिए पर्याप्त सहायता मांगने के लिए उनको एक विस्तृत ज्ञापन भेजा जायेगा। मैं इस महान सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ओलावृश्टि से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी।

चौ. सूबे सिंह पुनिया: अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख की रात के अलावा 24 तारीख को भी मेरी कांस्टिचुऐंसी के कुछ गांवों में फिर ओलावृश्टि हुई। इस ओलावृश्टि के बाद मैं सब डिवीजन आफिसर के अधिकारियों के साथ जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे, मौके पर गया था। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने जो प्रिलिमिनरी

रिपोर्ट तैयार की है, उसमें 75 प्रतिशत से अधिक किसी भी गांव में किसी भी फसल का नुकसान नहीं दिखाया। सरसों और मसरी की तो 100 परसैंट के आसपास फसल खराब हुई है। मैं चाहूंगा कि उन प्रभावित क्षेत्रों को खेती–बाड़ी के स्पैशलिस्ट देखने जायें। ओलावृश्टि यदि नहीं होती तो वहां पर एक–एक एकड़ में सरसों और सारी मसरी की फसल 10–20 और 25–25 मन होनी थी लेकिन अब वहां पर 20–25 किलो से ज्यादा एक एकड़ में फसल नहीं होगी। मैं आपके जरिए मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या उस इलाके की किन्हीं स्पैशलिस्ट से स्पैशल गिरदावरी करवायेंगे ताकि वहां के किसानों को अपनी फसल के हुए नुक्सान का उचित मुआवजा मिल सके?

श्री निर्मल सिंह: जहां पर इन्हें शक लगता हो कि गिरदावरी ठीक नहीं हुई है मुझे लिखकर दे दें, वहां पर हम स्पैशल गिरदावरी करवा देंगे। इस बात पर सरकार पूरी तरह निगाह रखती है कि गिरदावरी के मामले में कहीं पर कोई गड़बड़ न हो।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने सूबे सिंह पुनिया क काल अटैन्शन मोशन का जवाब देते हुए बताया है कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जायेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि पिछले साल अक्तूबर में मेरे हल्के के अन्दर ओलावृश्टि से कपास की खड़ी फसल तबाह हो गई थी। उस समय हुए नुक्सान का मुआवजा किसानों को आज

तक नहीं मिल पाया है। मुझे तो यह भी पता चला है कि किसानों को जो मुआवजा देने का केस आया था वह रिजैक्ट होकर चला गया है क्योंकि फण्डज नहीं हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वहां के किसानों को उस समय हुए नुकसान का मुआवजा देने पर फिर से विचार किया जायेगा?

Mr. Speaker: You are not entitled to ask question on this motion.

श्री कंवर सिंह: स्पीकर सर, मेरी तो सिर्फ सबमिशन है।

Mr. Speaker: No, please.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, कई जगह ओले पड़े और वे जगहें शायद इनके नोटिस में नहीं आई होंगी।

श्री अध्यक्ष: भले राम जी आप बैठिए। यह बैड प्रैसिडैन्ट होगा। जिस मैम्बर को मोशन हो वही सवाल पूछ सकता है।

चौ. सूबे सिंह पुनिया: स्पीकर साहब, आशाड़ी की फसल बड़ी खर्चीली इसके लिए बहुत से किसान तो सरकार से कर्जा लेते हैं और बहुत से किसान पुरानी प्रथा के अनुसार आढ़तियों से कर्जा ले लेते हैं जिसे वापस करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। विशेश कर उस समय जब उनकी फसल का नुक्सान हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि किसानों को जो सहकारी ऋण दिया गया है उसे खरीफ की फसल आने तक मुल्तवी कर दिया जाए।

इसके अलावा, स्पीकर साहब, गांव में प्रभा है कि कारीगर यानि खाती और लोहार किसान के हल के उपर निर्भर करते हैं। अगर किसान के घर एक मन अनाज आता है तो उसे आधा किलो अनाज मिलता है। अगर किसान की फसल मर जाए तो उन लोगों को कोई अनाज नहीं मिलता और उनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। मेरी प्रार्थना यह है कि उन लोगों के लिए भी राहत के काम, जैसे तालाब खुदवाना आदि का काम शुरू करवाए जाने चाहिएं।

स्पीकर सर, एक और सबमिशन मैं करवा चाहता हूं। इस समय हरे चारे यानि बरसेम पर कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त स्पीकर साहब, गेहूं के प्लान्ट पर जब ओला पड़ जाता है तो जहां उसका दाना काला और कड़वा हो जाता है वहां उसकी तूड़ी भी कड़वी हो जाती है। इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि यदि सूखे घास के लिए और हरे चारे के लिए भी मुआवजा देने का प्रावधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।

स्पीकर साहब, हमारे इलाके में एक कोआप्रेटिव शूगर मिल है क्योंकि वहां गन्ना काफी पैदा होता है। आजकल वहां गन्ने की बुआई शुरू है जो 15 अप्रैल तक शुरू रहेगी। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि गन्ने की बीज बोने से पहले किसान को खेत में प्ले करना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि वहां 15 दिन के लिए पानी ज्यादा

मात्र में दे दिया जाए तो किसान खेतों में प्ले करके गन्ने का बीज आसानी से बो सकता है। मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि गन्ने का बीज रियायती दर पर किसानों को दिलाया जाए।

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, इसके बारे में निवेदन यह है कि जहां ओलावृश्टि से नुक्सान हुआ है वहां हम काम के बदले अनाज की स्कीम चलाएंगे। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है वहां कोआप्रेटिव और दूसरे कर्जे पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। जहां तक चाहे का सम्बन्ध है, चारा लोगों को दनै का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि वह भी हमारी इमदाद करे। इसके अलावा भी सरकार सहानुभूमि से सोच रही है कि हम किसानों की क्या मदद कर सकते हैं?

स्पीकर साहब, कुछ चर्चा यह भी हुई कि पहले जिन इलाकों में ओलावृश्टि हुई थीं, वहां के किसानों को भी रिहायतें दी जाएं। स्पीकर साहब, इसके बारे में निवेदन यह है कि अगर इनको हैल्प की गई तो उनकी भी साथ ही की जाएगी।

स्पीकर साहब, जहां तक 15 दिन के लिए पानी देने की बात का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल में अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो सुरजेवाला जी अवश्य इसका प्रावधान कर देंगे और हर जगह पूरी इमदाद करने की कोशिश की जाएगी।

चौ. सूबे सिंह पुनिया: स्पीकर साहब, मैंने निवेदन यह किया था कि जब हरे चारे की फसल नश्ट होती है तो उसका चने और गेहूं का फसल की तरह कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इस बारे में बरसेम की फसल बिल्कुल नश्ट हो गई है। क्या सरकार इसके लिए भी कोई मुआवजा देगी?

श्री निर्मल सिंह: इसके लिए हमने चारा देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा चारे पर तकावी भी देंगे और सबसिडी भी देंगे।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, गवर्नर ऐड्रैस पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस हाउस के एक मैम्बर के खिलाफ बहुत सीरिया चार्जिज लगाए थे लेकिन जब भी सदन मीट करता है तो वह सदस्य हाउस में आता नहीं और अपने खिलाफ लगे चार्जिज का जवाब नहीं देता। Why does he fear to face the charges levelled against him in the House? उसे चाहिए कि वह हाउस में आए और अपनी पोजिशन क्लैरिफाई करे। मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि आप उस मैम्बर को सदन में बुलाएं क्योंकि अभी बहुत टाईम है ताकि वह अपने खिलाफ लगे चार्जिज के बारे में सफाई दे सके।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ हालात में किसी व्यक्ति के भाग अच्छे होते हैं। चौ. भजन लाल जी का भाग्य अच्छा था कि उनको सरकार को कोई क्रिटिसाइज

नहीं कर सका। अब चौ. बंसी लाल जी का भाग्य अच्छा है और सारे मिनिस्टरों का भाग्य अच्छा है कि इनकी कारकर्दगी को कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं।

वर्श 1987–88 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब ईयर 1987–88 के बजट पर जनरल डिस्कशन शुरू होगी।

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर सर, मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब को एक बात के लिए मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि कल जो बजट इन्होंने हाउस में पेश किया है वह टैक्स फ्री है। इसके अन्दर इन्होंने हरियाणा की जनता का पूरा ख्याल रखा है और कोई टैक्स उन पर नहीं लगाया। दूसरी तरफ स्पीकर साहब, 34.63 करोड़ रूपया के घाटे का बजट है। इसका कारण भी इन्होंने बड़ा वाजिब बताया। वर्श 1986–87 की ऐनुअल प्लान पहले 525 करोड़ रूप्ये की बनी थी लेकिन चूंकि सोशल और इकोनौमिक डिवैल्पमैंट के लिए इसे बाद में 569.62 करोड़ कर दिया गया इसलिए कुदरती बात थी कि घाटे का बजट इन्हें मजबूरी की हालत में पेश करना पड़ा। इन्होंने यह भी जस्टिफिकेशन दी है कि इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे। अगर फाइनैंस मिनिस्टर साहब और गवर्नमैंट कोशिश करेगी तो यह घाटा पूरा हो सकता है इसमें कोई शक की बात भी नहीं है।

स्पीकर सर, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने बहुत ज्यादा स्ट्रैस एस.वाई.एल. पर दिया है। स्पीकर साहब, आप तो मिनिस्टर भी रहे हैं और आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी है लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि बहुत अर्से से हरियाणा में इसके मुताल्लिक बहुत बड़ी चर्चा है और ऐजीटेशन भी है लेकिन वह मैं कहूंगा कि पोलिटिकली मोटिवेटिड है। लोगों को बहुत चिन्ता है कि यह नहर जल्दी बननी चाहिए। स्पीकर साहब, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि प्राईम मिनिस्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया हे कि जो भी खर्चा एस.वाई.एल नहर के बनने पर अब तक हुआ है और जो आयंदा होगा उसे भारत सरकार देगी। जो पैसा अब तक खर्च हुआ है उसे भारत सरकार री–इमबर्स करेगी। इससे हरियाणा की इकौनोमी पर बहुत अच्छा असर होगा और जो प्रौजैक्अस स्टेट गवर्नमैंट ने चलाने हैं, जैसा इन्होंने इस बजट के अन्दर बताया है, उन्हें ये अच्छी तरह से चला सकेंगे। स्पीकर साहब, मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब से इस बारे में एक अर्ज करना चाहूंगा। मैंने कल टैलिविजन पर 'सच की परछाई' कार्यक्रम देखा था। श्रीमती नलिनी सिंह उसमें खराब ईटें उठाती हुई दिखाई गई थीं। कहीं वह हाल पंजाब में जो नहर बन रही है उसका न हो। वैसे हरियाणा सरकार इस काम की मौनिटरिंग करती होगी और सारा कुछ देखती होगी लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इसका काम अच्छी तरह होना चाहिए। यह कोई पोलिटिकल इशू नहीं है। यह हमारी बदकिस्मती है कि यह पोलिटिकल इशू बना है। भले ही इसमें 6 महीने ज्यादा लगें,

साल ज्यादा लगे लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन में मैटीरियल पूरा और अच्छी स्पैसिफिकेशन का लगना चाहिए। स्पीकर साहब, जब एक दफा नहर बन जाये ओर उसमें सीपेज हो जाये तो उसका आधा पानी तो वेस्ट हो जायेगा। इसी प्रकार से अगर उसमें सीमेंट पूरा न लगे और जल्दी के अन्दर जैसा कि अभी कहा गया था कि दो शिफ्टें लगा कर या तीन शिफ्टें लगाकर काम को पूरा कर दिया जाये तो उसका इतना लाभी नहीं होगा। मैनुअल वर्क पर जितना टाईम लगना है वहा तो लगेगा। अगर आप किसी मकान का लैन्टर लगायें और पांच सात दिन के बाद उसकी शैटरिंग उतार दें तो वह बिल्डिंग गिर जायेगी। मेरी सुझाव है कि इस बारे में जल्दी नहीं करनी चाहिए। स्पीकर साहब हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं लेकिन इस बात का चुनाव पर या लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि एस.वाई.एल. को दूसरी स्टेट वाला नहीं है इसलिए इसके बनने में वक्त लगेगा। हर चीज के बनने में वक्त लगता है। हमारी अपनी स्टेट में 90 किलोमीअर लम्बी नहर बननी थी, वह जल्दी बन गई और सस्ती भी बन गई। यह बहुत अच्छे वक्त में बन गई लेकिन जब यह नहर चलेगी तो इस 90 किलोमीटर लम्बी नहर पर भी काफी खर्च करना पड़ेगा। उसकी सफाई करनी पड़ेगी। हम सभी यह कहते हैं कि हरियाणा को इससे फायदा होगा इसलिए यह जल्दी बननी चाहिए लेकिन मैकैनिकली और टैक्नीकली जितना टाईम लगना है वह तो लगेगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) अगर जल्दबाजी में यह नहर बनगी तो ऐसा ही मैटीरियल

लगेगा जैसा कि सैन्ट्रल पी.डब्ल्यू.डी. का टैलीविजन पर दिखलाया गया था। एक बार नहर खराब हो गई तो यह बहाना मिल जायेगा और यह नहर नहीं कर पायेगी। आज हाउस में मिनिस्टर सहाब ने बताया कि सरपंचों और पंचों को नहर दिखाने के लिए ले जाया जायेगा ताकि उनकी तसल्ली हो सके कि नहर बन रही है। नहर का काम इस वक्त अच्छा चल रहा है और इसमें कोई शक की भी बात नहीं है। अगर इस नहर को सैन्ट्रल गवर्नमैंट का हैन्डओवर कर दिया जाये तो बहुत जल्दी बन सकती है। वहां की सियुएशन ही ऐसी है कि सरकार को कोशिश के बावजूद भी काम ढीला हो जाता है। उसके और भी रीजन हैं। सरकार की भी मजबूरी है। इसलिए इसका काम भारत सरकार को अपने जिम्मे लेना चाहिए। हरियाणा और पंजाब को इसे भारत सरकार को देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब कि सारे का सारा पैसा भारत सरकार का लगता है। पंजाब सरकार का पैसा भी केन्द्र सरकार ने देना है और हरियाणा का पैसा भी सैन्टर ने देना है। इसलिये इसकी सुपरविजन और जिम्मेदारी भी भारत सरकार की होनी चाहिए। मैं पंजाब सरकार से भी दरखास्त करूंगा कि उन्हें इसे भारत सरकार को देने से इन्कार नहीं करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे अपोजिशन के साथी यहां पर बैठा करते थे। आप जानते हैं कि असैम्बली का टाईम पांच वर्श होता है। वे साथी दो वर्श से गैरहाजिर हैं। वे एस.वाई.एल. और चण्डीगढ का मसला लेकर जनता में जाते हैं। वे जनता में

प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी और संत लौंगोवाल के मध्य हुए अकौर्ड की क्लाज नौ और सात की बड़ी भारी बात करते हैं। इस बारे में पब्लिक जलसे और मीटिंगें करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत हरियाणा की जनता तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा और इस सदन को भी बताना चाहूंगा और साथ ही फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से भी जवाब चाहूंगा कि पंजाब अकौर्ड को हुए आज एक डेढ़ साल हो गया है लेकिन वह कौन सी क्लाज है जो हरियाणा के खिलाफ इम्पलीमैंट हो चुकी हैं? मुझे तो यह बात समरू में नहीं आती प्राईम मिनिस्टर साहब ने ऐग्री किया कि अगर हरियाणा को इन यू औफ चण्डीगढ़ एरियाज नहीं देंगे तो चण्डीगढ़ ट्रांसफर नहीं होगा और कैनाल इतने अर्से के अन्दर मुकम्मल होगी। यह ठीक है कि कहीं ऐजीटेशन की वजह से उसमें कुछ डिलें हो गयी हो। अब चण्डीगढ़ के आम आदमियों को बड़ी गलतफहमी है और वे यह समझते हैं कि 70 हजार एकड़ एरिया वह आयेगा जो हिन्दी स्पीकिंग है। डिप्टी स्पीकर साहब बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने प्राईम मिनिस्टर साहब की स्टेटमैंअ पढ़ी होगी और अखबार वालों ने जो बार–बार कहा वह भी पढ़ा होगा। दूसरी तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमैंट भी पढ़ी होगी और साथ ही उन नेतागण की भी स्टेटमैंट पढ़ी होगी जो सरकार को अपोज करते हैं। उन सबके अन्दर वह पंजाबी स्पीकिंग एरिया है। इन लयू आफ चन्डीगढ़ वह एरिया हमें मिलना है जो हरियाणा का है, वह तो वैसे ही मिल जायेगा जब क्लाज 7.4 के तहत बाउन्डरी

कमीशन बैठेगा। तो उसके लिए प्राईम मिनिस्टर भी कभी एग्री नहीं करते और हरियाणा के लोग भी एग्री नहीं करते। यह बड़ी भारी कंफयूजन क्रियेट कर दिया है कि हरियाणा की फाजिल्का अबोहर नहीं मिला तो क्या मिला। वे तो और एरियाज है। They are otherwise disputed areas. हरियाणा को जब भी कभी एरिया मिलता है इन लयू आफ चन्डीगढ़ मिलना है 'इन लयू आफ चण्डीगढ़' का मतलब सिम्पल है। अंग्रेजी की डिकशनरी निकाल कर देखें तो उसके माने यही हैं कि चण्डीगढ़ के बदले। चण्डीगढ़ के बदले तो वही चीज देंगे जो पंजाब की अपनी है। जो हरियाणा को क्लाज 7.4 के तहत आने वाली है उसका तो कोई यहां मतलब होता नहीं। यह बिल्कुल कलियर और साफ बात है इसलिए मैं अपोजिशन के दोस्तों से एक बात कहना चाहूंगा कि वे इस हाउस के एम.एल.ए. हैं, यहां पर अपनी बात रखे सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते है। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है वह यह समझ कर उठाया है कि अगर इतने आदमी हाउस से चले जाऐंगे तो शायद इलैक्शन बड़े जल्दी हो जायेंगे। इलैक्शन तो टाईम पर ही हुआ करने हैं। इलैक्शन पहले कैसे हो सकते हैं? 23 जून, 1987 तक हरियाणा की असैम्बली का पीरियड है। यह कहां पर लिखा हुआ है कि इलैक्शन जनवरी में करवायेंगे या फरवरी में? कल को इलैक्शन होने के बाद दूसरी विधान सभा बनेगी। अगर छः महीने के बाद गुस्से में जाकर या दाल न गलने के कारण फिर असैम्बली से बाहर चले जायें तो इस तरह से कैसे असैम्बली चलेगी? अब हरियाणा की जनता को यह शक हो सकता

है कि अगर हम इन्हें दुबारा चुन कर भेजेंगे तो फिर गैर हाजिर हो जाएंगे। अभी भी वक्त है और यह चूंकि लास्ट सैशन है इसलिए इन लोगों को फौरन हाजिर होना चाहिए तथा हाउस के अन्दर अपनी बात कहनी चाहिए। यह जनता का दरबार है। उनके ऊपर जनता के लोगों की जिम्मेदारी है। इन लोगों ने कांस्टीच्यूशन की कसम खाई हैं। उन्हें जिम्मेदारी के साथ लोगों के हितों की बात यहां हाउस में करनी चाहिए। इसलिए मैं फिर दरखास्त करूंगा कि उन सब भाईयों को यहां आना चाहिए और आकर अपना पक्ष पेश करना चाहिए। उन्हें यहां आकर फाइट करना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। एक आदमी यानि मैं ही क्या कर सकता हूं? सरकार के पास बहुत ज्यादा ताकत है। अगर यहां पर अपोजिशन के 20 और आदमी बैठे हों तो अपनी बात बता सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी एक बात आप नोट कर लें कि अभी हरियाणा के इलैक्शन में कोई बहुत लम्बा पीरियड नहीं है इसलिए इस इलैक्शन पर चण्डीगढ़ के इशू का और एस.वाई.एल. का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। कम से कम अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे सबसे जयादा ज्ञान है। अम्बाला, कुरूक्षेत्र और करनाल के बारे में आप जानते हैं कि उन पर क्या असर होगा। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जो भी सरकार बनाना चाहते हैं, उनका इकोनोमिक प्रोग्राम क्या है? वे देश की नेशनल इन्टैग्रिटी और यूनिटी के लिए कितना हाथ बंटा रहे हैं? क्या वे इस देश की 75 करोड़ जनता को इकट्ठा रख

सकते हैं? आप इस बात को देखें कि जो लोग पांच या सात इकट्ठे नहीं रह सकते, क्या वे 75 करोड़ लोगों को इक्ट्ठा रख सकेंगे?

उन्हें यहां आकर बताना चाहिए कि हमारी क्या प्लान व पालिसी है। जब तक वे जनता के दरबार में आकर अपना कार्यक्रम नहीं बतायेंगे तब तक वे अपनी डियूटी पूरी नहीं करते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो यह उसकी डियूटी की कोताही होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी श्री कंवल सिंह जी ने एक बात जीरो आवर में कही थी जिसका मैं यहा पर जिक्र करना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर चौ. बंसी लाल ने अपने गवर्नर ऐड्रैस के जवाब में चौ. देवी लाल और दूसरी के बारे में कुछ बातें कहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की हक हासिल है कि जो भी इस हाउस का मैम्बर है उसके बारे में वे बात कह सकते हैं। अब उस मैम्बर की डियूटी बनती है कि वह यहां हाउस में आकर कलैरीफाई करे कि यह गलत कहा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह असैम्बली का रिकार्ड है। कल को इलैक्शन आ रहे हैं। अगर उसकी नकल लगा कर कोई इश्तहार या पोस्टर छपा देता है तो उस अखबार वाले के खिलाफ कोई इज्जत हतक का दावा नहीं बन सकता और जिस ने भी पोस्टर छापा है उसके खिलाफ भी कोई बात नहीं बनती है। हाउस के अन्दर जो भी बात कही जाये वह कोर्ट के परव्यू से इम्यून है। यदि कोई इन्सीन्यूशन किसी के अगेन्सट छापता है या लिखता है, तो वह प्रिवलेज नहीं बनता है।

इसलिए मैं खासतौर से चौ. देवी लाल जी से कहूंगा कि उन्हें यहां जवाब देना चाहिए। उन्होंने ओथ भी ले ली है। उन्होंने चुपचाप आकर ओथ ले ली। उन्हें असैम्बली के अन्दर आकर ओथ लेनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने ओथ इसलिए ले ली कि एक दिन नेहरा साहब ने हिन्द समाचार अखबार में छपवा दिया कि चौ. देवी लाल जी तो कांस्टीच्यूशन को ही नहीं मानते हैं। जब उन्होंने यह अखबार में लिखा हुआ पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो इलैक्शन में ही गड़बड़ हो जाये इसलिए उन्होंने ओथ ले ली। इसलिए मैं आज भी उनसे अपील करूंगा कि वे इस हाउ के अन्दर आयें और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ऐलीगेशन्ज लगाये हैं उनका जवाब दें कि ये गलत हैं या सही हैं। जब तक वे इस बात को कलियर नहीं करेंगे तब तक इस हाउस के मैम्बर और हरियाणा की जनता को यह बात खलती रहेगी कि एक आदमी के खिलाफ ऐलीगेशन्ज लगत हें, उसे ऐक्यूज किया जाता है लेकिन उसका जवाब न आना ठीक नहीं होगा। अगर वे जवाब नहीं देंगे तो कोई इस बात को सही मानेगा और कोई गलत मानेगा। वेसे अखबारों में काफी बातें चलती हैं। उन्हें कोई आदमी पढ़ता है, कोढ नहीं पढ़ता है लेकिन जो बात असैम्बली में कही जाये और उसका उलट जवाब न हो तो यह समझा जायेगा कि उस पर ऐलीगेशन सही लगा है। आपने यहां हाउस में देखा होगा जब भी किसी वजीर के खिलाफ जरा सी बात होती है तो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देते हैं इसलिए चौ. देवी लाल को पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देनी बहुत जरूरी है। अगर वे हाउस के सामने

पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो यह बात उनके और ज्यादा खिलाफ जायेगी। अपोजिशन के भाई कहते हैं कि वे अचछे हैं। सभी अच्छे कभी नहीं होते हैं। चौ. देवी लाल जी अभी दो साल में दो दफा इलैक्शन हार गये। इसलिए सभी कैसे अच्छे हो सकते हैं। देवी लाल जी मेरे दोस्त हैं। मैं दोस्त के नाते अर्ज करना चाहूंगा कि उनके ऊपर यह बहुत बड़ा ऐलीगेशन है। अगर वे हाउस में आकर पोजिशन कलैरीफायी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ इश्तहार छप जायेंगे, जगह–जगह लोग पढ़ेंगे ओर यह बातें सच हो जायेगी। उन्हें यहां आकर उन बातों का जवाब देना चाहिए उन्हें यहां आना चाहिए और दूसरे लोगों को भी आना चाहिए। दो वर्श तक तो ये लोग नहीं आये, केवल तीन वर्श ही का पीरियड रह गया। अगर इस तरह से मैम्बर घर में बैठ जाये तो वह अपनी डियूटी पूरी नहीं करता है, वह अपनी डियूटी की कोताही करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपोजीशन के भाई समझेंगे और इस बात का आकर स्पश्टीकरण करेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बड़ें अफसोस की बात है। यहां पर मैंने जीरो आवर में सवाल किया था। आठ नौ जनता पार्टी के मैम्बर्ज हैं लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐप्लीकेशन नहीं दी कि हमने जनता पार्टी छोड़ दी है। वे आज भी उसी पार्टी के मैम्बर चले आ रहे हैं। उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी किसी पार्टी के साथ ऐफीलिएशन है। उनको यहां लिख कर देना चाहिए कि उनका किस पार्टी के साथ ऐफीलिएशन है। मैंने

लिख कर दिया, सब आदमियों ने लिख कर दिया है कि मेरी फलां पार्टी के साथ ऐफीलिएशन है। ऐन्टी डिफैक्शन बिल बना हुआ है। लगता है कि उनको उसका डर बना हुआ है जिसकी वजह से वे लिखकर नहीं दे रहे हैं। इस बात की कलैरिफिकेशन बड़ी जरूश्री है। जब तक वे हाउस में नहीं आयेंगे तब तक कलैरिफिकेशन नहीं हो सकती। सब बातों को कंफ्यूजन चल रहा है। हर आदमी कंफ्यूजन में है। यह पता ही नहीं है कि कौन कहां खड़ा हुआ है। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि अपोजिशन के भाई अपनी डियूटी समझ कर यहां आयेंगे। जनता ने उन्हें चुन कर भेजा है, वे अपनी डियूटी पूरी करें।

डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ बातें मैं बजट के मुताल्लिक भी कहना चाहता हूं। फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने कुछ राहतें दी हैं, छूट दी हैं, और बजट के अन्दर अन्दर उन्होंने घाटा भी दिखाया है। वे शायद डैफिसिट बजट पेश नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनकी दिक्कतें थीं, उनकी मजबूरियां थीं। उन्होंने पर्टीकूलर राहत चूड़ियां की दी हैं, यह बड़ी अच्छी बात की है लेकिन चूड़ियों के साथ कड़े भूल गये हैं क्योंकि चूडियों के साथ कड़े भी होते हैं। हमारे वाले भी कड़े होते हैं और औरतों के भी कड़े होते हैं। हमारी दो बहनें बैठी हुई हैं ये मोटे कड़े भी पहनती हैं, उनमें भी छूट देनी चाहिए थी और जो डायबैटिक हैं, वे भी कड़े पहनते हैं, वे एक मैटल के बने होते हैं। मैं यहां पर सोने की चूडियों की बात नहीं कर रहा हूं। सोने की चूड़ियों पर

सेल्ज टैक्स लगायें या न लगायें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना बहुत मंहगी चीज है। अगर मिनिस्टर साहब को यह सूट करता हो तो कड़ों को भी इसमें ऐड कर लें। ये भी चूड़ियों का पार्ट हैं। डिप्टी स्पीकर साहब सरकार ने जमींदारों को भी कंसैशन दिया है। बड़ी खुशी की बात है। जमींदारों को उनका मशकूर होना चाहिए। हरियाणा की जनता पर बहुत देर से मालिया चला आ रहा था। यह अंग्रेजों के टाईम से चला आ रहा था वह भी माफ किया है।

11.00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें महज मामले पर दे दी थीं। चौ. कंवल सिंह जी यहां पर बैठे नहीं हैं। नेहरा साहब, यहां पर बैठे हुए हैं। इनको पता होगा कि इनके जिले में तो लोगों ने मालिये पर जमीनें दी हुई हैं क्योंकि लोग मालिया भी नहीं दे सकते थे। यह एक बहुत बड़ी लानत थी। पहले एक नम्बरदार का फंक्शन सिर्फ मालिया इकट्ठा करने का होता था। मैं समझता हूं कि इसके अलावा उसका और कोई फंक्शन नहीं है। क्या फाइनैंस मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि अब नम्बरदार का औहदा ऐबौलिश कर दिया है या वह अभी तक कायम है। यह तो बड़ी खु ी की बात है कि बैकवर्ड भाइयों को भी नम्बरदार बनाया जा रहा है। पहले भी कुछ हरिजन और बैकवर्ड भाई नम्बरदार हैं लेकिन यह फैसला करके अब उनको बहुत बड़ी मुराद या फैसिलिटी दी गई है। धानक साहब बहुत

खुश नजर आ रहें हैं। इन्होंने हिम्मत करके यह करवाया है। ये मुबारिकबाद के मुस्तहक हैं। मैं मुख्यमंत्री का और हरियाणा सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने बैकवर्ड या कमजोर क्लासिज के लोगों को नुमांयदगी दी है, यह अच्छी बात है क्योंकि ये इलैक्शन में तो जीत नहीं सकते थे। इसी सैशन में सरकार एक्ट में भी अमैंडमैंट के लिए एक बिल ला रही हैं। इसके लिए भी मैं इनकी मुबारिकबाद देता हूं। इन्होंने जो कोशिश की है, यह हिम्मत की है। डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहेबान मुझे माफ करेंगे, कई बार वे रिप्लाई इवेड कर जाते हैं। बिल्कुल इवेड नहीं करना चाहिए। साफ करना चाहिए। यह कह देते हैं कि हमारे पास इन्फर्मेशन अवेलेबल नहीं हैं और हमारे पास फलां चीज अवेलेबल नहीं है। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब के नोटिस में एक बात पी.डब्ल्यू.डी. एंड आर. के बारे में लाना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि उन्होंने इसके लिये काफी पैसा रखा है। मैं यह बात भी मानता हूं कि सड़कों की मुरम्मत भी हो रही है लेकिन सिंगल लिंक्स को फर्स्ट प्रायरिटी देनी चाहिये। चाहे वह किसी हल्के के अन्दर हों। चाहे कितना ही पैसा लगता हो, वह पहले बनाने चाहियें। लोगों का कोई कसूर नहीं है अगर वह पहाड़ों में बसे हुए हैं या फुटहिल्ज में बसे हुये हैं। अभी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब मोरनी गये थे। इन्होंने वहां पर दो ऐसी रोडज सैक्शन की हैं जिससे लोगों ने खुशी में घी के चिराग जलाये वे पहाड़ों के अन्दर रहने वाले लोग बहुत खुश हैं। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, वह बहुत पुराने जमाने से रहते हैं। पहले जब

मुगलों के राज में कत्लोगारत हुआ करते थे, तब वे डर कर पहाड़ों में सेफर प्लेसिज में चले गऐ थे। वहां पर जाकर बस गये। कोई भी नीचे का आदमी अगर उसको सारी जायदाद भी दे दी जाये तो भी एक दिन भी वहां पर ठहरना नहीं चाहेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर कोई सहूलियत नहीं है। कोई सड़क नहीं हैं। पीने का पानी नहीं है बहुत सारी मुश्किलात हैं। हालांकि बजट के अन्दर बहुत सारा उनके लिए प्रोविजन रखा गया है लेकिन वहां पर कौन जाये? उनकी आवाज भी नहीं है। बेचारे बेसहारा और बे–जुबान हैं। न तो वे कोई अर्जी दे सकते हैं और न ही कोई डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार या एस.डी.एम. वहां पर कभी जाता है। मोरनी हिल्ज में अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आपके अफसर नहीं पहुंचे सिवाय महकमा जंगलात के अफसरों के जिन्होंने उनको केवल परेशन करना होता है। वह तो पहुंचते हैं लेकिन दूसरा कोई आदमी वहां पर नहीं जाता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मोरनी हिल्ज के लिए दो रोडज तो सैक्शन हो चुकी है। उन्होंने 569.62 करोड़ रूपये का बजट रखा है। आइन्दा के फाईव ईयर प्लान में फाइनैंस मिनिस्टर साहब हमें विश्वास दिलायें कि कालका, नारायणगढ़ और छछरौली कांस्टिचुऐसीज के हिल्ली एरियाज में जहां पर सड़कें नहीं बनी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, केवल 5–7 रोडज ही हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं पहले 5–7 दफा नाम ले चुका हूं। उनको उम्मीद है कि अगले 5 सालों में यह जरूर बना देंगे। 5 साल का अर्सा कोई कम अर्सा नहीं है। पैसा भी इनके पास काफी है डिटेल्ड प्रोग्राम

पब्लिक हैल्थ महकमें का बना रखा है। 1990 तक का प्लान बनाया हुआ है। मैं समझता हूं कि 1990 तक तो पीने के पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। लेकिन एक बात जी मैं अर्ज करना चाहूता हूं वह यह है कि पब्लिक हैल्थ वालों ने जो स्कीमें बना रखी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान हीं देते। मैंने यह बात गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए भी कही थी कि वे तमाम की तमाम स्कीमें फेल के बराबर होती चली जा रही हैं। अगर कहीं पर नलके टूट जाएं तो बदलने के लिए नलके नहीं है। अगर पाईप टूट जाए तो पाईप नहीं है। इसके लिए तो कुछ न कुद प्रोविजन होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, इसके लिये किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। There must be some person responsible for that. जब तक आप किसी बड़े अफसर को जिम्मेदारी नहीं रखेंगे तक तक बात नहीं बनेगी। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने यह दरखास्त करूंगा कि वे ऐसी हिदायतें जारी करें किं अगर इस किस्म की लैक्सिटी या कमजोरी या डियूटी की कोताही हो गयी तो बड़े अफसर जिम्मेदार होंगे। यह तो नीचे जिम्मेदारी डाल देते हैं। सिपाही के ऊपर जिम्मेदारी डाल देने से कोई बात नहीं बनती। उस बेचारे के पल्ले तो कुछ होता नहीं है। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने विनती करूंगा कि इस किस्म का कोई फैसला करें और सारी बातें उनको जाकर बतायें ताकि वह भी कुछ पार्ट प्ले कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहब कोआप्रेटिब्ज की बात मैं करना चाहूंगा। मैं जो बातें पहले बोल चुका हूं उनको बार–बार नहीं कहूंगा। मैं इस बार में एक सुझाव दूंगा। यह बात ठीक है कि कोई भी सरकार कर्जा माफ

नहीं कर सकती। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यह तो बिल्कुल क्लैरीफाईड है आप देखें कि इतना पैसा कहां से हरियाणा के पास आयेगा। इसका तो मतलब ही नहीं है। यह तो लोगों को बहकाने की बात है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर जो बात है, वह तो आप कर ही सकते हो। पंजाब के अन्दर जमींदार को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर वह कोआप्रेटिव का कर्जा नहीं दे सकता तो उसको परसूएड करते हैं, उसको मजबूर करते हैं और दूसरे साधन अख्तियार करते हैं। यहां पर जो 40 दिन की गिरफतारी की बात है, इसके बारे में मैं चौ. बंसी लाल जी से और हरियाणा सरकार से दरखास्त करूंगा कि इसको हटाया जाए। मैं यह चाहूंगा कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब जब जवाब दें तो यह बतायें कि क्या वे मेरी इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि उनको छोड दिया जाये और उनको गिरफतार न किया जाये। यहां गुरबत बहुत ज्यादा है। लोग 40–40 दिन तक जेल में पड़े रहते हैं उनके ऊपर और खर्चा पड़ जाता है। आप जानते हैं कि रैवेन्यू लौक–अप है। अगर किसी ने 500 रूपया देना है तो 100 रूपया खच्र उस पर और पड़ जाता है। वे उसकी पेमैंट नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यह बात कर दी जाए तो उससे जमींदारों के अन्दर को बदअमनी है वह दूर होगी। मैं समझता हूं कि कर्जा तो माफ नहीं कर सकते क्योंकि वह तो इम्पौसीबल बात है और उसकी करने का कोई फायदा नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि महंगाई के इस जमाने में उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं जो दूर होनी चाहिए।

एक बात डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इरीगेशन के बारे में कहना चाहूंगा। इरीगेशन का बहुत बड़ा महकमा है। जब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते, हमारी तरक्की नहीं हो सकती प्रोडक्शन तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक इरीगेटिड लैंड न हो। आप जानते हैं कि बंजर जमीन है कालका से लेकर छछरौली तक ओर ताजेवाला तक नहर तो निकलती है लेकिन उस नहर का पानी इनको नहीं मिलता। अभी इरीगेशन मिनिस्टर साहब ने बताया है कि वह कब लगेगा। इसके लिए एक प्लन बनाई हुई है। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि पिछले सैशन के अन्दर यह जवाब दिया गया था कि 15 करोड़ रूपये के खर्च से वहां पर 864 अर्दर्न डैम बनाएंगे। मैं यह कहता हूं कि अगर बनवाने हैं तो यह फोरैस्ट डिपार्टमैंट से बनवाएं, वह अच्छे बनायेगा। मैं एक क्लैरिफिकेशन फाइनैंस मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि यह पैसा 15 करोड़ का जो इन्होंने कहा था यह कितने सालों में खर्च होगा। इस साल में खर्च होगा या अगले साल में खर्च होगा। किस तरह से यह उस अमाउन्ट को बाईफरकेट करेंगे, वह जरा बता दें। एक साल में, 4 साल में या 5 साल में इस अमाउन्ट को खर्च करेंगे या पूरी प्लान में खर्च करेंगे, इस बारे में इनकी प्लान क्या है। इस इलाके के लोगों में बड़ी बदअमनी है क्योंकि यहां पर बड़ी गुरबत है। बिजली की बात यह ठीक है कि हम भाखड़ा से बिजली लेते हैं या थोड़ी थर्मल की भी बिजली है। इसके अलावा हमारे पास बिजली के हरियाणा में कोई साधन नहीं हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि कि आप के जो बड़े बड़े डैम्ज हैं,

उनको आम आदमी कोई देखता नहीं हैं। वे तो सिर्फ एक बात को देखते हैं कि हमारे बल्ब में जब हम बटन को दबाते हैं तो लाईट है या नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार इतने बड़े बड़े प्लान बनाती है, इतने बड़े–बड़े प्रोजैक्ट बनाती है तो उसके लिए बिजली की समस्या हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चाहे किसान लोग अनपढ़ हैं लेकिन वे सभी बातों को समझते हैं। उनको तो बिजली चाहिए जिससे कि वे अपना काम कर सकें। पंजाब में दो थर्मल प्लांटस है एकतो रोपड़ में है और दूसरा भटिन्डा में है। उन्होंने इन प्लान्टस के लिए केन्द्रीय सरकार से परमीशन नहीं ली थी क्योंकि उनके पास अपना पैसा था। जब तक हम अच्छी किस्म के थर्मल प्लांटस नहीं लगाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। इस काम को हमें प्रायरिटी देनी चाहिए। पंजाब में 24 घंटे बिजली इंडस्ट्रीज को मिलती हे। गोइन्दवाल में तो हालत यह है कि ऐप्लीकेशन दो और बिजली का कनैक्शन ले लो। यह ठीक है कि ला एंड आर्डर खराब होने की वजह से वहां कोई जाना नहीं चाहता लेकिन वहां पर बिजली की पोजीशन बड़ा अच्छी हे। हमारे यहां पर भी इंडस्ट्रीज लगाने का दो–चार जगहों पर बड़ा भारी स्कोप है लेकिन यह तभी होगा जब कि बिजली की सप्लाई में सुधार होगा। अगर हम किन्हीं एरियाज को बैकवर्ड भी डिक्लेयर करवा दें तब भी क्या होगा? अगर वहां पर बिजली की सप्लाई ठीक नहीं होगी तो उसका कोई खास लाभ नहीं होगा। बिजली इंडस्ट्रीज के लिए भी और फार्मर के लिए भी बहुत जरूरी है। लोग कहते है। कि 1978 में बिजली कहां से आ गई थी?

डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय बिजली आ नहीं गई थी बल्कि पोजीशन यह है कि 1978 में फ्लड आ गए थे। 1978 में जितना बड़ा फ्लड आया था उसके बाद इतना बड़ा फ्लड कभी नहीं आया। पानी की कमी नहीं रही थी। उसके बाद तो ड्राउट ही आए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, जब ड्राउट होता है तो जमींदार को बिजली की जरूरत उसी ड्राउट के समय होती है। दूसरी बात यह है कि पैट्रन आफ ऐग्रीक्लचर अब चेन्ज हो गया है। पहले जहां गन्दम की बिजाई होती थी अब वहां पर पैडी की बिजाई होने लगी है और उसके लिए पानी की बड़ी जरूरत होती है। अगर बिजली की कमी होगी तो किसानों को पानी जो टयूबवैल से मिलता है, वह नहीं मिल पाता और उनकी फसल को काफी नुक्सान होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय सवाल डिमान्ड और सप्लाई का है। बिजली की डिमान्ड ज्यादा है। सरकार को बिजली के बारे में टौप प्रायरिटी देनी चाहिए। हमारी सरकार को चाहिए कि भारत सरकार से जितनी भी मैक्सीमम थर्मल प्लांटस लगाने की परमीशन वह ले सकती हो, ले और अगर इसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो अपने लैवल पर जितने सोर्सिज यह जुटा सकती है, वह जुटाये। अपने लैवल पर जहां से भी पैसा मिले, उसको लेकर बिजली की सप्लाई को बढ़ाये। डिप्टी स्पीकर साहब, अपनी स्टेट को खुशहाल बनाने के लिये इसके सिवाय और कोई जरिया नहीं है कि बिजली की सप्लाई बढ़ाई जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे थर्मल प्लांटस क्यों फेल होते हैं। इसका कारण यह है कि कोल में पिलफिरेज होती है। बंगाल और आसाम की कोल

माइन्ज से डस्ट वाला कोयला आता है। पता नहीं रास्ते में कहां बंगलिंग होती है। रास्ते में कहीं गड़बड़ होने के कारण सारा कोयला खराब सप्लाई होता है और जब वह खराब कोयला प्लांटस में यूज होता है तो प्लांटस की मशीनरी खराब हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे औफिसर्ज को कोयले की सप्लाइ के बारे में बहुत अधिक केयरफुल रहना चाहिए। अगर कभी कोयला खराब आ जाता है तो उसको काम में नहीं लाना चाहिए। थर्मल के अन्दर डस्अ वाले कोयले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे इंजीनियरों के अन्दर रिजैन्टमैंट नहीं होनी चाहिए। उनके अन्दर डिस–सेटिसफैक्शन नहीं होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि यह टैक्नीकल काम है। इसका हर आदमी नहीं चला सकता। इस काम में आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब काम करने वाला आदमी आपका साथ दे। आपको पता है कि अगर आपके वर्कर ठीक नहीं होंगे तो इलैक्शन नहीं जीत सकते। इसी तरह से बिजली के वर्कर्ज के अन्दर डिस–सैटिस्फैक्शन होगी तो वे दिन से काम नहीं करेंगे। सरकार को प्रैजुडिस होकर काम नहीं करना है। उनकी समस्याओं को हली करना चाहिए। मुझे पता नहीं कि उनकी कोई समस्या है या नहीं लेकिन कहीं कहीं भनक आती है। बिजली की ठीक सप्लाई न होने का यह भी एक कारण हो सकता है। पंजाब में बिजली की प्रौब्लम क्यों ठीक है? यह नहीं है कि हमारे अफसर होशियार नहीं हैं। वहां से ही हमारे अफसर आए हैं और वे बहुत

काबिल हैं। हमें कुछ भी करना पड़े हमें हर हालत में बिजली की पोजीशन ठीक करनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला जिला बहुत अच्छा जिला है और यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बड़े भले मानस हैं। किसी से लड़ते नहीं हैं। अगर कोई बात मान ली जाती है तब भी ठीक है और अगर नहीं मानी जाती, तब भी ठीक है। यह बजट सैशन आखिरी सैशन है। चण्डीगढ़ तो पंजाब को जाएगा। कब जाएगा यह नहीं कहा जा सकता। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी हरियाणा की कैपीटल के साईट के सिलैक्शन की बात आए तो हरियाणा सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अम्बाला के लोगों को चण्डीगढ़ की फैसीलिटी पिछले चालीस साल से मिली हुई है। मुश्किल से एक घंटे का सफर है। मैं चौ. बंसी लाल से यह दरखास्त करूंगा कि हरियाणा की कैपीटल हमसे इतनी दूर न चली जाए कि अम्बाला के लोग यह महससू करें कि हमारे लिए यह एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। रिवाड़ी के लोग तो पिछले चालीस साल से चण्डीगढ़ आ रहे हैं औव वे अब इतनी तकलीफ नहीं महससू करते हैं लेकिन अगर राजधारी अम्बाला से दूर बन गई तो अम्बाला के लोगों की काफी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। राजधानी ऐसी जगह बने जो अम्बाला के लोगों को कफी दिक्तत खउ़ी हो जाएगी। राजधानी ऐसी जगह बने जो अम्बाला के नजदीक हो। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पंचकूला एक बहुत सुन्दर जगह है। चौ. बेसी लाल ने

इसको बसाया है। सभी लोग यहां पर बहुत अच्छे हैं। चण्डीगढ़ से भी अच्छी बिल्डिंग्ज हैं लेकिन हुड्डा के पास मैंटीनेंस के लिए पैसा नहीं है। मैंने जब हुड्डा वालों से बात की तो वे कहने लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है हमने तो प्लाटस बेच दिए। मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि हुड्डा को रोडज की मैंटीनेंस के लिए पैसा अधिक दिया जाए। वहां की सड़कों की हालत बहुत खराब है। पीन की तो इतनी किल्लत नहीं है। लेकिन बिजली की और रोडज की हालत खराब है। वहां पर स्ट्रीट लाईट ठीक नहीं है। वीकर सैक्शन के लिए हाउसिंग बोर्ड ने जो मकान बनाए हैं उनकी हालत यह है कि एक हाथ से दरवाजा खुल जाता है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर कम से कम रोडज तो ठीक होना चाहिएं। जहां तक अच्छे स्कूल्ज और मैंडीकल फैसीलीटीज की बात है वहां पर न तो अच्छे डाक्टर्ज हैं और न कोई अच्छा अस्पताल है। वहां पर कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है। पंचकूला सैट लाइट टाउन है। वहां पर एक बहुत अच्छा अस्पताल होना चाहिए और अच्छा कालिज व स्कूल होना चाएिहं अगर वहारं पर बहुत अच्छा अस्पताल होना चाहिए और अच्छा कालिज व स्कूल होना चाहिए। अगर वहा परन सैनीटेशन ठीक नहीं होगी तो वहां की डिवैल्पमैंट रूक जाएगी। वहां पर मुलाजिम लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं इसलिए वहां की डिवल्पमैंट का खास ध्यान रखना चाहिए। वहां पर इंडस्ट्री काफी डिवैल्प कर सकती है। पंचकूला एक ब्यूटीफुल जगह है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जब भी राजधानी शिफ्ट की जाए तो

टैम्पोरेरीली पंचकूला को राजधानी बनाया जाए। इस समय भी वहां पर काफी औफिसिज हैं और जब भी यहां से शिफटिंग हो तो वह शिफटिंग पंचकूला में होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पंचकूला हरियाणा की टैम्पोरेरी कैपीटल बननी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, ला एंड आर्डर के बारे में मैं चौ. बंसी लाल को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। लोगों के अन्दर इनके आने से बड़ा कौन्फिडैंस आया है। हम जब भी बाहर जाते हैं और लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो वह यही कहते हैं कि हरियाणा के अन्दर कायदा कानून और ला एंड आर्डर देश में सब से बेहतरीन है। इसके लिए मैं चौ. बंसी लाल को मुबारिकबाद देता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस ला एंड आर्डर को मेनटेन रखने के लिए यहां की ब्यूरोक्रेसी भी मुबारिकबाद की मुस्तहक है। चौधरी साहब जो भी आर्डर इशू करते हैं उसको इम्पलीमैंट करने में यहां की ब्यूरोक्रेसी कोई देर नहीं करती। चौ. बंसी लाल से पहले तो यह हालत थी कि कोई आर्डर इशू हो गया तो एक कहता था कि तू ले जा और दूसरा कहता था कि तू ले जा। कल मैं एक अफसर के पास 6.30 बजे गया। वह 6.30 बजे भी काम कर रहा था। मैंने पूछा कि क्या बात है तो उस अफसर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब के दफतर में यह कागज आज ही चाहिए। चौ. बंसी लाल बहुत ही मजबूत आदमी हैं। मैं तो कहता हूं कि डिस्पलिन तो होना चाहिए। जो वर्किंग क्लास है अगर वह डिसिपलिन्ड हो और अच्छे ट।ग से काम करे तो हरियाणा अब

नम्बर 2 पर है, वह एक दो सालों के अन्दर–अन्दर नम्बर 1 पर आ सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सब कुछ अपने सामने होगा, डिवैल्पमैंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिन रात पूरी तरह से डिवैल्पमैंट के कामों में लगे हुए हैं। बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। यह पोलिटीक्स मैच्योरिटी की निशानी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यहां यह कहते हुए बड़ी शर्म सी आती है कि हमारे विरोधी पक्ष के भाई बगैर मतलब के बढेंगा तरीके से शोर मचा रहे हैं और इस सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं आपको रैजिगनेशन की बात ही बताता हूं। रोहतक में आठ–दस हजार लोगों का इकट्ठे हुआ और यह फैसला कर लिया कि चलो भाई दे दो इस्तीफे और दे दिए। मैंने कहा कि हम 25–25 हजार की वोट से जीत करके यहां पर आए हैं, इन 10 हजार लोगों के पल्ले क्या है और इनसे आप अपनी तकदीर का फैसला क्यों करवाते हो? इसके अलावा यह बात भी देखने वाली है कि यदि ये कह दें कि इस्तीफे न दो तो क्या आप इस्तीफे नहीं देंगे? इसलिए जहां पर इस तरह के फैसले होने लग जाएं वहां इससे ज्यादा बदकिस्मती की और कया बात हो सकती है? मुझे एक बात और याद आ गई। मैं पंजाब का सैशन देख रहा था वहां किसी ने बताया कि एक किसान किसी जमींदार के घर चला गया। उसने वहां रात काटी। रात घोड़ी सुई और घोड़ी ने बछेरी दे दी। जब वह चलने लगा तो वह कहने लगा कि यह तो गाय की है। सारे गांव के पंच भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने यह

फैसला कर दिया कि यह गाय की ही बच्छी है। जब लोग जाने लगे तो वह रोने लगा। लोगों ने पूछा कि भाई रोते क्यों हो? कहने लगा कि मैं बच्छी की नहीं रो रहा, न ही घोड़ी की बात है। मैं तो रो रहा हूं कि जब यह पंच मर जाएगा तो ऐसे गल्त फैसले कौन करेगा? तो डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह के अपोजीशन के भाइयों के गल्त फैसले कि असैम्बली से इस्तीफा देना और असैम्बली सैशन अटैण्ड न करना यह कोई अच्छी रिवायात नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी टर्म का आधा पीरियड एबसैन्ट होने में काटा हो, यहां आकर अपने हल्के की कोई बात सरकार के सामने र रखी हो कि उनके हल्के की क्या–क्या दिक्कतें हैं, किसी बात को यहा पर न कहा हो तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि पहले तो जनता ही काट देगी परसैंटेज कम हो जाएगी, कुछ टिक्टों में कट जाएंगे। बहुत कम परसैन्टेज ऐसी होगी जो इस हाउस में आएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता होगा कि हम पिछली दफा टोटल 90 में से केवल 24 आये थे और अगली बार इस हाउस से 66 के करीब पहले सदस्य गैर हाजिर थे। पब्लिक ने उन्हें यहां पर नहीं भेजा था इसलिए मैं बार–बार अपोजिशन वाले अपने भाईयों से कहूंगा कि वे इस हाउस में आएं और अपनी बातों का यहां पर स्पश्टीकरण देवें। लेकिन इस वक्त हरियाणा के ऊपर यह ऐलीगेशन लगाये जा रहे हैं कि हरियाणा ने बहुत कुछ लूज किया है। हरियाणा का काफी नुकसान हुआ है। यह बिल्कुल गल्त बात है। इस बारे में लोग हमसे पूछना चाहेगे और समझना चाहेगे

लेकिन मैं डिप्टी स्पीकर साहब, इतना ही कह सकता हूं क्योंकि कोई खास ज्यादा सूझबूझ नहीं रखता, केवल अपने तजुर्बे के तौर पर इतना ही कह सकता हूं कि मुझे तो यहां पर कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जिससे कि हरियाणा के हितों के ऊपर कुल्हाड़ा गिरा हो या हरियाणा का किसी स्टेज पर नुकसान हुआ हो। यह ठीक है कि पानी पाकिस्तान को जा रहा है। कितना जा रहा है, यह वक्त ही बताएगा। लोग इराडी कमीशन का फैसला देख रहे हैं, उसकी इन्तजार में बैठे हैं, भारत की नजरें उसी पर लगी हुई हैं कि इराडी कमीशन का क्या फैसला आता है। अभी उसकी रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। पार्लियामैंट में अभी पेश नहीं की गयी। कब आएगी, कब वह रिपोर्ट रिलीज होगी, यह कह नहीं सकते। लेकिन नहर बनने से पहले–पहले तो वह रिपोर्ट रिलीज होगी ही और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलेगा ही। हरियाणा के अन्दर पीने के पानी का मसला है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी इस बारे में पंजाब के बहुत से अधिकारियों के साथ बात हुई है कि हरियाणा के अधिकारियों ने, हरियाणा सरकार ने इराडी कमीशन के सामने अपने पक्ष को बड़ी ही बखूबी के साथ रखा है। पंजाब के अधिकारियों का यह कहना है कि आपके अधिकारियों ने अपना पक्ष इस तरीके से रखा है कि हम उसका जवाब नहीं दे पाए। यह सारी बात, डिप्टी स्पीकर साहब, मेहनत की है कि किस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, आई.पी.एम. साहब और अधिकारीगण ने इस मामले में मेहनत की है और इसी मेहनत का यह नतीजा है कि वे इराडी कमीशन के सामने अपने

पक्ष को बड़ी बखूबी के साथ पेश कर पाएं हैं। इसके लिये मैं अपने चीफ मिनिस्टर, आई.पी.एम. साहब व सम्बन्धित अधिकारीगण को बधाई देता हूं लेकिन अन्त में इसका क्या फैसला होगा इस बारे तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। अखबारों की तुक्केबाजी है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फैसला क्या होगा इसके लिये हमें वेट करनी होगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि शायद विधान सभा का यह आखिरी सैशन होगा। मैं पहले भी कई दफा इस हाउस का मैम्बर रहा हूं हो सकता है कि कोई आदमी कोई गल्ती करता हो, कभी–कभी उल्टी सीधी बात भी करता हो। मैं इसके लिये सभी माननीय मैम्बर साहेबान से माफी चाहता हूं। I apologise to them. I also apologise to the people and the bureaucracy of the State क्योंकि आदमी कभी जजबात में आकर गल्त बात भी कह सकता है। इन शब्दौं के साथ मैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट का, जोकि फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने कल इस हाउस में पेश किया है, खैर मकदम करता हूं और इस बात के लिए फाइनैन्स मिनिस्टर महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बजट में गरीब लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखा है और यह बजट बिना किसी टैक्स लगाए यहां हरियाणा की जनता के सामने पेश किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बैठने से पहले डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका भी

धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जब हिन्द।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): डिप्टी स्पीकर साहब, आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने कल जो सदन के सम्मुख विचार हेतु बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन एवं अनुमोदन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। अगर बजट का गौर से दखेा जाए, गहराई से पढ़ा जाए तो इस बजट को समतावादी बजट और समाजवादी बजट कहा जा सकता है। इस बजट के अनदर सरकार ने हर क्षेत्र व हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हर प्रकार की लोगों को मदद देने की कोशिश की है। चाहे कोई उद्योगपति है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर व गरीब तबके का आदमी है, सभी को इस बजट के द्वारा राहत दी गयी है। इस प्रकार से इस बजट को अगर मैं सर्वे हितकारी बजट भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में प्रधानमंत्री द्वारा खास तौर से हरियाणा को दी गई मदद का जिक्र किया है। इसलिए सबसे पहले यह कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इसके लिए हरियाणा की जनता उनकी बड़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने पुराने संकल्प को दोहराया है। उन्होनं अपने देश के सामने घोशणा की थी कि हम इस देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने अन्य सूबों में भी, जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मदद देकर अपने उस संकल्प की पुश्टि की है ताकि सारा देश विकास की

गति पर तेजी से चल सके और हमारा देश 21वीं सदी में दुनिया के मुकाबले में आगे आए। इस सारे कामों के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने जो भरपूर मदद हमें दी है उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हरियाणा की डिवैल्पमैंट के लिए प्रधान मंत्री महोदय ने जो 403 करोड़ रूप्या दिया है, उसके साथ–साथ एम. बाई.एल. का भी विशेश रूप से जिक्र किया।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विपक्षी भाई यहां हाउस में न आकर यदि अपने घरों में बैठे रहें तो यह कोई औचित्य नहीं है। सरदार लछमन सिंह व मेरे दूसरे साथियों ने भी यहां बोलते हुए इस बात को कहा है। उनको चाहिए था कि वे यहा पर आते और हरियाणा के हितों के बारे में अपने पक्ष को खूब मजबूती और खुबसूरती के साथ यहां पेश करते और सरकार से इस बात का आश्वासन लेते कि हरियाणा को बहुत जल्द ही रावी–ब्यास के पानी का हिस्सा मिलना चाहिए जिसके ऊपर हमारी सारी खुशहाली का दारोमदार है लेकिन विरोधी दल के भाईयों ने ऐसा न करके जनता के साथ विश्वासघात किया है। अच्छा होता कि वे यहां सैशन का बाईकाट करने की बजाये, सरकार के साथ, इस नहर के मामले पर, जोकि हरियाणा के जीवन मरण का सवाल है, अपना पक्ष रखते, अपनी बात कहते, सरकार के हाथ मजबूत करते, केन्द्रीय सरकार के साथ यह मामला उठाते और इस चीज की पुश्टि करते कि जितनी जल्दी हो सके केन्द्र सरकार इस एस.वाई.एल. कैनाल के कंस्ट्रक्शन के

मामले को अपने हाथ में ले और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करे ताकि हरियाणा को पानी की उपलब्धि हो सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि वे हरियाणा सरकार के विरूद्ध काम करते रहे। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता होगा कि पिछले दिनों विरोधी पक्ष के एक भाई और पार्टी के एक बड़े जिम्मेदारी आदमी ने एक रैजोल्यूशन भी रखा था कि क्यों न यह सरकार और हाउस केन्द्र सरकार को यह सिफारिश करे कि एस.वाई.एल. के काम को सैन्टर अपने हाथ में ले। डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ तो यह रैलोज्यूशन रखा जाता है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि एस.वाई.एल. का काम तेजी से हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि पिछले दिनों विरोधी पक्ष के भाइयों ने इस काम को देखने के लिए एक कमेटी बनायी थी उसका काम था कि एस.वाई.एल. के काम का मुआयना करे कि कितना काम वहां पर हो गया है। उसके बाद अखबारों में आया था कि संघर्श समिति ने यह कहा है कि एस.वाई.एल. काम काम बड़ी तेजी से चल रहा है, बड़ा तसल्लीबख्श काम हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ वे इस तरह के रैजोल्यूशन पास करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनका मेन उदेश्य तो यह है कि जो सरकार, हरियाणा की सरकार जनहित के लिए, जनहित के कामों के लिए अपना जीवन मरण का प्रश्न बनाए बैठी है, उसको बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोआप्रेट न किया जाए ताकि कहीं यह क्रैडिट कांग्रेस सरकार को न चला जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, 1977 के बाद अढ़ाई–तीन साल तक

पंजाब, हरियाणा ओर केन्द्र में इनकी सरकारें रहीं लेकिन उस वक्त इन्होंने अपने प्रान्त के हितों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया हालांकि उस वक्त ये बड़ी आसानी से इन मामलों को निपटा सकते थे लेकिन उन दौरान इन लोगों का जनहित में ध्यान न होकर दूसरे कामों में ही लगा रहा। इनका तो केवल मकसद यही है कि कांग्रेस सरकार इस काम को सरअन्दाम न दे सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, बजट में आने आने वाले वक्त के लिए पैसे का वित्त मंत्री जी ने और सरकार ने जिस ढंग से बंटवारा किया है, उससे इस बात की फिर पुश्टि हो जाती है कि कुछ 585 करोड़ रूपये के बजट में से 367 करोड़ रूपया सिंचाई और बिजली के लिए रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसके किसान और मजदूर जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उसका विशेश ध्यान रखा है। सरकार ने बजट का 60 प्रतिशत पैसा उनकी हालत को मजबूत करने के लिए रखा है। इससे यह जाहिर होता है कि यह सरकार किसान और मजदूर की सच्ची हमदर्द सरकार है जिसके लिए वह एक बार फिर बधाई की पात्र हे। डिप्टी स्पीकर महोदय, आप भी जानते हैं और यह सर्व विदित है कि जब 1966 में हरियाणा बना था, तो उस समय लोग शक किया करते थे कि क्या हरियाणा अपने अस्तिव्त की भी रखा कर सकेगा या नहीं। लेकिन आज हम सब देख रहे हैं कि हरियाणा ने अपने अस्तित्व की ही रक्षा नहीं की बल्कि विकास के इतिहास में हरियाणा ने कीर्तिमान स्थापित किया है। चौ. बंसी

लाल जी को हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। यह एक सच्चाई की बात है। यहां तक कि इन्दिरा जी ने भी कई बार अपनी स्पीचों में दूसरे प्रदेशों में कहा है कि अगर विकास का नमूना देखना हो तो हरियाणा में जाकर देखा जाए जो चौ. बेसी लाल ने किया है। डिप्टी स्पीकर महोदय, पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में बंजर जमीन पड़ी थी जो आज लह–लहाती हुई नजर आ रही है। यहां पर हरित क्रान्ति हुई वे इंडस्ट्रियल क्रांन्ति हुई। इस देश के सामने इस प्रदेश के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज हरियाणा को देश में दूसरे नम्बर पर माना जाता है लेकिन मैं एक मायने में इसको पहले नम्बर पर मानता हूं। वह इसलिए कि पंजाब से अलग होते वक्त यहां कुछ भी नहीं था और पंजाब में उस समय भी सारे काम हुए पड़े थे। अगर उस की निस्बत आज हरियाणा को देखा जाए तो मैं हरियाणा को आज देश में सबसे पहले नम्बर पर मानता हूं। जहां तक किसानों का ताल्लुक है, किसानों के लिए पहले भी और आज भी हमारे मुख्यंमत्री जी की रहनुमाई में बहुत कुद हो रहा है। सारे देश में हरियाणा एक मिसाल है जिसने किसानों का लगान माफ किया है और खालों का पिछला सारा खर्चा माफ किया है। आगे के लिए भी सरकार ने अपने सिर पर जिम्मेदारी ली है। मैं समझता हूं कि यह इतना बड़ा काम है कि अगर दूसरे सूबे भी इसका अनुसरण करें तो यह एक आदर्श माना जाएगा। जहां तक विरोधी पक्ष की बात है वे भाई कहते हैं कि हम ही किसान और मजदूर के हमदर्द हैं लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अढ़ाई तीन साल के अर्से में जब उनका राज

था तो उन्होंने किसान और मजदूर के लिए क्या किया? जब वे सरकासर में नहीं थे तो भाव के बारे में नारे लगाते थे कि किसान को उसकी उपज का पूरा भाव नहीं मिल रहा है। 1977 में जब हकूमत बदली तो सबको मालूम है कि किसान की उपज के भाव कितने गिर गए थे। जब वे गए तो किसान की उपज के भाव अढ़ाई तीन गुणा बढ़ गए। उनको यह मालूम नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने कितनी गति से किसान की उपज के भाव बढ़ाए। सरकार ने हर चीज का ध्यान रखते हुए किसान की उपज के भाव बढ़ाए। किसान की उपज के भाव बढ़ाते हुए सरकार ने गरीब तबके का भी ध्यान रखा। विरोधी पक्ष के भाई इस बात को भूल जाते हैं कि उनके समय में डीजल की क्या हालत हो गई थी। किसानों को डीजल नहीं मिलता था और किसान उस वक्त अपने भविश्य को नश्ट होते हुए देख रहा था। आप सबको मालूम है कि उस समय गन्ने के भाव की क्या हालत थी और आज किस कदर गन्ने की कीमत दी जा रही है। मैं समझता हूं कि आज की सरकार ने किसान की हालत को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि इनके समय में जब किसान की जमीन ऐक्वायर की जाती थी तो उसको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। उसको 6 साल पुरानी कीमत दी जाती थी। उस समय किसान अदालतों में लड़ते फिरते थे लेकिन यह पहली सरकार है जिसने किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ–साथ मैं एक अफसोस भी जाजिर कर दूं कि यहां पर एलान

भी हुआ था और यह चीज मानी भी गई थी कि किसान अपनी जमीन को मां के रूप में देखता है क्योंकि उसके पास इसके सिवा और कोई साधन नहीं होता है। तो शहरों के साथ–साथ जो गांव लगते हैं उनकी जमीनें हुड्डा ने या दूसरे डिपार्टमैंटस ने ऐक्वायर की हैं। उसके लिए सरकार ने हुक्म दिया कि जिस किसान की जमीन ऐक्वारयर होती हे उसको एक रैजीडैशियल या इंडस्ट्रियल प्लाट दिया जाएगा। लेकिन दु:ख की बात यह है कि आज तक भी यह आदेश डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के पास नहीं पहुंचे हैं। यानी ऐसी व्यवस्था लिखित तौर पर नहीं की गई है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिस किसान की जमीन ऐक्वायर की जाती है उसको यह सुविधा जरूर दी जाए। मैं दूसरी अर्ज यह भी करूंगा कि कम्पलैक्स एरियाज में जहां जमीन तेजी से ऐक्वायर की जा रही है वहां मैं खासतौर से फरीदाबाद के 20 गांवों का जिक्र करूंगा। वे 20 गांव ऐसे आ गए हैं कि जहां पर ऐरिया बढ़ाने की कोई गुंजायश नहीं है। मैं चाहूंगा कि जहां जमीन पड़ी हुई है वहां उनके लाल डोरे को बढाने के लिए जरूर व्यवस्था की जाए। लेकिन जिनके पास जगह नहीं है वे कहां जाएंगे। इसलिए मंत्री महोदय से गुजारिश है कि वे इस चीज को नोट कर लें। यह जनता की जायज मांग हैं और सरकार अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो उसका भी गौरव हो जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक हुड्डा का ताल्लुक है इसके बारे में मैं थोड़ा और कहना चाहूंगा। आवास योजना के अन्तर्गत करोड़ों रूपया सरकार खर्च कर रही है। गरीब आदमी चाहे शहर में रहने वाला हो, उसके लिए

छोटी–छोटी कालोनीज बना कर सरकार उसको बुरियादी जरूरत उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने हरियाणा में हजारों ऐसे मकान उपलब्ध करवाए हैं और अब भी करीब तीन हजार मकान जिनमें दो हजार मकान छोटे हैं वह बनाने जा रही है। इसके बाद मैं फरीदाबाद शहर के लिए भी थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं। यह ठीक है कि सरकार गरीबों की मदद के लिए दृढ़ संकल्प है लेकिन फरीदाबाद जिले में आज झुग्गी–झोंपड़ियों की तादा 28 और 30 हजार के करीब है। जिस शहर में इतनी झुग्गी–झोंपड़ियां हो जाएं, उसकी क्या हालत होगी? इसे हम सुधारने की कोशिश करें या दूसरी सुविधाएं देने की कोशिश करें। झुग्गी–झोंपड़ियों के रहते हुए हालांकि उस एरिया का खूबसूरत एरिया बनना बहुत मुश्किल है लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वहां पर गलियां और नालियां बनाई जानी चाहिएं ताकि वे लोग भी सफाई के साथ वहां पर रह सकें। जो स्थिति आजकल वहां पर है वह किसी शहर के लिए अच्छा नमूना नहीं है। पिछली बार भी मैंने इस बारे में कहा था और सदन ने यह माना था कि यह जायज बात है। इस काम के लिए एक कमेटी बनाये जाने की बात कही गई थी। उस कमेटी ने सर्वे करना था कि 15–15 साल से जहां पर झुग्गी–झोंपड़ियां हैं, वहां के लोगों को सुविधा देने के लिए, आवास बोर्ड जो नई कालोनीज बना रहा है, उनमें प्राथमिकता के तौर पर उनके लिए सैक्टर आबाद किए जाएंगे। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनमें कुछ पैसा लेकर उनको अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए और सरकार का भी यह फर्ज बनता है कि वह भी अपनी तरफ से कुछ

पैसा और लगाए ताकि इन झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को गन्दगी में रहना न पड़े। समय रहते ऐसी जगहों पर काबू पाया जा सकता है नहीं तेा बाद में बहुत भारी समस्या हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं लोगों को प्रदान की हैं। इस साल भी बजट के अन्दर कुछ हस्पतालों का अपग्रेड यिका जा रहा है। यहा लोगों की बुनियादी जरूरत है। स्वास्यि ठीक रहना मनुश्य के लिए पहली जरूरत है। इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि जिस समय फरीदाबाद में सैक्टर्ज आबाद किए गए उस समय यह प्रोविजन किया गया था कि वहां पर 800 बैडज का एक हौस्पिटल होगा। फरीदाबाद के सैक्टर्ज आबाद हुए बहुत समय हो गया है। हौस्पिटल आदि की सुविधा के हिसाब से ही वहां के लोगौं से प्लाटों के पैसे चार्ज किए गए थे। लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि आजतक वहां पर उन लोगों को हौस्पिटल की सुविधा नहीं दी गई है। फरीदाबाद ओर बल्लभगढ़ साथ–साथ लगते दोनों शहर हैं। इन दोनों शहरों की आबादी करीब 4 लाख के आस पास है। फरीदाबाद शहर एक इण्डस्ट्रियल शहर हो चुका है। वहां पर इंडस्ट्रीज में या किसी और वजह से आगे दिन ऐक्सीडेन्टस बढ़ते जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रख्तो हुए सरकार का यह दायित्व है कि वहां पर एक हौस्पिटल जल्दी के जल्दी बनाया जाये। इस हौस्पिटल को वहां पर बनाए जाने के लिए अभी भी जगह पड़ी हुई है। यदि पूरा हस्पताल एक साथ नहीं बनाया जा

सकता तो पार्टली काम शुरू करवाया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं पेय जल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पेज जल लोगों की बुनियादी जरूरत है। इसके लिए सरकार ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हरियाणा में आज करीब 6700 गांव हैं। इनमें से 4700 के लगभग गांव सरकार ने समस्या–ग्रस्त घोशित किए हुए हैं। इन 4700 समस्या ग्रस्त गांवों में से करीब 4200 गांवों के आस पास में पेय जल की सुविधा प्रदान की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत अच्छा कीर्तिमान सरकार के लिए है। इसके अलावा सरकार ने बजट में दर्शाया हे कि इस साल तकरीबन 320 गांवों को पेय जब की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। मैंन इस बारे में क्वैश्चंज आसर के दौरान भी एक सवाल पूछा था, लेकिन उस समय मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब कुछ गोल–मोल कर गए थे। अब फिर मैं आपके जरिए उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गांव जहां पर पेय जल का बड़ा भारी संकट है और आगे गर्मियों में बहुत भारी किल्लत उन लोगों को पीने के पानी की हो जायेगी वहां पर एम.आई.टी.सी. के जरिये या किसी और जरिए जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध करवाया जाए ताकि उन लोगों को गर्मियों के दिनों में पानी के संकट का सामाना न करना पड़े। ऐसे स्थानों पर, जहां पर पानी की कमी है, प्रायरिटी बेसिज पर पानी सरकार की उपलब्ध करवाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं वैटरनरी हौस्पिटल के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। पशुधन किसान की खेती के अलावा दूसरी इण्डस्ट्री है जिस प्रकार से किसान को खेती से आमदनी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से पशु भी किसान की आर्थिक हालत में बराकर का भागीदार है। आज हरियाणा हरित क्रान्ति के नाम से जाना जाता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हरियाणा में हरित क्रान्ि के साथ–साथ श्वेत क्रान्ति भी बराबर आ रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की खपत तकरीबन 400 ग्राम के आसपास है। हरियाणावासियों के लिए इतनी मात्रा में दूध मिलना भी अपने आप में एक अच्छी मिसाल है। सरकार पशुधन की देखरेख के लिए और किसानों की मदद के लिए पशुओं के लिए और हौस्पिटल खोलने जा रही है इसकी व्यवस्था सरकार ने बजट में भी की है। इसके लिए मैं मंत्री जी से खासतौर से अनुरोध करूंगा कि जहां पर पशु ज्यादा हैं, उस एरिया में पशु हस्पताल अधिक से अधिक खोले जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ी इलाके में और खादर के इलाके में दूसरे इलाकों की बजाये कम पशु होते हैं। इसलिए मरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे एरियाज में होस्पिटल खोलने के जो नौर्मज रखे हुए हैं, उनको ध्यान में न रखते हुए अधिक से अधिक हौस्पिटल खोले जाएं ताकि वहां के लोग अपने पशुओं को अच्छी प्रकार से रख सकें। इसलिए इस बारे में मेरी सरकार से फिर विनती है कि ऐसे एरियाज में प्राथमिकता के बेसिज पर हौस्पिटल पशुओं के लिए खोलने चाहिएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एजुकेशन के मुत्तालिक कुछ कहना चाहूंगा। सरकार ने ऐजूकेशन के लिए हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोला है। हर अढ़ाई किलोमीटर के फासले पर एक मिडल स्कूल है और हर 4 किलोमीटर के दायरे में एक हाई स्कूल सरकार ने खोला हुआ है। हरियाणा में भी 10+2 प्रणाली शुरू की जा चुकी है। यह एक अच्छी बात है। जब हम पढ़ते थे तो उस समय स्कूल बिरले ही देखने को मिला करते थे। लेकिन अब सरकार ने जगह–जगह पर स्कूल खोल दिये हैं। शिक्षा की तरफ जितना ध्यान सरकार दे रही है वह बहुत अच्छी बात है। सरकार ने फरीदाबाद में एक गर्ल्ज कालेज विंग के तौर पर खोला है। इस समय यह कालेज विंग के तौर पर चल भी रहा है। सरकार ने इस कालेज के बारे में आश्वासन दिया था कि शुरू में तो इसे विंग के तौर पर चलायेंगे और बाद में इसे पूरा खोल देंगे। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस नैक्टस ईयर में उस गर्ल्ज कालेज को जो इस समय विंग के तौर पर चल रहा है, फुलफलैज्जड खोला जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकारी कर्मचारी सरकार के हर काम में बराबर की जिम्मेदारी निभाते हैं। सरकार ने हमेशा अपने सरकारी कर्मचारियों का ख्याल रखा है। हमारी सरकार फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट दूसरे प्रदेशों के मुकाबले सबसे पहले लागू करने जा रही है। इस बारे सरकार ने एक आश्वासन पिछले साल दिया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। सरकार अपने कर्मचारियों

का इस बात का ध्यान रखती है कि वे किसी तकलीफ में न रहें और उन्हें अपने गुजारे के लिए अधिक परेशान न होना पड़े। जो भ्रश्टाचार बढ़ रहा है, फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से उसको भी रोकने में मदद मिलेगी। सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि हर सूबे से पहले यहां पर फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट लागू की जा रही है और सरकार अब उसे लागू करने के लिये इस रिपोर्ट को ऐग्जामिन करना रही है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि कफद लोग आन्दोलन की धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग इलैक्शन की वजह से या किसी वजह से कर्मचारियों के मन में झूठी आशंकाएं पैदा कर रहे हैं। चौ. बंसी लाल जी के बारे में आज की तारीख तक यह माना गया है कि उन्होंने एक बार जो वायदा कर लिया है उसको निभाया है। उसके बाद भी कुछ लोगों के मन में आशंकाएं पैदा होना, मैं समझता हूं, बुरी बात है। हो सकता है कि कुछ पोलिटिकल लोग कर्मचारियों को जाने या अनजाने में बहका रहे हों। जो काम प्रशंसा योग्य हो, उसकी प्रशंसा करनी भी चाहिए। चाहे वह प्रशंसा का काम अपोजीशन भाईयों की तरफ से किया गया हो या सरकार की तरफ से किया गया हो। मैं समझता हूं कि सरकार ने फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने को जो कदम उठाया है वह बहुत बढ़िया है। सरकार इसके लिये बधाई की पत्र है। स्पीकर साहब, अन्त में मैं एक बार फिर इस बजट को सर्वहितकारी बजट करते हुए इसका समर्थन व अनुमोदन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

ठाकुर बहादुर सिंह (दड़बा कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, जो बजट फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हरियाणा के लोगों को सुख का जीवन प्रदान करने के लिये सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी का जिक्र करता हूं। एस.वाई.एल. नहर जो हरियाणा के लिए एक जीवन रेखा है, हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ा साधन है और जिसे बनाने का बहुत बड़ा भार हरियाणा सरकार महसूस करती थी, उस नहर का सारे का सारा खर्चा भारत सरकार ने देना मंजूर करके बहुत बड़ा अहसान हरियाणा के किसानों पर किया है, लोगों पर किया है और हरियाणा सरकार पर किया है। हरियाणा के लोग नहर की बहुत अर्से से प्रतीक्षा कर रहे हैं यहां के सूखे खेत इस इन्तजार में है कि जल्दी पानी आए और वे हरे भेर हों और यहां के भूखे बच्चे इस प्रतीक्षा में हैं कि जब पानी आएगा तो यहां के खेत हरे भरे होंगे तथा वे पूरी खुराक खांएगे। लेकिन बदकिस्मती से आज क्या हो रहा है? एक अनिश्चित सी स्थिति है। हमारी सरकार कई बार स्टेजों पर भी और हाउस में भी यह डिक्लेयर कर चुकी है कि इस साल तक नहर का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यह नहर आज तक नहीं बन पाई। हमारे विरोधी भाई, जिन्हें वास्तव में इस मसले को हल करने में सरकार का साथ देना चाहिए बदकिस्मती की बात है स्टेजों पर जाकर उल्टा प्रचार करते हैं और भोले–भाले लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। सारी कोताही सरकार की बताते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार

ने, हमारे योग्ज नेतृत्व में, जिस तरह केस प्लीड किया, इराडी कमीशन के सामने अपना केस रखा, वह सराहनीय है। बहुत बड़ी रकम हमारे प्रदेश को पंजाब को देनी होती थी। बहुत सी बार सुनने को मिला कि पंजाब सरकार उसका हिसाब–किताब नहीं देती और खुदाई का काम बहुत ही सुस्त रफ्तार से चलता हुआ बताया गया। विरोधी भाइयों ने, जैसा मैंने पहले कहा, इस मसले को कभी सीरियसली नहीं लिया। वे अपने आपको किसानों का हितैशी कहते हैं लेकिन जब भी एस.वाई.एल. कैनाल की बात हाउस में आई तो उन्होंने इसे मजाक में लिया और सरकार को कभी समर्थन नहीं दिया। मेरे एक भाई यहां बता रहे थे कि एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी एस.वाई.एल. कैनाल को जल्दी पूरा करवाने के लिये भारत सरकार से कोशिश कर रहे थे ताकि वे इसे टेक–ओवर कर लें लेकिन दूसरी तरफ विरोधी भाइयों की एक कमेटी ने यह कह दिया कि काम बहुत ही तसल्लीबख्श ढंग से चल रहा है। स्पीकर साहब, यह तो खुशी की बात है कि हमारे इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया है कि इस साल के अन्त तक इस नहर का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि कितने पुल इस पर बनने हैं और कितने दूसरे भारी काम अभी इसके होने हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात की पूरी कोशिश कर रहे कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट इस काम को टेक ओवर कर ले। अगर ऐसा हो जाए तभी यह नहर समय से पूरी होगी और हमारे खेतों को पानी मिलेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, प्रधान मंत्री जी ने जो 403 करोड़ रूपये की राशि हरियाणा के लोगों की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए और हर लाईन में हमें फायदा पहुंचाने के लिए दी है, उससे हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब का भी कुछ दिल खुला और इन्होंने फराखदिली से बजट बनाया जो कि सराहनीय है। इन्होंने बिना टैक्स लगाए हर मद में पैसा जुटाने की चेश्टा की है। स्पीकर साहब, कुदरती आफात से जिन लोगों का नुक्सान हुआ था, उनके लिये प्रधान मंत्री जी ने 17.25 करोड़ रूपया दे कर हमारी बहुत बड़ी सहायता की है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने इस बजट में हर तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए, चाहे वह खेती की है, तालीम की है, पशुपालन की है या वाटर सप्लाई स्कीम आदि की है, सभी कामों के लिए राशि देने का प्रावधान किया है। इसके लिये हम इनके आभारी है और खास करके भारत सरकार के आभारी हैं जिन्होंने यह सहायता दी और जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ और हमें यह नजर आता है कि हमारे अच्छे दिन आऐंगे और हमारी तरक्की के द्वार खुलेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, सातवीं पंचवर्शीय याजेना के लिए 2900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसा नजर आता है कि हमारे जो टारगैटस रखे गए हैं वे लाजमी तौर पर पूरे होंगे। इसी तरह से वर्श 1986–87 के लिए पहले तो 525

करोड़ रूप्ये का प्रोवीजन रखा गया था लेकिन अब 569.62 करोड़ रूपये का कर दिया गया है। इससे भी हमारे हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा काम होंगे। बिजली के उत्पादन के लिए कुछ खर्च का 34 प्रतिशत भाग रखकर इन्होंने हरियाणा में जो बिजली का संकट है, उसको दूर करने में बहुत सहायता दी है। इसी तरह से सिंचाई और बाढ़ की रोकथाम के लिए कुछ खर्च का 20.05 प्रतिशत खेती तथा उससे संबन्धित कामों के लिए 8.2 प्रतिशत, मानव संसाधनों तथा विकास में घनिश्ठ सन्बन्ध मानते हुए सामाजिक सेवाओं के एिल 19.2 प्रतिशत और तालीम के लिए 4.75 प्रतिशत रूपया रखकर हरियाणा को तरक्की की ओर ले जाने के लिए बहुत बड़ा कदम बढ़ाया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, 20 प्वायंट प्रोग्राम के तहत 51075 नए परिवारों को जो आय के सहायक साधन दिए गए हैं उससे हम देखते हैं कि हर गांव में जिस परिवार के पास पहले आय के साधन नहीं थे उसे आय के साधन मिले हैं ओर उसका जीवन सुखी हुआ है। साधन न होने की वजह से वे अपना काम नहीं कर सकते थे लेकिन इस बात का प्रावधान करके सरकार ने बहुत ही अहम काम किया है। इस साल 10.96 करोड़ रूपया इस मद में खर्च होगा और इससे बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, 97 ब्लाकों में बाल विकास योजना लागू करके हमारी आने वाली नस्लों को जो फायदा मिलेगा, जो लाभ होगा, वह भी एक बहुत बड़ा कदम है। इनके लिये 9.65

करोड़ रूपया देने से हरियाणा का कुछ ऐसा नक्शा, ऐसा रूप सामने आएगा जो इस काम में नम्बर 1 पर होगा।

पिछड़े वर्गों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोशणा की है, वह भी बहुत सराहनीय है। पिछड़े वर्ग के लोग ऐसा महसूस करते थे कि हरिजनों का सब कुछ मिलता हैं, दूसरे लोग भी काफी फायदे उठाते हैं लेकिन उनकी तरक्की क लिए कम काम होते हैं। जहां उनकी आबादी 2 परसैन्ट है, उस गांव की पंचायत में जब उन्हें नामजदगी मिल जाएगी तो वह भी अपनी बातें पंचायत के सामने रख सकेंगे और पचांयत के विकास के कार्यों में शामिल हो सकेंगे पहले शामलात जमीन के लिए भी उनके लिऐ कोई रिजर्वेशन नहीं थी लेकिन अब 10 परसैन्ट जमीन उनको देने से उन्हें पूरा लाभ मिलेगा और वे भी काम करके अपना गुजारा कर सकेंगे। पंचायत समिति में भी अगर उनका कोई मैम्बर चुनकर नहीं आता है तो एक सदस्य नामजद कर दिया जाएगा। यह भी उनके लिए बहुत अच्छी रियायत है। इससे भी उनको बहुत लाभ होगा।

12.00 बजे

जिस गांव में पचास घर पिछड़ी जाति के होंगे उस गांव में उनको नम्बरदार बनने का भी मौका दिया गया है। आप जानते हैं कि नम्बरदार पहले तो बहुत ही महत्व होता था लेकिन अब के समय में भी उसकी जरूरत पड़ती है। लोन के कागजों पर

और शिनाख्त करने के लिये उसके दस्तखतों की आवश्यकता होती है।

सरकार ने योजना को जिला स्तर पर अर्थपूर्ण बनाने के लिये डि–सैन्ट्रेलाइज्ड स्कीम आरम्भ की है जिसकी बहुत ही जरूरत थी। कई ऐसी स्कीमें होती थीं जिनके कारण बहुत सी कमियां रह जाती थी लेकिन अब विकेन्द्रीकरण योजना स्कीम से गांवों के लोगों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। इस स्कीम के लिए 5.50 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। इसका 20 परसैन्ट हरिजन चौपालों तथा हरिजन बस्तियों के विकास कार्यो पर खर्च किया जायेगा और 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों के सुधार और विकास कार्यो पर खर्च किया जाएगा। आपको पता ही है कि पहले हरिजनों को बारात ठहराने के लिये भी जगह नहीं थी। अब हरिजनों को बड़ा सहारा मिलेगा। उन्हें गांवों में बैठने की जगह मिलेगी।

चालू साल में 45.2 करोड़ रूपये का घाटा है लेकिन उस घाटे का फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने कारण भी बताया है कि पहले हमारा सालाना प्लान 1986–87 को 525 करोड़ का बनाया गया था लेकिन इस बढ़ा कर 569.62 करोड़ कर दिया गया जिसके कारण यह घाटा हुआ। इस घाटे के बावजूद भी हमारी सरकार ने इस साल कोई टैक्स नहीं लगाया। फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी सूझबूझ के साथ नया टैक्स नहीं लगाया है। आज के दिन हमारे प्रान्त में बिजली की आवश्यकता है। बिजली क लिए

बजट में 195.4 करोड़ रूपया रखा गया है ताकि आइन्दा हमारी बिजली की कमी पूरी हो सके। सामाजिक सेवाओं के लिए सन् 1986–87 में 92.82 करोड़ रूपया रखा गया था लेकिन इस आने वाले साल के लिये 113.23 करोड़ रूपया रखा गया है। यह बहुत ही बड़ी बात की है। किसानों को भी रिलीफ दिया गया है। किसानों के जो एम.आई.टी.सी. खाल पक्के करता था उसका उन पर बोझ था वह 113 करोड़ बनता था उसे भी सरकार ने माफ कर दिया हैं इस पैसे की वसूली के टाईम लोग गांव से भाग जाते थे लेकिन जब कोई रजिस्टरी या किसी अन्य काम के लिए चले जाते थे तो उनसे वसूली कर ली जाती थी। यह बहुत बड़ी रकम नौन–पेमैंट की वजह से इकट्ठी हों गई थी और खासतौर पर उन इलाकों में जहां कहत पड़ जाता था, वे लोग इस पैसे को अदा नहीं कर सकते थे। उन लोगों पर बड़ा भारी वजन था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब किसानों की धड़कन को पहचानते हुए 113 करोड़ रूपया माफ करके उन पर बड़ा भारी एहसान किया है। इससे उनको बड़ी भारी राहत मिली है। इसी प्रकार से मालिया माफ करके भी सरकार ने बहुत बड़ा कदम लिया है। हमारी गांव की भाशा में कहा जाता है कि हाला और पाला शरीर में से ही निकलता है। हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ा भारी रिलीफ देकर उनका हाला खत्म कर दिया है। हरियाणा के किसान उनके बहुत आभारी हैं क्योंकि उन्होंने किसानों का बहुत बड़ा काम किया है। इसके माफ करने से 5.75 लाख लोगों को फायदा हुआ है।

दूसरी बात फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने यह भी की है कि कारों और मोटरों पर सेज्ल टैक्स घटाया है। मोटरों के टैक्स घटाने की बात सुन कर हमें बड़ी खुशी हुई थी लेकिन वह तो दूसरी मोटरों का ही सैल्ज टैक्स घटा। हम चाहते थे कि सरकार किसानों के टयूबवैल्ज की मोटरों का टैक्स भी घटाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आपको पता ही है कि किसान जब टयूबवैल लगाता है कि तो उसे उसका खच्र भी बर्दाश्त करना पड़ता है साथ ही उसे मोटर लगाने के लिये भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है बिजली की फ्लकचुएशन के कारण उनकी मोटरें जो रोज जलती हैं उनका खर्चा भी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। बिजली की गड़बड़ के कारण महीने में लगभग दो दो बार मोटर जल जाती है, फिर उसे बन्धवाना पड़ता है। दूसरे आपको पता ही है कि मोटरों की कीमतें बहुत बढ़ गई है। इसलिये मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि जहां दूसरी मोटरों का सेल्ज टैक्स सरकार ने कम किया है वहां किसानों की मोटरों को भी शामिल कर लिया जाये तो उन्हें काफी रिलीफ मिलेगा। जब कोई मोटर जल जाती है तो उसके बनाने के लिए जो कौपर वायर आती है वह बहुत ही महंगी होती है, उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अगर फाइनैन्स मिनिस्टर साहब किसानों को भी रिलीफ दे सकें तो किसान उनके बहुत आभारी होंगे। जीप वगैरह का सेल्ज टैक्स उन्होंने घटाया है। बड़ी अच्छी बात की है। इसी तरह से सर्टीफाइड बीजों का टैक्स आठ परसैन्ट से घटा कर चार परसैन्ट कर दिया है। इसके साथ साथ गेहूं की चोकर, चना छिलका तथा

अजवायन के बीजों को बिक्री कर से छूट दे दी गई है। इसी प्रकार से रोजमर्रा की जरूरत की चूड़ियों पर भी बिक्री पर माफ कर दिया है। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हं कि जहां गेहूं के चोकर पर बिक्री कर छूट दी है, वहा मवेशियों के लिए जो खल इस्तेमाल होती है उस पर भी छूट मिलनी चाहिए। सरकार जहां डेरी डिवैल्पमैंट की तरफ ध्यान दे रही है, वहां अगर सरकार खल की कीमत में रियायत देगी तो पशु पालन वाले लोगों को काफी फायदा होगा दूसरे दूध में भी बढ़ौतरी होगी। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को फाइनैन्स मिनिस्टर साहब नोट करेंगें और इन पर बिक्री कर कम करने पर विचार करेंगे। (विघ्न) उम्मीद है कि फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने मेरी बात नोट कर ली होगी क्योंकि बिनौलों और सरसों की खल पर बिक्री टैक्स माफ करने से किसानों को काफी फायदा होगा।

जहां तक व्यापारियों का ताल्लुक है, उन्हें काफी बड़ी राहत दी गई है। वे अब अपने द्वारा छपवाए गए निजी बिक्री पर फार्म संख्या 13, 14 और 15 का प्रयोग करके अपनी रिटर्न भर सकेंगे। जहां तक नौकरी पेशा लोगों का सवाल है, उनके लिए सरकार ने चौथे–पे–कमीशन की सिफारिशें मान कर बड़ा भारी कार्य किया है। हरियाणा पहला प्रान्त है जिसने चौथे–पे–कमीशन की सिफारिशों को माना है। इसी तरह से सरकारी कर्मचारियों के जी.पी.एफ. के 9 परसैन्ट से 12 परसैन्ट ब्याज बढ़ा दिया है जिससे उन्हें बड़ा भारी फायदा मिलेगा लेकिन नौकरी पेशा लोगों की एक

बड़ी अजीब बात हैं। जितनी उनको रियायतें दी जा रही हैं व फायदे दिये जा रहे हैं, उसके बाद भी वे पोलिटिकली मोटिवेटिड होकर ऐजीटेशन की धमकियां दे रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर न जायें। उनका बड़ा ही सुखी जीवन है। आज किसान 24 घंटे काम करता है लेकिन नौकरी पेशा लोग आठ घंटे काम करते हैं। उन्हें इतनी भारी सहलियतें मिलने के बाद भी के हड़ताल की बात करते हैं। किसान 24 घंटे काम करता है। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती उसे किसी किस्म का आराम नहीं जिससे वह अपना जीवन ठीक से बिता सके। किसान को 24 घंटे काम करने के बाद ही पेट भरने को अनाज मिलता है लेकिन नौकरी का पेशा आज के दिन बहुत मुनाफाकश है। चाहे कोई तिजारत करने वाला है या नौकरी करने वाला है, उसे घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसानों का काम पैदा करना है उनका दूसरे कामों की तरफ कम ध्यान जाता है। लेकिन हमें एक बात का ख्याल होना चाहिए कि हमारे यहां एक और बैकवर्ड क्लास पैदा हो रही है जिसकी नौकरी की और दौड़ लगी हुई है क्योंकि यह पेशा मुनाफाकश है जिसमें घाटे का सवाल ही नहीं हे। आज की तालीम की वजह से किसानों के बच्चे भी यह कैलकुलेशन सीख गये हैं कि नौरी में फायदा है। किसानों के बच्चे नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं। वे तिजारत की तरफ नहीं जा रहे हैं। नौकरी की तरफ मेन दौड़ हो गई है। आज यह सोचने की बात है कि लोग इस तरफ क्यों जो रहे हैं। नौकारी का पेशा सबसे ज्यादा मुनाफाकश है। आज के दिन किसानों के बच्चे उस ओर दौड़ रहे

हैं। वे मिनिस्टरों और एम.एल.एज. के पीछे दौड़ रहे हैं और इसी तलाश में है कि नौकरी मिले। ऐसा क्यों है? जब इस नौकरी पेशा लोगों को इतनी रियायतें दे दी गयी हैं तो उनको यह एहसास होना चाहिये कि उनके भाई जो गांव में रहते हैं, उनके बीच में और उनमें जो यहां चण्डीगढ़ में या दूसरी जगहों पर रहते हैं, कितना फर्क है?

श्री उपाध्यक्षः ठाकुर साहब, अब आप वाइंड–आप करें। दूसरे मैम्बर साहेबान ने भी बोलना है।

ठाकुर बहादुर सिंहः बहुत अच्छा जी! मैं थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा। सतलुज यमुना लिंक नहर के बनाने के लिये हमारी सरकार ने इस वक्त 49.44 करोड़ रूपया खर्च करने का प्रावधान किया है। इसी तरह से नहरों को पक्का करने के लिये और हमारी जो लिफ्ट स्कीम्ज हैं, जैसे लोहारू लिफ्ट स्कीम है और जवाजर लाल नेहरू कैनाल है, उनके लिये 95 करोड़ रूप्ये का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात की गयी है। हमारी नहरों को आधुनिक बनाने के लिये जो प्रावधान किया गया है, यह बहुत ही अच्छी चीज की गयी है। हमारे सारे के सारे हरियाणा प्रदेश में नहरों का पानी जाने से हम खेती को प्रोफिटेबल बना सकेंगे। यह जो प्रोविजन किया गया है, यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ ही मैं एक दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगा। मैंने पहले भी एक बार इस बारे में दरख्वास्त की थी कि नहरों के ऊपर औटोमैटिक गेज रीडर लगाये जायें। आज एक ऐसे

आदमी को सौंप दिया जाता है जो यह नहीं देखता कि अगर उसने नहर का पानी कम कर दिया तो कितने लोगों को इससे नुक्सान होगा या कितने लोगों को उससे घाटा होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोशिश की जाये कि नहरों पर ओटोमैटिक गेज रीडर लगा दिये जायें। आधुनिक नहरें तो जब बनेगी, तब बनेंगी लेकिन फिलहाल उन पर औटोमैटिक गेज रीडर लगा दिये जायें ताकि किसानों को पानी का फायदा पहुंच सके। इसी तरह से मैं इरीगेशन मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि किसी नहर के मेन शेयर होल्डर्ज के पास उस नहर के हैड का आपरेशन होना चाहिये। शेयर होल्डर्ज के पास अगर उसका आपरेशन होगा तो ठीक रहेगा। मैं आपसे यह भी दरख्वास्त करूंगा कि काजल हैड का आपरेशन सुप्रिन्टैंडिग इंजीनियर सिरसा के पास दे दें। जहां तक खालों की मेनटेनैंस की बात है, इसी हाउस में एक बार बात हुई थी। आई.पी.एम. साहब ने यहां पर डिक्लेयर किया था कि जो नहरें ऐसी हैं, जिनका लैवल ठीक नहीं बना हुआ है, उनको ठीक कर दिया जायेगा। मैंने उनको सिरसा मेजर का मुआइना कराया था। उस नहर में अढ़ाई अढ़ाई फुट ऊंच–नीच है। वह अभी तक भी ठीक नहीं की गयी है। इसी तरह से मेरा सिरसा जिला सारा ही सैंडी एरिया है। वहां पर जो वाटर कोर्सिज पक्के बने हुए हैं, उनका लैवल 7–8 फुट ऊंचा है। उनके नीचे जो रेत लगी हुई है, वह खिसक जाती है। मैटीरियल भी उनमें ठीक नहीं लगा हुआ है जिस वजह से वे टूट जाते हैं। उन खालों की मुरम्मत के लिये भी कुछ पैसा मिलना चाहिये। मैं यह दरख्वास्त

करूंगा कि कुछ जगह जहां पर खालों की जरूरत है, वहां वे मंजूर की जायें और उनको प्लास्टर कराया जाये ताकि उनमें पानी ठीक प्रकार से चल सके। जितना पैसा इसके लिये अभी रखा गया है, उसे तो वह खालों को मेनटेन भी नहीं कर सकते। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि खालों की मुरम्मत के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कृपा करें ताकि खालों द्वारा किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके और उससे किसानों का जीवन स्तर सुधर सके। इसके ऊपर किसानों का जीवन निर्भर करता है। उस इलाके की तरक्की और उस इलाके की बेहतरी के लिये यह बहुत जरूरी चीज है। इस साल 20000 टयूबवैल कुनैक्शन देने का प्रोग्राम भी बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। टयूबवैल कुनैक्शन्ज के लिये बहुत से केसिज जो पैडिंग पड़े हैं, वह क्लीयर होंगे। इसी तरह से जो पैदावार बढ़ाने के बारे में टारगैट फिक्स किये गये हैं, हम यह विश्वास दिलाते हैं कि पैदावार के 81.80 लाख टन के टारगैट जरूर पूरे हो जायेंगे लेकिन किसानों के काम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और मुनाफे वाला बनाना पड़ेगा। किसानों को अपने खेतों के लिये पानी चाहिये। हमारे मुख्यमंत्री जी उनको पानी मुहैय्या करवाने के लिये वचनबद्ध हैं। उसको मंडियां चाहियें। हमारे बजट में अच्छी मंडियां बनाने के लिये प्रोविजन किया गया है। इसी तरह से मैं एक दरख्वास्त करूंगा। मैं पशु पालन मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि पता नहीं इन्होंने सिरसा जिले को कैसे भुला दिया? मेरी कांस्टिचुऐंसी में एक भी अस्पताल इन्होंने नहीं दिया जबकि दूसरी

जगहों पर बनाने का फैसला इन्होंने किया है। मैं पशु पालन मंत्री जी से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जो इन्होंने 30 अस्पताल बनाने की तजवीज रखी है, उसमें मेरी कांस्टिचुऐंसी को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। स्पीकर साहब, मेरे इलाके में पशु धन बहुत ज्यादा है। वहां से सारा दूध मिल्क प्लांट सिरसा को जाता है। उसमें इन्होंने एक भी अस्पताल खोलने के लिये फैसला नहीं किया है। इसलिये मैं इनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वहां पर यह अस्पताल जरूर दें ताकि वहां पर लोगों को सुविधा हो सके। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि आपने घंटी बजा दी है, अब मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता तो यह था कि अभी कुछ और जरूरी बातें कहूं इसलिये आपसे मेरी यह रिक्वैस्ट है कि अगर आप मेरी विनती कबूल कर लें तो थोड़ा सा वक्त और दे दैं।

श्री उपाध्यक्षः जो जरूरी बातें है, वह आप कह लीजिए।

ठाकुर बहादुर सिंहः आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे कुछ बातें और कहने का मौका दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पर भी और हाउस में भी बहुत सी सच्ची बातें कही हैं। उन्होंने हमारे एक्स मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल के बारे में बहुत सी सच्ची बातें कही हैं। चौ. देवी लाल स्टेज पर कुछ कहता है और प्रैस द्वारा कुछ कहता है। वह हमारे इलाके का रहने वाला है। हम उसके अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हाउस में वह एक बार आया और उसने किसानों के हित के लिये एक बहुत बड़ी तजवीज

रखी। वह तजवीज यह थी कि अगर पंजाब में अमन चाहते हैं और पंजाब में कत्लोगारत को बन्द करना चाहे हैं तो प्रकाश सिंह बादल को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाये। इसके कुछ दिन बाद ही प्रकाश सिंह बादल का ब्यान आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। वे यह कहने लगे कि अगर एस.वाई.एल. किसी तरह से बना भी दी गयी तो मैं कार–सेवा लगाकर उस नहर को गिरवा दूंगा। यह उन किसानों के हितैशी नेता की बात है कि वे उनको स्पोर्ट करते हैं जो हमारी जीवन रेखा रूपी नहर एस.वाई.एल. को बनाये जाने के बाद कार सेवा लगाकर तुड़वाने की कोशिश करेगा। एक तरफ तो वह किसानों के हितैशी बनते हैं और दूसरी तरफ उस आदमी को स्पोर्ट करते हैं जो हमारी एस.वाई.एल. को तुड़वाने की बात करता है। दूसरी तरफ हमारे चौ. बंसी लाल जी ने एस.वाई. एल. की कंस्ट्रक्शन की बात कहकर किसानों के अन्दर एक नया ही खून पैदा कर दिया है। एक नया उत्साह पैदा कर दिया है। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैटरमैंट टैक्स माफ किया है। जब तक चौ. देवी लाल मुख्यमंत्री रहे, तब तक अपने अढ़ाई साल के टाईम में उन्होंने कुछ माफ नहीं किया लेकिन आज वे कहते हैं कि हम यह माफ करेंगे और वह माफ करेंगे। जब इनका अपना समय था, तो कुछ माफ नहीं कर सके। हमारी मुख्यमंत्री चौ. बंसी लाल, ने 113 करोड़ रूपया खालों का खर्चा माफ कर दिया है। चौ. देवी लाल का लिखित हुक्त था कि अगर नहर आगे बढ़वायेंगे तो उसका सारे का सारा खर्चा भी हिस्सेदारान अदा करेंगे और नहर आगे बढ़वायेंगे तो उसका सारे का सारा खर्चा भी हिस्सेदार

अदा करेंगे। किसानों के सही हितैशी चौ. देवी लाल ने एक ही कलम से 113 करोड़ रूपया माफ कर दिया है। एक तरफ तो चौ. बंसी लाल किसानों की तरक्की के लिये, किसानों की बहतरी के लिये संघर्श कर रहे हैं, किसानों के लिये सतलुज यमुना लिंक द्वारा रावी–ब्यास का पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपना पूरा हिस्सा लेने के लिये कोशिश करे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे विरोधी भाई किसानों का हितैशी बता कर गांव के किसानों को बहकाने की कोशिश में आज वे लोग बड़े जलसे कर रहे हैं, बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं। हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने बहट में किसानों को बहुत सी रियायतें दी हैं जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है। अब वे क्या कहने लगे हैं? उनकी कहने की तो बहुत सी चीजें हैं। बड़ी अजीब–अजीब बातें वे करते हैं चौ. देवी लाल बात यूं करता है कि भाई तेरे खेत के पास सड़क पर जो कीकर है, अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो आधी वह तेरी और आधी सरकार की। इस किस्म की बातें करके वह लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। वह लोगों को गल्त रास्ते पर लगाने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, वह लोगों के कर्जे माफ करने की बात करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर जगह यह कहा कि अगर कर्जा माफ करने की बात मुख्यमंत्री के हाथ में होती तो मैं सबसे पहले माफ कर देता। डिप्टी स्पीकर साहब, यह हकीकत भी है। बंगाल में और केरल में यह कहा गया कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा लेकिन वहां की सरकारें बहुत दिन से चल रही हैं और वे आज तक भी कर्जा माफ नहीं कर

पाए। चौ. देवी लाल कह रहे हैं कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो सब कर्जे माफ कर दूंगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर कर्जा माफ हो सकता होता तो चौ. बंसी लाल सबसे पहले कर्जा माफ कर देते। डिप्टी स्पीकर साहब, यह हकीकत भी है। बंगाल में और केरल में यह कहा गया कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा लेकिन वहां की सरकारें बहुत दिन से चल रही हैं और वे आज तक भी कर्जा माफ कर नहीं कर पाए। चौ. देवी लाल कह रहे हैं कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो सब कर्जे माफ कर दूंगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर कर्जा माफ हो सकता होता तो चौ. बंसी लाल सबसे पहले कर्जा माफ कर देते। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे भाइयों में यह पूरा यकीन है कि यह लोगों को बहकाने की बात कर रहा है। 1977 में भी चौ. देवी लाल ने बहुत वायदे किए थे लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। लोगों ने जब देवी लाल को वायदों की याद दिलाई तो यह कहता था कि भई सारा खजाना खाली करके चले गए। खजने में कुछ भी नहीं छोड़ा। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने टी.वी. पर चौ. बंसी लाल और दूसरी तरफ चौ. देवी लाल का इंटरव्यू देखा होगा। एक तरफ चौ. देवी लाल और दूसरी तरफ चौ. बंसी लाल। चौ. बंसी लाल के क्या जवाब थे और चौ. देवी लाल के क्या जवाब थे, ये सब डिप्टी स्पीकर साहब आपने सुने थे। अगर उस इन्टरव्यू के टेप हर ग्राम पंचायत में भिजवा दिए जाएं तो किसी भी गांव के आदमी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि किसान का हितैशी कौन है। किसने किसान के लिए बलिदान दिया है। सबको यह

बात पता लग जाएगी। कभी चरण सिंह का जन्म दिन मनाने के लिए मीटिंग रखते हैं क्योंकि उसमें चन्दा इकट्ठा करना है। जब उनसे पूछा जाता है कि चन्दा क्यों इक्ट्ठा किया जा रहा है तो कहा जाता है कि किसान के लिए अखबार निकालेंगे और वह सारा पैसा हल्म हो जाता है। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी ढाबे में चले जाओ, चौ. देवी लाल के लोग यही कहते फिरते हैं कि यह कर देंगे और वह कर देंगे। इस तरह की बात करने वाले लोग सारे इलाकों में घूमते रहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हम कांग्रेस जन अपने विचारों को पूरी तरह बताने में झिझकते हैं। हमको अपनी पालिसीज और अपने विचार लोगों को खुलकर बताने चाहिएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो यह बजट पेश किया गया है इसमें सभी लोगों के मुतालबे पूरे लिए गए हैं ओर लोगों को काफी रियायतें दी गई हैं। मैं किसानों की तरफ से यह दरख्वास्त करूंगा कि उनकी भी छोटी सी मांग है ओर वह यह है कि उनकी खेती को पूरा पानी मिले, उनकी उपज को बेचने के लिये मन्डियों में अच्छी सुविधा दी जाए और कौस्ट आफर प्रोडक्शन घटाई जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं और आप अच्छी तरह से समझते है कि आज किसान जब ट्रैक्टर लेने जाता है तो उसे ट्रैक्टर इतनी ज्यादा कीमत में मिलता है कि किसान में उस ट्रैक्टर की कीमत का ब्याज भी अदा करने की हिम्मत नहीं है। अगर हम खेती की कौस्ट आफ प्रोडक्शन की अलग–अलग चीजों

के आंकड़े इकट्ठे करें तो खेती का काम नुकसानदायक दिखाई देता है। कोई वक्त था जब नौकरी के मुकाबले में खेती को तरजीह दी जाती थी। मुझे भी सलाह दी गई थी कि नौकरी करके क्या करोगे दो एकड़ में कनक की बुवाई कर लो। आज वही खेती है जिसमें कपास होती है, कनक होती है और जीरी भी होती है लेकिन इसके बावजूद किसान का लड़का नौकरी के लिए भाग रहा है। अगर गांव में जाकर देखा जाए तो किसान के लड़के को नौकरी के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता। डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस सरकार ने सब कुछ दे दिया है लेकिन सब कुछ देने के बावजूद खेती के में मार्जिन कम है। कौस्ट आफ प्रोडक्शन को घटाने से ही किसान की समस्या हल हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि आठ बार जमीन की जुताई करने के बाद जमीन बुवाई के लायक बनती है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, बीज डालना पड़ता है और स्प्रे कराना पड़ता है अगर इन सब चीजों का खर्चा जोड़ें तो किसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। इन सब के अलावा किसान को कुदरती मुसीबतें भी झेलनी पड़ती है। इन सब बातों के बावजूद किसान खेती करता है क्योंकि कोई और चारा नहीं है। अगर वे भाग जाएं तो आपको पता ही है कि क्या हश्र होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जो समझदार लोग थे, उन्होंने बिजनैस का काम शुरू कर दिया, जो थोड़े लोग ऐप्रोच वाले थे, उन्होंने अच्छी नौकरी हासिल कर ली और जो बाकी बच गए उन्होंने खेती का काम सम्भाल लिया। इसलिए इन लोगों को वह सुविधा दी जानी चाहिए जिससे कि वे लोग दूसरों

के बराबर का फायदा उठा सकें। आज जरूरत इस बात की है कि कौस्ट आफ प्रोडक्शन कम की जाए जिससे कि किसान अपनी खेती को नौकरी समझे और अपनी खेती में ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे और दूसरे धंधों की तरफ वह न भागे।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे फाइनैंस मिनिस्टर ने कल जो बजट पेश किया था उसमें किसान को काफी सुविधाएं दी हैं और अगर दो तीन सुझाव जो मैंने दिए हैं उनको मान लिया जाए तो अच्छा रहेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम्ज बनवाई हैं और जो गांव बाकी रह गए हैं उनक लिए प्लानिंग चल रही है। लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम को जो बिजली के साथ नत्थी कर दिया है इससे बहुत बड़ी समस्या हो गई है। खासकर हमारी गांव की बहनों को इससे बहुत दिक्कत है। जब तक बिजली का पूरा प्रबन्ध नहीं हो जाता तब तक वाटर सप्लाई स्कीम्ज हमारे खिलाफ रहेगी। मैं समझता हूं कि बजाए इसके कि इससे हमको सिला मिलता यह शिकायत बन गई है। रात के ग्यारह या बारह बजे पानी की टूटी के सामने खड़े होना कितनी दिक्कत वाली बात है। अगर सरकार हर वाटर सप्लाई स्कीम के साथ जनरेटर का प्रावधान कर दे जिससे कि समय पर लोगों को पानी मिल सके तो बहुत अच्छी बात होगी। करोड़ो रूपया वाटर सप्लाई स्कीम्ज पर खर्च किया गया है और फिर भी लोगों में और खासकर औरतों में बहुत झगड़े होते हैं। इसलिए मेरी तजवीज है कि जनरेटर हर

वाटर सप्लाई स्कीम के साथ लगा दिया जाए तो लोगों को बहुत भारी रिलीफ मिलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो तजवीजें मैंने रखी हैं उन पर सरकार गौर करेगी।

चौ. इन्द्र सिंह नैन (बरवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, कल चौ. कटार सिंह जी ने जो इस औगस्अ हाउस में बजट प्रस्तुत किया है, मैं आपकी आज्ञा से उस पर बोलने के लिए खड़ा हूं और इसका समर्थन करता हूं। बजट को पढ़ने और समझने से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, यह निश्कर्श निकाला जा सकता है कि इस बजट में हर वर्ग को सुविधा देने का प्रयत्न किया गया है। इसमें किसान के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए इसको प्रो–किसान बजट भी कहा जा सकता है। इस बजट में हरियाणा स्टेट की जो पीछे प्रोग्रैस हुई है, उस बारे में भी रोशनी डाली गयी है। इसलिये इसको प्रोग्रैसिव बजट भी कहा जा सकता है। सजाम कल्याण के लिए, हर वर्ग का चूंकि सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, इसलिये इसको समाजवादी बजट भी कहा जा सकता है। एक आम आदमी को चूंकी राहत दी गयी है, इसलिये इसकमो कामनमैन बजट भी कहा जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो बजट पेश किया जाता है, उसमें सरकार की पिछली प्लान की प्रोग्रैस बतलायी जाती है और आगामी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दो

सालों से इस देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली है और इस थोड़े से समय से ही उन्होंने भारत को मौडर्न इंडिया बना दिया है। इस थोड़े से समय में इस देश ने काफी तरक्की की है। आर्थिक मामलों में विशेशरूप से इस देश ने तरक्की की है। अभी पिछले 17 दिसम्बर को हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी चौ. बंसी लाल जी के आग्रह पर पलवल में गये थे और उन्होंने वहां पर एक विशाल जनसमूह को सम्बोधित किया था उस समय उन्होंने हरियाणा के लिये 403 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोशणा की थी और इसके साथ–साथ यह भी एलान किया था कि जो एस.वाई.एल. नहर का कार्य है, जोकि हरियाणा की लाईन है, इसका भार, सारा खर्चा केन्द्र सरकार वहन करेगी।

इसके इलावा, डिप्टी स्पीकर साहब, 17 करोड़ 25 लाख रूपया नैचुरल कैलैमिटी के लिये इस बजट में रखा गया है। इनके इलावा और भी बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि पहले चौ. बंसी लाल जी साढ़े सात साल के लगभग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस काल में भी उन्होंने केन्द्र से काफी वित्तीय सहायता इस प्रदेश के लिये ली है और अब भी लेते आ रहे हैं। जब से चौ. बंसी लाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बन कर हरियाणा में आए तब से वे केन्द्र सरकार से हरियाणा के लिये काफी वित्तीय सहायता लाए। हरियाणा एक छोटा प्रान्त है और डिप्टी स्पीकर साहब, कोई भी प्रान्त भारत के अन्दर चाहे कोई अपोजीशन पार्टी

से सम्बन्धित हो, बगैर केन्द्र सरकार की मदद से अपनी पूरी तरक्की नहीं कर सकता। इन सभी बातौं को मददेनजर रखते हुए हरियाणा को केन्द्र सरकार ने हर तरह से मदद दी है और इसी कारण आज हमारा हरियाणा हर लिहाज से तरक्की कर रहा है और खुशहाली के रास्ते पर जा रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी सरदार लछमन सिंह जी बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें यहां हाउस के सामने रखीं। एक बात उन्होंने यह भी कही कि अपोजीशन के भाईयों को ईश्वर सदबुद्धि दे ताकि वे अपनी बात को यहां पर आकर कहें और जिस पब्लिक ने उनको चुनकर यहां पर भेजा है, उनकी बातों को वे यहां पर आकर रखें। पिछली बार मैंने भी बोलते हुए यही कहा था और अपोजीशन के भाईयों को यह सलाह भी दी थी कि उनको यहां हाउस में आकर अपनी बात को अवश्य कहना चाहिये। प्रजातन्त्र में पोजीशन और अपोजीशन दोनों मिलकर डैमोक्रेसी बनती है। अगर कोई सदस्य यहां आकर अपने लोगों की बात न कहे, अपने हल्के की बात न कहे, अपने पक्ष की बात को न कहे, और यहां से गैर हाजिर रहे, तो मैं समझता हूं कि वह अपनी डयूटी से हिचकचाता है, अपनी डियूटी में वह बुरी तरह से फेल हो रहा है।

इससे आगे, डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात और कहना चाहता हूं। अभी सरदार लछमन सिंह जी ने बोलते हुए राजधानी के बारे में भी एक बात कही कि जब भी चण्डीगढ़ से राजधानी

शिफ्ट हो, टैम्पोरेरी तौर पर उसे पंचकूला में शिफ्ट कर दिया जाए लेकिन इस बारे में मैं यही कहूंगा कि हिसार शहर इसके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पहले तो हिसार जिले के सिरसा और भिवानी हिस्से होते थे लेकिन अब वे अलग–अलग डिस्ट्रिक्अ बन गये हैं। फिलहाल मेरा इस बारे में यही कहना है कि जब तक पंजाब का 70 हजार एकड़ का इलाका हरियाणा को न मिल जाए तब तक चण्डीगढ पंजाब को न दिया जाए। जब इलाका मिल जाए तक हिसार के अन्दर राजधानी बनाने का मेरा सही विचार है क्योंकि जब चौ. बंसी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस वक्त हिसार के अन्दर एक जुडीशियल कम्पलैक्स इस विचार से बनाया गया था कि हाई कोर्ट यहां पर बनेगा। एक पांच मंजिला मिनी सैक्रेटेरिएट भी वहां पर बनाया गया है। इस नजरिये से हिसार को राजधानी बनाया जाना उपयुक्त होगा, सही कदम होगा। इसके लिये सरकार को कोई मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। इसके इलावा वहां पर ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक गिरी हाल है। जिस तरह का हमारा यह असैम्बली हाल है, इसी तरह का वह हाल बना हुआ है। वहां पर सिर्फ कुर्सियां ही लगवानी शेश हैं, उसके बाद असैम्बली वहां पर लग सकती है। यह काम वहां पर भी हो सकात है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब देहातों में रहने वाले लोगों को हम मिलते हैं तो उनका भी यही विचार होता है कि राजधानी कहीं दरमियान में बननी चाहिये। वे डरते हैं कि कहीं पंचकूला में राजधारी न बन जाए, वह तो एक तरफ हो जाएगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि मेरे इस

सुझाव पर अवश्य विचार किया जाए और राजधानी के लिये हिसार को ही उपयुक्त समझा जाए और वहां पर राजधानी बनायी जाए। इस तरह के लोगों के विचार, लोगों की भावनाए मैं हाउस के माध्यम से और आपके द्वारा सरकार को पहुंचाना चाहता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने इस बजट को बड़े गौर और अच्छी तरह से पढ़ा है। डिमांड और सप्लाई को मेनटेन करने के लिये ओर प्राइसिज को कंट्रोल करने के लिये इस बजट में हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। इरीगेशन के बारे में बहुत सी बातें कहीं गयीं हैं लेकिन मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। एस. वाई.एल. नहर के बारे में बहुत चर्चा हुई जोकि हरियाणा की लाईफ लाईन है, रूप रेखा हे। हरियाणा प्रान्त कृशि प्रधान प्रदेश है, इसको आप भली भांति जानते हैं। वैसे तो सारा भारत ही कृशि प्रधान है। गांधी जी कहा करते थे कि अगर असली भारत को देखना है तो आप गांवों में देख सकते हैं। किसानों के लिये इस बजट में सबसे ज्यादा सुविधाएं दी गयी हैं लेकिन फिर भी आज देखा जाए तो हमारे प्रदेश में पानी की कमी है। इसमें दो राय नहीं हैं। अगर हमारे हरियाणा को इससे ज्यादा और पानी मुहैया किया जाए तो हरियाणा प्रान्त की पैदावार और बढ़ सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, तरक्की तो हमने बहुत की है। हम सैन्ट्रल पूल में 30 लाख टन के करीब अनाज हर वर्श भेजते हैं और अगर यह नहर जैसा कि एवार्ड में दिया हुआ है कि 15

अगस्त, 1987 तक बनकर तैयार हो जाएगी, बन जाये तो इससे हरियाणा को बड़ा फायदा होगा लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि पंजाब के अन्दर इस समय दूशित वातावरण है, जिसको सारा भारत जानता है और जिनके कारण से यहा नहर का निर्माण नहीं हो रहा है। ठाकुर बहादुर सिंह जी ने भी बोलते हुए काफी बातें कहीं हैं लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो नहर है इसका निर्माण जल्दी ही होना चाहिये। आज क्वैश्चन आवर में सिंचाई मंत्री महोदय ने बताया है कि यह नहर दिसम्बर, 1987 तक बनकर तैयार हो जाएगी लेकिन हमारा विचार है कि जब तक केन्द्र सरकार इस नहर के निर्माण के कार्य को अपने हाथ में नहीं लेती तब तक यह काम दिसम्बर, 1987 तक सम्पूण्र होना असम्भव है। मैं तो, डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा कि इस एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले ताकि इसका निर्माण ठीक समय के अन्दर–अन्दर हो सके जिससे कि हरियाणा कि किसानों को पानी की सुविधा हो सके, किसानों को सिंचाई करने में सहूलियत हो और प्रदेश खूब खुशहाल हो। सिंचाई की बात बड़ी जरूरी है। अभी बहुत सी बातें कही गई हैं। चौ. देवी लाल और विरोधी पार्टी के भाई बहुत नारे लगाते हैं। इन्होंने 1977 से पहले बहुत बातें कहीं थीं कि किसान को ज्यादा भाव देंगे और मजदूर को काम देंगे लेकिन जब उनको मौका मिला तो कुछ भी नहीं कर पाएं पांच साल की बजाए अढ़ाई साल में ही छोड़ कर भाग गए। ये खालों के खर्चे की बात और कर्जों की बात लोगों को कहते हैं

लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पीदे साढ़े सात साल में इस हरियाणा को भारत में दो नम्बर पर ला दिया था और आशा है कि थोड़े दिनों में हरियाणा नम्बर एक पर आ जाएगा। जो खालों का 113 करोड़ रूपया माफ किया गया है, यह तो वह रूपया है जो इस वक्त बकाया है। आगे खाल और भी बनने हैं काम चलता रहेगा, वह पैसा भी माफ होगा। सिंचाई मंत्री जी पीछे हिसार गए थे। इन्होंने जमींदारों को समझा दिय था क्योंकि अपोजीशन वाले गलत फहमी पैदा कर देते हैं। सिंचाई मंत्री जी ने बताया था कि सरकार आगे भी खाल बनाएगी इसलिये केवल 113 करोड़ रूपया ही नहीं माफ किया है बल्कि वहा पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात मालिया की है। सर छोटू राम जी भी किसानों के हितैशी थे लेकिन मालिया वे भी माफ नहीं कर सके थे। किसानों का मालिया चौ. बंसी लाल जी ने माफ किया है। इसके अलावा चौधरी साहब किसानों को और भी बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। चौ. साहब खुद किसान हैं औ, डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसानों की 80 फीसदी आबादी हमारे प्रान्त में रहती है, उसको सबसे ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। ऐग्रीकल्चर सिंचाई के साथ जुड़ी हुई है। अगर सिंचाई होगी तो ऐग्रीकल्चर बढ़िया होगी क्योंकि पानी के बगैर खेती अच्छी नहीं हो सकती। हमारी ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी न बहुत नए–नए बीज ईजाद किए हैं। 1987–88 में इस यूनिवर्सिटी के अन्दर ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरी पाठयक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इससे भी किसानों को बहुत फायदा होगा। हम गांव

के रहने वाले हैं गांवों में आज सुविधांए तो बहुत दी जा रही हैं लेकिन आमदनी के मालले में अभी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। अभी ठाकुर बहादुर सिंह जी भी कह रहे थे कि गांव में किसान की बात सुनी जाती। यह बात तो ठीक है कि गांवों में सरकार ने बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं। डी.आर.डी.ए., आर.एल.ई.जी.पी. और एन.आर.ई.पी. की स्कीमें हैं। सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डज के लिए भी बहुत रूपया रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सी सहायता गांव वालों को इस बजट में दी गई है। अभी नेहरा साहब यहां बैठे थे। मैं उनके महकमें की बात कहना चाहूंगा। महेन्द्र प्रताप सिंह जी भी कह रहे थे कि पशुधन सबसे बड़ा धन है। आदमी अगर बीमार हो जाता है तो उसे बार में या रिक्शा में हस्पताल ले जाया जा सकता है लेकिन पशु अगर बीमार हो जाता है तो उसे हस्पताल में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज एक–एक पशु दस–दसा हजार रूपए का मिलता है। इसलिये इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। मैं वित्त मंत्री महोदय की मार्फत नेहरा साहब को प्रार्थना करूंगा कि जो आप हस्पताल अपग्रेड कर रहे हैं उसमें हसनगढ़ को भी किया जाए। हसनगढ़ में एक एस.एम.सी. चला रहा है। वह मेरा अपना गांव है। मेरी प्रार्थना है कि इस सैन्टर को अपग्रेड किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं कोआप्रेटिव सैक्टर की बात करूंगा। वैसे तो इस सैक्टर में हरियाणा ने काफी तरक्की की है लेकिन महाराश्ट्र के बराबर अभी हम नहीं आ सके हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, दुनिया के जो ऐडवांस्ड कन्ट्रीज हैं, जैसे जापान, वैस्ट जर्मनी ओर यू.एस.ए., इसमें मुझे दो साल पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां हमने देखा कि इन कन्ट्रीज में कोआप्रेटिव मूवमैंट में बहुत तरक्की हुई हैं। हरियाणा में अभी हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए हैं लेकिन दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। हम लोग देहात के रहने वाले हैं और देहाती आदमी हमेशा कोआप्रेशन के सिद्धान्त को मानता है। जैसे हमारे देहातों में निउंदे का रिवाज है यह भी कोआप्रेशन में ही आता है। इसके आलवा और भी बहुत सी बातें हैं। शुरू से ही देहात वाले इस बात को मानते हैं। हमारे कोआप्रेटिव बैंकों द्वारा भी बहुत से कर्जे देने की सुविधा दी गई है। मैं हैफैड का चेयरमैन हूं। हमारी 3–4 ऐजेंसीज है जैसे हैफड, एफ.सी.आई., फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट और वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन। ऐ एजेन्सीज फूड ग्रेन की प्रोक्योरमैंट करती हैं। पिछले साल टोटल उपज का 84 प्रतिशत अकेली हैफैड ने प्रोक्योर किया था। यह एजेंसी किसानों की मित्र है। अगर यह फील्ड में न आती तो किसान को बड़ी दिक्कत आती। किसान को पैसे की जरूरत होती है और इस एजेंसी ने किसान को समय पर पैसा मिल जाता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में कुछ बातें कहूंगा। इसमें आई.टी.आई. और वोकेशनल ऐजुकेशन इंस्टीच्यूटस आते हैं। मेरे हल्के में एक राखी शाहपुर गांव है। वहां पर मैंने दस–जमा दो सिस्टम के तहत एक वोकेशनल सैंटर

खुलवाया है। उसकी बिल्डिंग 20 लाख रूपए की लागत से बनती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमैंट को डायरैक्शन दें कि वह इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी तैयार करवाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं रोडज और ट्रांसपोर्ट की बात कहूंगा। यह बात कहते हुए मुझे खुशी होती है कि हरियाणा की जो ट्रांसपोर्ट है, वह सारे हिन्दुस्तान में प्रथम है। इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सरकार को मुबारिक बाद देता हूं। मैंने क्वैश्चन आवर में भी कहा था कि बरवाला के बस स्टैंड के लिए मैंने एस.टी.सी. और ट्रांसपोर्ट मिनिस्अर को लिख कर दिया है कि उस बस स्टैंड के लिए जमीन अवेलेबल है और पैसा जमा करवाए तीन साल हो चुके हैं। लोग मेरे को बार बार कहते हैं कि इसको जल्द शुरू करवाया जाए। बरवाला एक बहुत बड़ा कस्बा है। सैन्टर ने शेर शाह सूरी मार्ग नेशनल हाई वे न. 1 को फोर लेनिंग बनाने की योजना बनाई है जबकि बरवाला में पहले की फोर लेनिंग बन चुकी है। आप इससे बरवाला की अहमियत को जान सकते हैं। बरवाला में फोन लेनिंग के लिए मैं चौ. अमर सिंह और चौ. फूल चन्द जी को धन्यवाद करता हूं। मेरी रिक्वैस्ट है कि बरवाला के बस स्टैंड का काम जल्दी शुरू करवाया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐजुकेशन के बारे में कुछ बातें कहूंगा। जिस देश की शिक्षा बढ़िया होती हैं देश तरक्की

करता है। शिक्षा किसी देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। हमने आर्थिक मामलों में व सामाजिक मामलों में बहुत तरक्की की है लेकिन ऐजुकेशन में हम उतनी तरक्की नहीं कर पाये हैं जितनी करनी चाहिए थी। सरकार ने अब शिक्ष्द्वा की नयी पद्धति भी लागू की है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि स्कूलों के अन्दर नैतिकता की तरफ भी अगर कुछ ध्यान दिया जाये तो और अच्छी बात होगी। इसके लिए यदि एक सबजैक्ट इन्ट्रोडयूस कर दिया जाये तो और भी अच्छी बात हो सकती है। जब तक किसी इन्सान की नैतिकता अच्छी नहीं होगी तब तक वह देश तरक्की नहीं कर सकता। आज के दिन इंसान में पैसे की होड़ लगी हुई है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। नैतिकता के आधार पर जो तरक्की होती है वह सबसे बड़ी तरक्की होती है। मेरे हल्के के बरवाला कस्बे की आबादी कोई 40 हजार के आसपास होगी। वहां पर 30–40 किलोमीटर के फासले पर कोई कालेज नहीं है। उस इलाके के लोग कालेज में पढ़ने के लिए फतेहाबाद, हिसार, टोहाना या जीन्द आदि स्थानों पर जाते हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) स्पीकर साहब, मैं वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि बरवाला में जल्दी से जल्दी एक बुआएज डिग्री कालेज खोला जाये क्योंकि उस एरिया में आसपास कोई कालेज नहीं है। इस बारे में मेरी मंत्री जी से फिर प्रार्थना है कि वहां पर एक कालेज अवश्य खोला जाये ताकि उस इलाके के लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके।

स्पीकर साहब, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य के बारे में एक कहावत भी है, कि 'पहला सुख निरोगी काया' और दूसरी बात है कि 'sound mind in a sound body' अगर हैल्थ ठीक है तो बाकी सब कुछ ठीक है। इस बारे में बहुत सी बातें मेरे साथियों ने कही हैं। आज सरकार जगह–जगह पर हस्पताल बना रही है। इस बारे में मेरा कल भी एक क्वैश्चन था। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि बरवाला में जल्दी स जल्दी एक हैल्थ सैन्टर बनाया जाये। वित्त मंत्री महोदय ने एक महीना पहले समालखा में एक कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर बनवाया है जबकि मैं काफी दिनों से अपने हल्के की बात यहां पर उठाता आ रहा हूं। इस बारे में दो बार स्कीम भी बनी है लेकिन वह फाइनैंस डिपार्टमैंट ने रिजैक्ट कर दी। अब फिर केस सैक्शन के लिए गया हुआ है। वित्त मंत्री जी उसकी क्लीयरैंस दे दें ताकि बरवाला में यह हैल्थ सैन्टर बनाया जा सके। यदि मंत्री जी शीघ्र ही क्लीयरैंस दे देते हैं तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा।

स्पीकर साहब, अब मैं लेबर एण्ड एम्पलायमैंट के बारे में कहना चाहूंगा। आप भी देहात के रहने वलो हैं। हमारे जैसों के पास दो ही चीजें रह गई हैं। 90 प्रतिशत तो लोग नौकरी के लिए आते हैं और 10 प्रतिशत ट्रांसफर के लिए आते हैं। आज कोई भी यह नहीं कहता है कि हमारे यहां पर सड़कें बना दी जायें या इण्डस्ट्रीज लगा दी जायें। सारे ही देश में अन–एम्पलायमेंट की

बहुत भारी समस्या है। इसको दूर करना मैं समझता हूं आसान काम नहीं है लेकिन प्रयत्न किए जाते हैं और करने चाहिएं। सरकार को इस समस्या को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के दिन लोग बहुत समझदार हो गए हैं। आज लोग फैमिली प्लानिंग अपने आप करवाने लग गए हैं।

स्पीकर साहब, अब मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में कुछ जिकर करूंगा। समाज कल्याण विभाग ने सभी वर्गों के लिए बड़ी अच्छी–अच्छी स्कीमें बनाई हुई हैं। हरिजन कल्याण निगम, बैकवर्ड क्लासिज कल्याणा निगम व इकोनोमिकली वीकर सैक्शंज कल्याण निगम आदि ने भी बहुत सारी सुविधाएं समाज के वर्गों को प्रदान की हैं। अभी पीछे 15 तारीख को पानीपत के अन्दर बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों की एक कांफ्रैंस को मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया था। उस कांफ्रैस में जो आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिए वे भी इस बजट में दर्शाये गए हैं। आज तक जो सुविधाएं बैकवर्ड क्लाजिस के भाइयों को नहीं मिली थीं, उन्हें हमारे मुख्यमंत्री जी ने पानीपत की कांफ्रैंस में दिया है। अब जिन पंचायतों में बैकवर्ड क्लासिज का कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जायेगा वहां पर भी उनका एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार से ब्लाक समिति के अन्दर भी यदि उनका कोई मैम्बर चुन कर नहीं आयेगा तो वहां पर भी एक मैम्बर उनका नियुक्त किया जायेगा। इसके अलावा शामलात देह की जो जमीन है उसके अन्दर भी इन भाइयों को 10 प्रतिशत हिस्सा पट्टे पर दिया

जायेगा। इससे यह जाहिर है, जैसा मैंने पहले कहा है, कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

सरकार ने अपने कर्मचारियों का चाहे वे सर्विस में हैं, या रिटायर हो चुके हैं, ख्याल रखा है और उन्हें बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। इसी प्रकार से व्यापारियों को भी काफी सुविधाएं हमारे सी.एम. साहब ने दी हैं। इन्डस्ट्री वालों को भी और जो ट्रेडर्ज हैं उनको भी इस बजट में बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। स्पीकर साहब, फोर्थ–पे–कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और मैं तो आपके माध्यम से यह कहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। इस रिपोर्ट को सरकार ने इन–प्रिंसिपल तो मान लिया है और इसके लिए एक कमेटी बना दी है। मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट का डिसीजन आते ही रिपोर्ट का लागू किया जाये। मैंने तो अपनी हैफेड के कर्मचारियों को कह दिया है कि जो सरकार की नीति होगी उसी के मुताबिक आपके यहां पर भी रिपोर्ट को लागू किया जायेगा।

स्पीकर साहब, अब मैं खेलों के बारे में कहना चाहूंगा। खेलें भी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। बजट में दिखाया गया है कि हरियाणा के खिलाडियों ने खेलों में बहुत तरक्की की है और अच्छे ईनाम हासिल किए हैं। शिक्षा विभाग अगर संभव हो सके तो स्पोर्टस का एक सबजैक्ट रख ले ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बन सकें। हिसार के अन्दर हिसार ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्टस कालेज है। वह इस दिशा में कुछ प्रगति कर रहे

हैं। अध्यक्ष महोदय, साउथ कोरिया छोटा सा देश है। वह बहुत सारे मैडल जीत कर ले गया जबकि हमारा देश उस देश से क्षेत्रफल व आबादी के हिसाब से कई गुणा बड़ा है। मैं चाहूंगा कि सरकार खेलों की तरफ विशेश ध्यान दे। स्पीकर साहब, अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो बजट चौ. कटार सिंह जी ने रखा है, बहुत बढ़िया बजट है। इसके लिए मैं इन्हें मुबारिकबाद देते हुए हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इसे पास किया जाये।

चौ. साहब सिंह सैनी (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, सदन में जो हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार यहां पर रखना चाहता हूं। इस बजट को पढ़ने से पता लगता है कि यह बहुत गतिशील बजट है। इस बजट में सभी वर्गों को जो राहतें मिलनी चाहिए थे, वे राहतें दी गई हैं। इसे एक जनहित का बजट कहा जाये तो कोई गलती नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकास की जो गति है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। यह हमारी सरकार की नीतियों की वजह से और नेतृत्व के कारण ही संभव हो रहा है। स्पीकर साहब, आपने भी जैसा देखा है और इस बजट में भी आया है कि इस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बाकी देश के मुकाबले में बहुत आगे है। हमारे यहां की पर कैपिटा इनकम 1984–85 में 3259 रूपये थी। यही पर कैपिटा इनकम 1985–86 के दौरान 3969 रूपये हो गई। यह तकरीबन साढ़े बारह प्रतिशत बढ़ी है। यह तभी संभव हो पाया है

जब प्रदेश में सरकार ने अपने हर मैम्बर की आमदनी को बढ़ाया, चाहे वह कृशि का क्षेत्र है, चाहे इण्डस्ट्रीज का क्षेत्र है या कोई और दूसरा क्षेत्र है।

13.00 बजे

स्पीकर साहब, हमारे प्रदेश में कृशि का उत्पादन बहुत बढ़ा है। यह हमारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों की मेहनत और सरकार की कृशि की पैदावार बढ़ाने सम्बन्धी नीतियों की बदौलत हुआ है। हमारा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट समय–समय पर किसानों को सही बीज का उपयोग करने, खाद का उपयोगन करने और खेती की मौड्रन टैकनीक्स उपयोग करने के लिए गाईडैंस देता है। इन सब की वजह से उत्पादन में बढ़ौतरी हुई है और आज हमारा प्रदेश इस स्थिति में है कि हम लगभग 5.4 प्रतिशत अनाज सैन्टर के खाद्यान्न भंडार में देते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब हरियाणा बना था तो हम बारह से खाद्यान्न लेते थे लेकिन आज हम दूसरे प्रदेशों को खाद्यान्न देते हैं और अपनी जरूरत को भी पूरा करते हैं।

स्पीकर साहब, सिंचाई और बिजली का ऐग्रीकल्चर से घनिश्ठ सम्बन्ध है। इस बजट में बिजली उत्पादन के लिए भी काफी प्रावधान किया गया है। सारी योजना का लगभग 34 परसैन्ट रूपया बिजली की पैदावार पर खर्च होगा, जगह–जगह सब–स्टेशन बनाए जाएंगे और यमुनानगर और पानीपत थर्मल

प्लान्अस के दूसरे यूनिटस बनाए जाएंगे। इससे हमारे किसानों को और ज्यादा बिजली उपलब्ध होगी। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हमारा जिला कुरूक्षेत्र लगभग टयूबवैल्ज की सिंचाई पर निर्भर है क्योंकि नहर का पानी हमें नहीं मिलता है। इसलिए विशेशकर हमारे जिले को इन स्कीमों से काफी लाभ होगा। स्पीकर साहब, इसके अलावा भी हमारे जिले की कुछ जरूरतें हैं। आपके हल्के में 220 के.वी. सब–स्टेशन बनना है। उस पर शायद अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से कुरूक्षेत्र में भी 132 के.वी. सब–स्टेश्रान बनाने की प्रपोजल है। उसके लिए 10 एकड़ जमीन भी शायद बिजली विभाग ने हुड्डा से मांगी है लेकिन अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है। इन दो सब–स्टेशन्ज के बनने से हमारे जिले के शाहबाद, रादौर और थानेसर हल्कों को फायदा होगा। स्पीकर साहब, आप यह भी जानते हैं कि हमारे इलाके को पानीपत थर्मल प्लान्ट से बिजली नहीं मिलती है। हमें भाखड़ा की बिजली पर ही निर्भर रहना पड़ता है जिसकी वजह से कई बार बहुत दिक्कत होती है लेकिन इन सब–स्टेशन्ज के बनने से हमें पानीपत थर्मल प्लाट से भी बिजली मिल जाएगी और काफी सुविधा हो जाएगी।

स्पीकर साहब, नहरों के लिए भी इस बजट में काफी पैसा रखा गया है। दो दिनों से यहां चर्चा चल रही है और प्रश्नों के माध्यम से भी इस बारे में पूछा गया है। दादुपुर–नलवी और लाडवा, दोनों नहरें थानेसर सब डिविजन के लिए अहम हैं। एस.

वाई.एल. नहर जैसे प्रदेश के लिए लाईफ लाईन है वैसे ही जिला कुरूक्षेत्र के लिए ये नहरें लाईफ लाईन हैं। सरकार ने इसके लिए बजट में प्रावधान तो किया है लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए, उस तेजी से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ ध्यान देकर के इसे जल्दी से जल्दी बनवाया जाना चाहिए।

स्पीकर साहब, औद्योगिक तौर पर भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है, काफी तरक्की हुई है और जगह–जगह नए कारखाने लग रहे हैं। यदि आप अमृतसर से चलकर देहली तक जाएं तो देखेंगे कि हरेक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर तथा जी.टी. रोड पर जो भी शहर आते हैं, सभी में अच्छी इंडस्ट्री लगी हैं लेकिन शाहबाद और थानेसर के एरिया में इंडस्ट्रीज डिवैल्प नहीं हो पाई हैं। वहां राईस शैलर्ज और कोल्ड स्टोरेज आदि तो हैं लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगी हैं जिनसे लोगों को कारोबार मिले या ऐनसिलियरी यूनिटस लगें जिनसे इलाके को कुद फायदा हो सके। इसके लिए मेरा सुझाव है कि थानेसर तहसील को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिकलेयर किया जाए। आज मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में यह कहा कि केन्द्रीय सरकार को केस भेजा हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा कि उस केस को जल्दी से जल्दी क्लीयर करवाएं ताकि हमारे एरिया के लोगों को लाभ हो सके।

अध्यक्ष महोदय, बजट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी काफी पैसे का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं सरकार को

बधाई देता हूं लेकिन कुरूक्षेत्र जिला एक ऐसा जिला है जहां हैडक्वार्टर पर आई.टी.आई. की अपनी बिल्डिंग नहीं है। वह किराये की बिल्डिंग में है। मुख्य मंत्री जी दो तीन महीनें पहले वहां गए थे, उसका फाउन्डेशन स्टोन भी रखा जा चुका है, 10 एकड़ जमीन उसके लिये ली गई है लेकिन वह बिल्डिंग अभी बन नहीं रही है। मैं आशा करता हूं कि इस बिल्डिंग को जल्दी बना कर वहां सारे के सारे ट्रेडज शुरू किए जाएंगे। इस वक्त वहां केवल 2–3 ट्रेडज हैं जो पापुलर नहीं हैं और बच्चे उन्हें पसन्द नहीं करते हैं। यदि सारे ट्रेडज वहां शुरू कर दिए जाएंगे तो उस एरिया को काफी फायदा होगा। बजट में इसके लिये अढ़ाई करोड़ रूपये का तो प्रावधान किया गया है लेकिन मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसके लिये और प्रावधान करके इस काम को जल्दी करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, पशु विभाग द्वारा पशु चिकित्सा के लिए बजट में प्रावधान कराना महत्वपूर्ण है। आज नेहरा साहब ने एक क्वैश्चन के जवाब में कहा कि वर्श 1987–88 में 30 और हस्पताल खोलेंगे। वर्श 1986–87 में 40 डिसपैन्सरीज और हस्पताल खुले हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि पशुओं को दूर ले जाना मुश्किल होता है इसलिये यदि हम किसानों को, मजदूरों को यह सहूलियत उनके गांव में ही प्रदान कर दें ताकि पशुओं का वहीं ट्रीटमैंट हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरे हल्का में धांधला, सिरसला और भूतमाजरा ऐसी जगहें हैं, जहां बिल्डिग्ज बनी हुई हैं, और अन्य

सारी सुविधाएं गांव वालों ने जुटाई हुई हैं। यदि वहां स्टौकमैन सैन्टर या वैटरिनरी डिसपैन्सरी खोल दी जाए तो बड़ी कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में गांव की सड़कों की मुरम्मत के लिए 5.2 करोड़ रूपया रखा गया है। मूरथल से करनाल वाली सड़क को चार लेन वाली बनाने का भी प्रोग्राम है। इसके लिय मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं क्योंकि यह बहुत ही ही अहम बात है। इस समय जी.टी. रोड पर 30 हजार से ज्यादा वैहिकल्ज प्रतिदिन गुजरती हैं जबकि नौर्म 10 हजार वैहिकल्ज का प्रतिदिन है। इसी वजह से ऐक्सीडैन्टस ज्यादा होते हैं और बहुत जाने जाती हैं। मेरा यह अनुरोध हे कि यह प्रौजैक्ट जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिये।

स्पीकर साहब, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मंत्री जी भी कहते हैं कि नई सड़कें अभी मंजूर नहीं की जाएंगी लेकिन बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो बनती आवश्यक हैं। चूंकि सड़कों से लोगों को फायदा पहुंचा है इसलिए वे इनकी मांग करते हैं। यह बात भी ठीक है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सड़कों और बिजली का खूब काम करके सारे देश में नाम कमाया है लेकिन अब लोग डबल लिंक की मांग करते हैं। मेरे हल्के में भी पांच सात सड़कें ऐसी हैं जिनके बनने से 10–10 किलोमीटर का फासला कम हो जाता है। मैं मंत्री जी को उनके नाम लिख कर दे दूंगा। सरकार की तजवीज भी है कि हरेक स्कूल को और धार्मिक स्थान को सड़क से जोड़ा जाए। इन सड़कों में से कुछ

सड़कें स्कूलों को जाती हैं और बरसात के मौसम में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। मेरी प्रार्थना है कि इन डबल लिंक सड़कों को मंजूर करने की कृपा की जाए। स्पीकर साहब, प्रधानमंत्री जी ने जो 403 करोड़ रूपया हरियाणा को दिया है यह हरियाणा के विकास के लिए बहुत बड़ी मदद है। इस पैसे में से जहां सरकार ने नहरों की रिपेयर के लिए और दूसरी चीजों के लिए प्रावधान किया है वहां नई सड़कों के लिए भी कुछ पैसा रखा होगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि नई सड़कों पर भी पैसा खर्च किया जाये। सदन में परिवजन की भी बात हो रही थी। इस बारे में मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। हमारे प्रदेश की ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है। हमारी बसें बहुत अच्छी स्पीड से चलती हैं और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें। चौ. अमर सिंह जी आज ही हाउस में बता रहे थे कि पांच साल पहले कहीं–कहीं पर बस स्टैन्ड होते थे लेकिन आज कितने ही नए बस स्टैण्ड हरियाणा में बन गये हैं। हमारे ही कुरूक्षेत्र जिले में 8 बस स्टैण्ड बने हुए हैं। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारा थानेसर सिटी का बस स्टैन्ड बहुत पुराना चल रहा है, उसे भी बनाया जाये। उसकी फाउन्डेशन भी सन् 1980 में रखी गई थी लेकिन अभी तक वह नहीं बना है। इस बस स्टैण्ड के लिए जगह भी दी हुई है। पिपली और कुरूक्षेत्र में जो बस स्टैण्ड बन हैं, वे थानेसर शहर से काफी दूर पड़ते हैं जिनके कारण शहर के लोगों का दिक्कत होती है और यूनिवर्सिटी भी दूर पड़ती है। उस बस स्टैण्ड को जल्दी से

जल्दी बनाया जाये। म्यूनिस्पिल कमेटी ने नौ कैनाल जमीन 20 हजार रूपये सालाना पट्टे पर देना मान लिया है। वह केस एस. टी.सी. के पास आया हुआ है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिला था और प्रार्थना की थी कि वहां बस स्टैण्ड तो अब भी चल रहा है लेकिन बिल्डिंग न होने के कारण लोगौं को दिक्कत होती है। इसी प्रकार से सरकार बस क्यू–शैल्टर भी बना रही है। मेरे हल्के में भी तीन चार जगह ऐसी हैं, जहां पर बस क्यू–शैल्टर्ज बनने जरूरी हैं। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है और मैंने ज्वांयट एस. टी.सी. से भी कहा है कि सौंटी, भैनी, धांधला और बड़ौट गांवों में बस क्यू–शैल्टर्ज बनाए जायें। मेरे हल्के में एक शहर के अलावा कही कोई भी बस क्यू–शैल्टरर्ज पिछले साल नहीं बना है इसलिये मेरी प्रार्थना है मंत्री जी इस ओर पूरा ध्यान दें।

इसके बाद मैं ऐजूकेशन की बात करना चाहता हूं। ऐजूकेशन के लिये बजट में पैसे का बहुत अच्छा प्रावधान किया है। आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति बिना ऐजूकेशन के तक्की नहीं कर सकता। इसीलिये हमारी सरकार ऐजुकेशन की ओर पूरा ध्यान दे रही है। हर साल स्कूल अपग्रेड किये जा रहे हैं। प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल बनाये जा रहे हैं जिसके कारण हमारा प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब कोई प्रदेश आगे बढ़ता है तो उसकी मांगे भी बढ़ती हैं। इसलिये मेरी हल्के की भी मांग है कि जो दो–तीन स्कूल अपग्रेड होने से बचे हैं, उन्हें अपग्रेड किया जाये। वैसे तो पिछले साल भी अपग्रेड हुए

हैं लेकिन जो दो तीन रह गये हैं, उन्हें भी अपग्रेड किया जाये। आप जानते हैं कि पहले हमारे बुजुर्ग लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे लेकिन आज के जमाने में लड़कियों को शिक्षा देनी जरूरी है। मेरे हल्के में प्रतापगढ़ गांव हैं, जहां पर मिडल स्कूल है, उसको मिडल से हाई बनाना बड़ा जरूरी है। सरकार के पास केस आया हुआ है। उसके इर्दगिर्द कोई भी हाई स्कूल नहीं है जिसके कारण बच्चों को दूर पढ़ने जाना पड़ता है। इसी तरह से बन गांव है वहां पर भी मिडल स्कूल है। उसके आसपास दो तीन मील के फासले पर कोई हाई स्कूल नहीं है। इसे भी अपग्रेड किया जाये। खैरी में भी हाई स्कूल होना चाहिए क्योंकि वहां पर मिडल स्कूल है। बच्चों को दूर पढ़ने जाना पड़ता है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल करना भी जरूरी है ताकि किसी भी बच्चे को दो तीन किलोमीटर से ज्यादा दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए न जाना पड़े। आज के दिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे दूर जाना पसन्द नहीं करते। इसलिये बच्चों को हम जितनी भी सुविधायें दे पायें, उतना ही अच्छा है।

हैल्थ के बारे में हमारी सरकार बहुत सजग है और सरकार की योजना है कि सातवीं पंचवर्शीय योजना के दौरान हर गांव में सब–सैन्टर खोले जा सकें। जहां पर तीस हजार की आबादी है वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर और चार पांच प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज के ऊपर एक कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर खोला जायेगा। इस प्रकार से सभी नागरिकों को हैल्थ की सुविधायें प्रदान कर दी

जाएंगी और आज भी सरकार कर रही है। लेकिन इस विशय में मेरी एक और मांग है। हमारे यहां कुरूक्षेत्र में लोक नायक जयप्रकाश नारायण हौस्पिटल है। वह सौ बिस्तरों का है परन्तु वहां पर स्टाफ की कमी है। दूसरे जो स्पैशलिस्ट डाक्टर्ज हैं, वे अभी नहीं लगे हैं, डैन्टल सर्जन भी नहीं है, ई.एन.टी. स्पैशलिस्ट भी नहीं हैं। हमारे हस्पताल के 16–17 कमरे स्टोर और डाक्टरों के रैजिडैन्स के लिए इस्तेमाल किये जा रहे हैं जिसके कारण मरीजों को दिक्कत होती है। हौस्पिटल में जमीन खाली पड़ी हुई है इसलिये डाक्टर्ज के लिए रैजिडैन्स बनाये जाने ताकि पेशैन्टस को असुविधा न हो। डाक्टर्ज को शहरों में मकान लेना पड़ता है। अगर डाक्टर्ज को हम वहीं रहने की सुविधा प्रदान कर देंगे तो बहुत लाभ होगा। स्पीकर साहब, जिस भी जिले में हस्पताल है वहां पर नर्सिग कोर्स की भी क्लासिज लगती है। अम्बाला और करनाल में नरर्सिग कोर्स है लेकिन कुरूक्षेत्र में यह प्रबन्ध नहीं है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि बजट में इसका प्रावधान नहीं आया है हालांकि शिक्षा के लिए सरकार ने पैसा रखा हुआ है, इस ओर भी ध्यान दिया जाये। अगर कुरूक्षेत्र में नर्सिग ट्रेनिंग सैन्टर खोल देंगे तो वहां की लड़कियों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से हमारी स्टेट में कुरूक्षेत्र में गवर्नमैंअ आयुर्वेदिक कालेज है जिसे श्री कृश्ण गवर्नमैंट आयुर्वेदिक कालेज के नाम से पुकारा जाता है। उसकी बिल्डिंग की खस्ता हालत है लेकिन उसी में कालेज चल रहा है। 42 एकड़ जमीन कालेज की बिल्डिंग के लिए ली हुई है उसकी फाउन्डेशन भी सन् 1985 में रखी जा चुकी है

लेकिन अभी तक वहां पर बिल्डिंग बननी शुरू नहीं हुई। जमीन बेकार पड़ी है पैसा न होने के कारण काम शुरू नहीं हुआ। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी को भी लिख कर दिया है और फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से भी प्रार्थना है कि इस बारे में कुछ न कुछ पैसा रखा जाये ताकि इस पर काम शुरू हो जाये क्योंकि बच्चों को कालेज का भवन न होने के कारण काफी असुविधा हो रही है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कितने ही सालों से हमारा कालेज चल रहा है लेकिन उसमें आज तक कोई प्रिसिंपल नहीं लगा है। सी.एम.एम.ओ. ही वहां का ऐडमिनिस्ट्रेटर लगता है। बहिन करतार देवी जी ने भी कोशिश की थी लेकिन प्रिंसिपल नहीं लग पाया। छः साल का बच्चों का कोर्स है। प्रिंसिपल के बिना बच्चे क्या पढ़ सकेंगे, यह बड़ी मुश्किल की बता है। वहां पर जो डिमौन्सट्रेटर लगे हुए हैं, उन्हें लैक्चरार का ग्रेड नहीं दिया जाता है। इसलिये सरकार का इस कालेज की तरफ विशेश ध्यान देना चाहिए क्योंकि गवर्नमैंट का एक ही आयुर्वैदिक कालेज है। स्पीकर साहब, लाडवा के अन्दर रूरल डिस्पैन्सरी है। यह चूंकि काफी बड़ा कस्बा है इसलिए एक छोटी सी डिस्पैन्सरी से काम नहीं चलता। मैंने इस बारे में सवाल भी पूछा था। रादौर मे ंतो पी.एच.सी. है लेकिन सढौरा पिपली और रामसन माजरा के बची के इलाके में कोई पी.एच.सी. नहीं है इसलिये मेरील दरखास्त है कि लाडवा में कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर खोला जाये। डेरा गांव की पंचायत ने रैजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि वहां पर कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर

खोला जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पब्लिक हैल्थ की बात भी मैं करना चाहूंगा। सरकार ने इस बजट में पानी की सुविधाओं के लिये भी प्रोविजन किया है। वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि हम सभी समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे हल्के में भी कुछ स्कीमें मंजूर की गयी हैं और आपके हल्के में भी कुछ मंजूर हुई पड़ी हैं। आपको पता ही है कि हमारे कुरूक्षेत्र जिला 1974 में सर्वे हुआ था। वहां उस समय पीने के पानी की कोई प्रोब्लम नहीं थी। नीचे के पानी का लैवल उस समय ठीक थी। पानी निकालने के लिये कोई दिक्कत नहीं आती थी लेकिन अब वाटर लैवल वहां पर इतना नीचे चला गया है कि हरेक गांव में पानी की समस्या खड़ी हो गयी है। नलके कामयाब नहीं हैं। साढ़े सात हौर्स पावर की मोटर 60 फुट नीचे से पानी उठा सकती है। मेरी गुजारिश यह है कि प्रदेश के जितने भी समस्याग्रस्त गांव हैं, उनको तो पीने के लिये पानी देना ही चाहिये लेकिन कुरूक्षेत्र जिले के जितने भी गांव आज समस्याग्रस्त बने गये है, उनको भी पानी मुहैया किया जाये। मेरी प्रार्थना यह है कि मेरे हल्के के इन समस्याग्रस्त गांवों को जोकि लगभग सारे ही बन गये हैं, प्रायरिटी देकर पानी मुहैय्या कराया जाये। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, कुछ वाटर सप्लाई स्कीमें ऐसी भी हैं, जिन द्वारा कुछ हद तक तो पानी दे दिया गया है लेकिन अभी कुछ बाकी रहता है। जैसे किसी स्कीम में 5 गांवों को पानी देना था, उसमें दो गांवों को तो पानी मिल चुका है

लेकिन 3 गांवों को पानी अभी नहीं मिला है। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से प्राथ्रना करूंगा कि इसके लिये अवश्य ही पैसा प्रदान किया जाये ताकि बाकी के गांवों को भी पानी की सुविधा दी जा सके। इसके साथ–साथ शहरों में भी वाटर सप्लाई स्कीमें बनी हुई हैं। शहरों में भी आजकल आबादी बहुत बढ़ रही है और नई–नई कालोनीज बन रही हैं इसलिये हरेंक को कम से कम पानी की सुविधा देना जरूरी है। मेरी कहना यह है कि जहां–जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम देनी जरूरी है, वहां पर यह स्कीम जरूर दी जाये। इसके अतिरिक्त एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मेरे साथियों ने भी इस बारे में काफी चर्चा की हैं यह नहर हम सभी के लिये एक अहम नहर है। सभी चाहते हैं कि एस.वाई.एल. नहर जल्दी से जल्दी बने। इसके लिये हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। इस दिशा में सरकार ने बहुत काम किया है। जिस बखूबी से इस नहर को बनवाने के लिये हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर और पंजाब सरकार पर दबाव डाला है, वह बहुत ही सराहनीय है। पिछले कुछ अर्से से हमारी सरकार ने इराडी कमीशन के सामने भी जो अपना के पानी लेने के लिये प्रस्तुत किया है इसके लिये भी मैं सरकार का मुबारिकबाद देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। साथ ही साथ स्पीकर महोदय, आप देखेंगे कि हमारे जो विरोधी पक्ष्ज्ञ के भाई हैं, उनकी इस बारे में क्या भूमिका रही है। वे अपने आपको हरियाणा के हितों के लिये लड़ाई लड़ रहे कहते हैं लेकिन करते उलट हैं। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है और हमारे

दूसरे सदस्यों ने भी कई बार कहा है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें दो एम.एल.एज. और एक नौन औफिशियल रखा। पता नहीं वह मौके पर गये भी या नहीं गये। उन्होंने आकर यह कह दिया है कि नहर पर जो काम हो रहा है, हम उससे सन्तुश्ट हैं। इससे हमारी सरकार जो कोशिश कर रही थी कि वह नहर जल्दी बने उसके इस प्रयत्न को धक्का लगा और सरकार के प्रयत्नों में रूकावअ आयी। फिर भी हमीर सरकार ने इसके लिये कोशिश की है जो प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों पलवल में आये और उन्होने वाहं पर एनाउन्स किया कि एस.वाई.एल. जल्दी ही बना दी जायेगी और उसका जितनाप भी खर्चा होगा वह सारा का सारा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और जो पैसा इस पर पहले खर्च हो चुका है वह पैसा री–इम्बर्स किया जायेगा तो प्रदेश में खुशी की लहर दौड गई। हमारी सरकार ने जो पैसा पंजाब सरकार को एस.वाई.एल. के लिये दिया है, उसको री–इन्बर्स करवाने के लिये तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से अपने विरोध पक्ष के भाइयों से यह कहूंगा कि वे लोगों को बहकाना छोड़ दें कि वे ही उनका भलाकर सकते हैं। उनका भला करने वाले तो चौ. बंसी लाल जी और हामरी सरकार है। प्रदेश की जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। हमारा सभी का यह फर्ज बनता है कि हम लोगों को उनके बहकावे में न आने दें। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि वह उनके बहकावे में न आये। जो काम हमारी सरकार कह रही है वह जनहित में कर रही है। वे सरकार को पूरा

सहयोग दें ताकि जो असिंचित भूमि है, उसको पानी मिल सके। इस विशया में हमारी सरकार पूरी तरह से जागरूक है। हरियाणा सरकार केन्द्रीय सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है कि वह एस.वाई.एल. की कंस्ट्रक्शन अपने हाथ में ले लें। हमारे सिंचाई मंत्री चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब ने कहा भी है कि हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है कि तीन शिफ्टों में वहां पर काम चले और वह काम शायद शुरू भी हो चुका हे। दिसम्बर, 1987 तक आश्रा है यह नहर पूरी कर दी जायेगी। इसके बनने से हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे मुख्य मंत्री चौ. बंसी लाल जब से दोबारा मुख्यमंत्री बनकर यहां आये हैं, तब से हम यह देख रहे हैं कि वे जनहित में सभी लोगों को सुविधाएं देने में लगे हुए हैं। जितनी भी सुविधाएं वे लोगों को दे सकते हैं, वे देने की कोशिश कर रहे हैं। हरेक वर्ग को वे सुविधाएं दे रहे हैं। कुरूक्षेत्र में व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ। वहा पर व्यापारियों ने कुछ मांगे रखीं और मुख्यमंत्री जी ने अधिकतर मांगे मंजूर की। उनको कई प्रकार की सेल्ज टैक्स और इन्कम टैक्स के मामले में दिक्कतें थीं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उसी समय अनाउन्स करके उनको दूर करने का फैसला कर दिया। पहले उनको अपने कहीं खाते जाकर पेश करने पड़ते थे। उनको कह दिया कि बही खाते पेश करने की जरूरत नहीं है। खुद रिटर्न भरो और टैक्स भरो। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसी प्रकार से छोटे दुकानदारों की भी दिक्कत थी। उनकी शिकायत यह थी कि इंस्पैक्टर उनको तंग करते थे। उनको

कह दिया गया कि आज से आपको इंस्पैक्टर तंग नहीं करेंगे। कोई छापा नहीं मारेगा। उनके लिये भी टैक्स की सहूलियत दी गयी है कि अगर वे अपनी पिछली इन्कम में 15–20 परसैन्ट की इन्क्रीज शो करेंगे तो सरकार उसको सही मान लेगी। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसी प्रकार से व्यापारियों को कई प्रकार के फार्म भरने होते हैं जिनमें उनको कई प्रकार की दिक्कतें आती थीं। अब उनको यह कह दिया गया है कि वह अपना छपा हुआ फार्म भर सकते हैं। (व्यवधान व शोर) ..... हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैकवर्ड क्लासिज के बारे में सारे देश के लोगों के सामने एक मिसाल कायत कर दी है। मेरे दूसरे साथियों ने भी जो बैकवर्ड क्लासिज को रियायतें दी हैं, उनकी चर्चा की है। गांव के बैकवर्ड क्लासिज के लोग जहां पर हैं और उनका नम्बरदार नहीं है, वहां पर नम्बरदार बने। पंचायत में पंच नहीं बनकर आ सकते हैं तो पंच बनें। इसी तरह से ब्लाक समिति में भी उनको रिप्रेजैन्टेशन देना कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही शामलात भूमि में हरिजनों के लिये पट्टे परी लेने के लिए वन–थर्ड रिजर्वेशन थी लेकिन बैकवर्ड क्लासिज के लिये कोई नहीं थी। अब उनके लिये भी 10 परसैन्ट शामलात भूमि की रिवजर्वेशन कर दी गयी है। इससे उनको बड़ा भारी फायदा होगा। इसके साथ ही जैसे हरिजन भाइयों की चौपालें गांवों में बनी हुई हैं, उसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों के लिये भी चौपालें बनेंगी । इससे उनको बड़ा फायदा होगा। यह सारी की सारी देन हमारी सरकार की है। पहले जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने शायद इस दिशा में सोचा भी

नहीं होगा क्योंकि मैं पहले 5 साल से इस सदन में हूं। जितनी रियायतें इस सरकार ने बैकवर्ड भाइयों को दी हैं इससे पहले किसी भी सरकार ने उनको नहीं दी थी। एग्रीकल्चरिस्टस को जितनी रियायतें इस सरकार ने दी हैं, उनका हमारे प्रदे ा की जनता को पता ही है। स्पीकर साहब, 113 करोड़ रूपया खालों का माफ करना कोई आसान बात नहीं है। इससे साढ़े तीन करोड़ रूपया खालों का माफ करना कोई आसान बात नहीं है। इससे साढ़े तीन करोड़ का फायदा जिला कुरूक्षेत्र के किसानों को भी हुआ है। स्पीकर साहब, पहले जब भी किसान रजिस्ट्री करवाने जाता था तो उसको रैडक्रौस की टिकटें लेनी पड़ती थीं। इससे उनको बहुत दिक्कत महसूस होती थी और इस मामले में उनको तंग किया जाता था लेकिन अब चौं बेसी लाल ने यह टिकटें बन्द कर दी हैं। स्पीकर साहब, इसी तरह से मालिया जो टोडरमल के जमाने से चला आ रहा था, उसको भी माफ कर दिया है। .....

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल सुबह साढ़े नौ बजे तक के लिये एडजर्न किया जाता है।

13.30 बजे*

(तत्पश्चात् सदन बुधवार दिनांक 4 मार्च, 1987 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थापित*हुआ।)